# अर्थव्यवस्था की स्थिति*

*वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की परीक्षा व्यापार तनाव में वृद्धि और टैरिफ के दायरे, समय और तीव्रता के बारे में अनिश्चितता की बढ़ती लहर द्वारा की जा रही है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता उत्पन्न करने के साथ-साथ, इसने वैश्विक विकास में मंदी के बारे में आशंकाएँ भी पैदा की हैं। इन चुनौतियों के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन और बेहतर खपत में स्पष्ट रूप से सुदृढ़ता प्रदर्शित करना जारी रखती है। हालाँकि, अशांत बाहरी वातावरण की प्रतिध्वनि निरंतर विदेशी पोर्टफोलियो बहिर्वाह में परिलक्षित हो रही है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की वृहद आर्थिक ताकत खाद्य कीमतों में और सुधार के कारण फरवरी 2025 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति में सात महीने के निचले स्तर 3.6 प्रतिशत तक की गिरावट से मजबूत हुई है।*

## परिचय

2025 में सुदृढ़ता के एक मजबूत नोट पर प्रवेश कर चुकी वैश्विक अर्थव्यवस्था, बढ़ते व्यापार तनाव और टैरिफ के दायरे, समय और तीव्रता के आसपास अनिश्चितता की एक बढ़ी हुई लहर के तूफान में फंस गई है। हालांकि, जो अधिक निश्चित है, वह यह है कि व्यापार युद्ध और बढ़ते टैरिफ का विकास और ईंधन मुद्रास्फीति पर न केवल सीधे तौर पर शामिल देशों में बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक प्रभाव हो सकता है। अनुमान बताते हैं कि पूर्ण टैरिफ युद्ध से अमेरिका में मूल्य स्तर 1.0-1.2 प्रतिशत बढ़ सकता है, 2025 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में 0.6 प्रतिशत अंकों की कमी आ सकती है, तथा दीर्घावधि में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगातार 0.3-0.4 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।[1] कॉन्फ्रेंस बोर्ड के अनुमानों से संकेत मिलता है कि अगले दशक में विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण मंदी आने की संभावना है।[2] ये आकलन प्राप्त आंकड़ों से सही साबित हुए हैं जो अमेरिका की विकास गति में कमजोरी की ओर इशारा करते हैं।

वित्तीय बाज़ार वैश्विक विकास में अपेक्षित मंदी का अनुमान लगा रहे हैं, अमेरिका और अधिकांश गैर-यूरोपीय भौगोलिक क्षेत्रों में बेंचमार्क सूचकांकों में गिरावट देखी जा रही है। 17 मार्च, 2025 तक, अमेरिकी डॉलर ने नवंबर 2024 के मध्य से अपने सभी लाभ खो दिए हैं, जिसका कारण अमेरिकी व्यापार नीति और विकास अनिश्चितताएँ हैं। भू-राजनीतिक तनाव और बदलते वैश्विक शक्ति संबंध जटिलता के स्तर को और बढ़ा रहे हैं। यूरोप में, सुरक्षा प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण सैन्य खर्च में उछाल आ रहा है, विशेष रूप से जर्मनी और उसके पड़ोसी देशों में, जिससे बॉण्ड प्रतिफल में लगभग तीन दशकों में एक सप्ताह में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। उम्मीद है कि राजकोषीय प्रोत्साहन से यूरो क्षेत्र में विकास में बदलाव आएगा, जिससे यूरोपीय इक्विटी में लाभ हुआ, जिससे वे 2025 में अपने अमेरिकी समकक्षों सेकाफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक तनाव बढ़ने के साथ, आने वाले महीने अनिश्चितता में डूबे हुए हैं।

इन चुनौतियों के बीच, वैश्विक वस्तुओं के लिए दृष्टिकोण एक उम्मीद की किरण बना हुआ है। खाद्य और ऊर्जा की आपूर्ति संभावनाओं में सुधार हो रहा है। 2025 के दौरान वैश्विक अनाज उत्पादन 2024 को पार करने का अनुमान है।[4] इस चिंता के कारण कि व्यापार युद्ध आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है और ऊर्जा की मांग कमजोर कर सकता है, तेल की कीमतें (यूके ब्रेंट) जनवरी 2025 के मध्य से (11 मार्च तक) लगभग 15 प्रतिशत

* यह लेख रेखा मिश्र, जी. वी. नथनएल, शाहबाज़ खान, विश्वजीत मोहंती, श्रेया कंसल, बजरंगी लाल गुप्ता, रमेश कुमार गुप्ता, रजनी दहिया, हरेंद्र बेहेरा, गौतम, अमित कुमार, अमृता बसु, आयुषी खंडेलवाल, ऋषभ कुमार, राधिका सिंह, रशिका अरोड़ा, अमन तिवारी, दिव्या कादियान, स्निग्धा योगिन्द्रन, शैलजा भाटिया, शिवम, खुशी सिन्हा, मोनिका, युवराज कश्यप, निखिल प्रकाश कोसे, आशीष खोबरागड़े, सत्यम कुमार और श्रेया गुप्ता ने तैयार किया है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।.

[1] येल यूनिवर्सिटी बजट लैब, https://budgetlab.yale.edu/research/fiscal-economic-and-distributional-effects-20-tariffs-china-and-25-tariffs-canada-and-mexico. पर उपलब्ध है।

[2] विश्व जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 में 3.0 प्रतिशत से घटकर 2027-31 के दौरान औसतन 2.5 प्रतिशत और 2032-37 के दौरान 2.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। कॉन्फ्रेंस बोर्ड, वैश्विक पूर्वानुमान अपडेट, फरवरी 2025।

[3] व्यापक रूप से ट्रैक किए जाने वाले अटलांटा फेड जीडीपीनाउ मॉडल का अनुमान है कि 2025 की पहली तिमाही में अमेरिकी वास्तविक जीडीपी वृद्धि (मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दर) -2.1 प्रतिशत रहेगी (17 मार्च, 2025 अपडेट)।

[4] एफएओ अनाज आपूर्ति और मांग ब्रीफ़, 7 मार्च, 2025।

घटकर 70 अमेरिकी डॉलर से नीचे आ गई। मामूली मांग वृद्धि के माहौल में उत्पादन विस्तार के कारण इन्वेंट्री बढ़ने से 2025-26 तक कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है।[5] हालांकि, स्टील और एल्युमीनियम पर अमेरिका द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने की खबर के बाद फरवरी में धातु की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई । टैरिफ संबंधी चिंताओं और सुरक्षित-पनाहगाह की मांग ने 14 मार्च, 2025 को सोने की कीमतों को 3000 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया।

नीति निर्माता अब एक कठिन स्थिति में हैं, उन्हें टैरिफ और मुद्रा अवमूल्यन के कारण बढ़ती कीमतों के ऊपर की ओर दबाव के साथ-साथ आर्थिक मंदी से मुद्रास्फीति पर नीचे की ओर दबाव को संतुलित करना है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति की अपरिवर्तनशीलता, साथ ही स्थिर कोर और सेवा मुद्रास्फीति, टैरिफ युद्ध द्वारा उत्पन्न संभावित मंदी का मुकाबला करने के लिए एक उपाय के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली मौद्रिक नीति पर एक बाधा के रूप में कार्य कर सकती है। उभरती अर्थव्यवस्थाएँ व्यापार, पूंजी प्रवाह और मुद्रा अवमूल्यन चैनलों के माध्यम से इन विकासों के संक्रामक प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनी हुई हैं। घरेलू वृहद आर्थिक स्थितियों में विचलन केंद्रीय बैंकों के बीच नीतिगत कार्यों में मतभेद में भी परिलक्षित होता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था इस अशांत वैश्विक माहौल में सुदृढ़ता प्रदर्शित करना जारी रखती है, क्योंकि विकास की गति को मजबूत क्षेत्रीय प्रदर्शन और उपभोग प्रवृत्तियों में सुधार का समर्थन प्राप्त है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) में 2024-25 के लिए स्थिर 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नवीनतम तिमाही डेटा इस मजबूती को और अधिक रेखांकित करता है, जिसमें वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 की तीसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो पिछली तिमाही की नरमी को दूर करती है। निजी उपभोग व्यय ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जो मजबूत उपभोक्ता विश्वास और निरंतर मांग का संकेत देता है। हाल के महीनों में सरकारी खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे विकास को और बढ़ावा मिला है। निर्माण, वित्तीय सेवाओं और व्यापार सहित प्रमुख क्षेत्र आर्थिक सुदृढ़ता के स्तंभ के रूप में फलते-फूलते रहे हैं। आर्थिक गतिविधि के विभिन्न उच्च-आवृत्ति संकेतक चौथी तिमाही के दौरान भी विकास में निरंतर गति की ओर इशारा करते हैं। 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के पहले संशोधित अनुमान (एफआरई) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 9.2 प्रतिशत बताई गई है - जो कि एक दशक से अधिक समय में सबसे अधिक है, अगर हम कोविड के बाद की रिकवरी को छोड़ दें - यह दर्शाता है कि अनिश्चित दुनिया में, भारत की विकास कहानी स्थिरता और प्रगति का एक प्रतीक बनी हुई है।

विभिन्न क्षेत्रों में हाल ही में हुए घटनाक्रमों से विकास की गति में क्रमिक वृद्धि के आकलन की पुष्टि होती है। खरीफ सीजन 2024-25 में खाद्यान्न और तिलहन के उत्पादन अनुमानों में वृद्धि देखी गई है और रबी खाद्यान्न में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो मुख्य रूप से जलाशयों के संतोषजनक स्तरों द्वारा समर्थित सामान्य से अधिक वर्षा के कारण है।[6] गति में मामूली गिरावट के बावजूद, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र ने फरवरी 2025 में क्रय गतिविधि और रोजगार में वृद्धि देखी।[7] सेवा क्षेत्र ने नए व्यवसायों और रोजगार में मजबूत विस्तार दर्ज किया।[8]

मजबूत सूक्ष्म-वित्त स्थिति और विवेकपूर्ण नीति पर निर्मित सहज शक्ति के बावजूद, उथल-पुथल भरे बाहरी माहौल का प्रभाव अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। फरवरी में विदेशी पोर्टफोलियो के निरंतर बहिर्वाह ने घरेलू इक्विटी बाजारों पर काफी दबाव डाला और मुद्रा अवमूल्यन को जन्म दिया। जैसा कि खंड IV में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है , हालांकि, घरेलू निवेशकों ने अपनी धारिता में वृद्धि की है, जो एक प्रतिसंतुलनकारी बल के रूप में कार्य करता है, जिससे स्वामित्व पैटर्न में बदलाव होता है।

भारत का वित्तीय परिदृश्य भी घरेलू वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विभिन्न चैनलों के माध्यम

5 अल्पकालिक आर्थिक दृष्टिकोण, अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन, 7 मार्च, 2025।

6 कृषि फसल उत्पादन (खरीफ और रबी): 2024-25 के दूसरे अग्रिम अनुमान।

7 एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फरवरी 2025।

8 एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई, फरवरी 2025।

से प्रकट होने वाले इन बाहरी जोखिमों से निपट रहा है। रिज़र्व बैंक सावधान बना हुआ है, सरकारी कर प्रवाह गतिशीलता, मुद्रा रिसाव और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के बहिर्वाह से उत्पन्न चलनिधि की कमी से तेज़ी से निपट रहा है। रिज़र्व बैंक ने खुले बाजार परिचालन (ओएमओ), दैनिक परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी और डॉलर/रुपया खरीद-बिक्री स्वैप नीलामी सहित हस्तक्षेपों का एक रणनीतिक मिश्रण संचालित किया है। इन सक्रिय उपायों ने बाजार की चलनिधि की स्थिति को स्थिर करने में मदद की है, जिससे अप्रत्याशित वैश्विक वातावरण में वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित हुई है।

फरवरी 2025 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति सात महीने के निचले स्तर 3.6 प्रतिशत पर आ गई, क्योंकि खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से सब्जियों की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई, जो बाजार में सर्दियों की फसलों के आने से प्रेरित थी। हालांकि, कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) मुद्रास्फीति बढ़कर 4.1 प्रतिशत हो गई। समग्र मुद्रास्फीति में गिरावट से खपत में सुधार को और बढ़ावा मिलने और व्यापक आर्थिक मजबूती को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत कवच के रूप में काम करेगी।

इस पृष्ठभूमि में, लेख का शेष भाग चार खंडों में संरचित है। खंड II में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे घटनाक्रमों को शामिल किया गया है। खंड III में घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन किया गया है। खंड IV में भारत की वित्तीय स्थितियों का सार प्रस्तुत किया गया है, जबकि अंतिम खंड में निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

## II. वैश्विक परिदृश्य

लगातार व्यापार और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की परीक्षा ले रही हैं। मार्च 2025 की अपनी वैश्विक आर्थिक आउटलुक अंतरिम रिपोर्ट में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने अपने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान को 20 आधार अंकों (बीपीएस) से घटाकर 2025 के लिए 3.1 प्रतिशत और 2026 के लिए 30 बीपीएस से घटाकर 3.0 प्रतिशत कर दिया (उनके दिसंबर 2024 के अनुमानों से)। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में, अमेरिका को निकट भविष्य में अन्य एई से बेहतर प्रदर्शन करने का अनुमान है और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के वैश्विक विकास के प्रमुख चालक बने रहने की उम्मीद है (चार्ट II.1)। यह पाया गया है कि नीति अनिश्चितता वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के लिए एक प्रमुख जोखिम के रूप में उभरी है (बॉक्स II.1)

**चार्ट II.1: वैश्विक जीडीपी वृद्धि अनुमान**

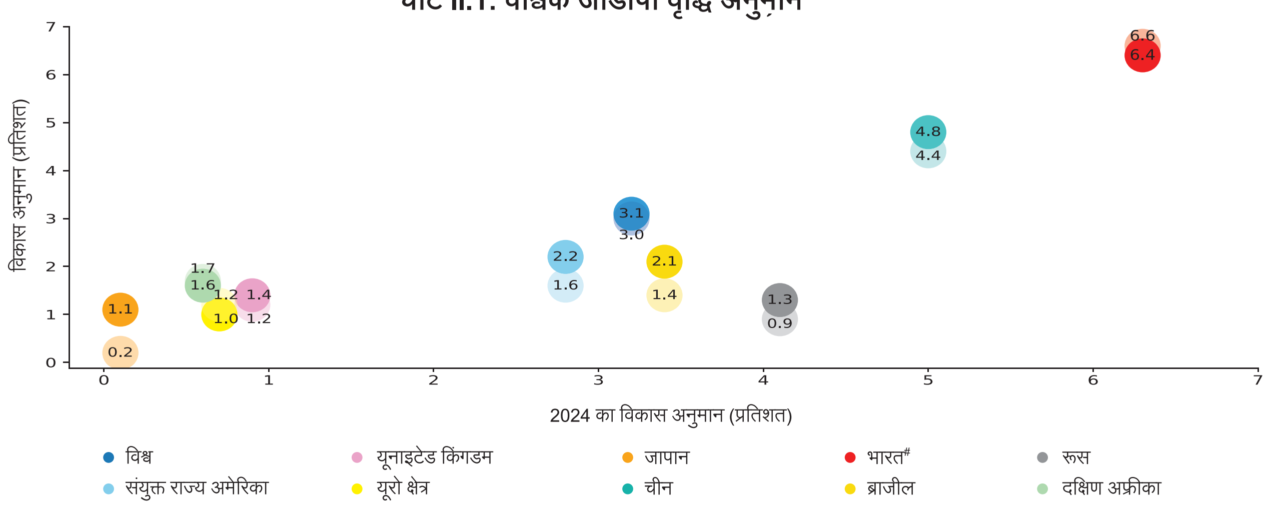


**टिप्पणी:** 1. *: पीपीपी भारित #: भारत का डेटा वित्तीय वर्ष के आधार पर है।
2. गहरे (हल्के) छायांकित वृत्त 2025 (2026) पूर्वानुमानों से संबंधित हैं।

**स्रोत**: ओईसीडी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, मार्च 2025।

### बॉक्स II.1: वैश्विक आर्थिक गतिविधि पर व्यापार नीति अनिश्चितता का प्रभाव

हाल ही में नीति अनिश्चितता, विशेष रूप से भूराजनीति और व्यापार से संबंधित (चार्ट II.बी1ए), का पुनरुत्थान हुआ है। विश्व व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक (टीपीयू)[9] , जो 2016 तक अपेक्षाकृत कम और स्थिर था, ने 2018 में एक महत्वपूर्ण उछाल का अनुभव किया, जो अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ संघर्षों के साथ-साथ अमेरिका द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के लिए टैरिफ छूट समाप्त करने से प्रेरित था, जिसने प्रतिशोधात्मक उपायों को प्रेरित किया। यह बढ़ी हुई अनिश्चितता 2020 के बाद कम हो गई लेकिन 2024 के अंत में फिर से उभरी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के बाद नए व्यापार प्रतिबंधों, टैरिफ वृद्धि और सख्त आव्रजन नीतियों के बारे में चिंताओं से प्रेरित थी (चार्ट II.बी1बी)।

व्यापार नीति में अनिश्चितता बढ़ने का असर प्रमुख आर्थिक चरों पर पड़ता है, जैसा कि वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (वीएआर) ढांचे में टीपीयू में वृद्धि के प्रति उनकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट होता है। टीपीयू में वृद्धि के प्रतिउत्तर में विश्व निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जो वैश्विक व्यापार प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभावों को उजागर करता है (चार्ट II.बी2ए)। ईएमई के लिए, टीपीयू में वृद्धि से औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आती है (चार्ट II.बी 2बी)। यह विशेष रूप से ईएमई के लिए चिंताजनक है जो आर्थिक विकास के इंजन के रूप में निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

पण्य बाजारों में, ऊर्जा मूल्य सूचकांक में टीपीयू में उछाल के प्रतिक्रिया में अस्थायी वृद्धि देखी गई है, जो जोखिम की बढ़ती

**चार्ट II.बी1: वैश्विक नीति अनिश्चितता सूचकांक**

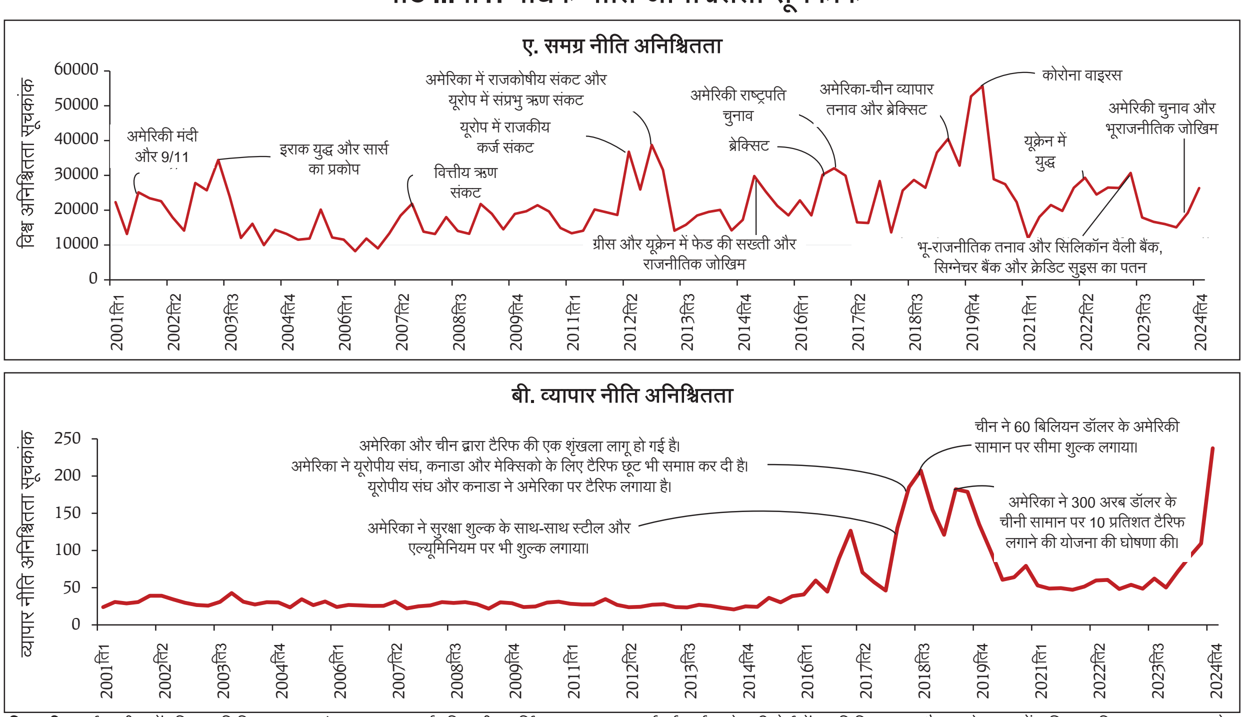


**टिप्पणी**: चार्ट II.बीए में, विश्व अनिश्चितता सूचकांक (डब्ल्यूयूआई) तिमाही आर्थिक आसूचना इकाई (ईआईयू) देश रिपोर्ट में "अनिश्चितता" (और इसके प्रकारों) की आवृत्ति गणना का उपयोग करके दुनिया भर में समग्र अनिश्चितता को मापता है। यह सूचकांक 142 देशों के लिए एक असंतुलित जीडीपी-भारित औसत है।

**स्रोत**: अहीर एवं अन्य (2022): काल्डारा एवं अन्य. (2019); और आरबीआई लेखकों का चित्रण।

*(जारी)*

[9] व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक (टीपीयू) फेडरल रिज़र्व बोर्ड के अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग के कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जाता है और यह व्यापार नीति अनिश्चितता से संबंधित समाचारों पर मीडिया के ध्यान को मापता है। यह सूचकांक व्यापार नीति अनिश्चितता पर चर्चा करने वाले 7 प्रमुख समाचार पत्रों के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखागार के स्वचालित पाठ-खोज परिणामों को दर्शाता है: बोस्टन ग्लोब, शिकागो ट्रिब्यून, गार्जियन, लॉस एंजिल्स टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और वाशिंगटन पोस्ट (प्रोक्वेस्ट हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर्स और प्रोक्वेस्ट न्यूज़स्ट्रीम के माध्यम से एक्सेस किया गया)। सूचकांक को इस प्रकार स्केल किया गया है कि 100 दर्शाता है कि 1 प्रतिशत समाचार लेखों में टीपीयू का संदर्भ है।

**चार्ट II.बी2: टीपीयू में एक मानक विचलन आघात के लिए वीएआर आवेग प्रतिक्रियाएं**

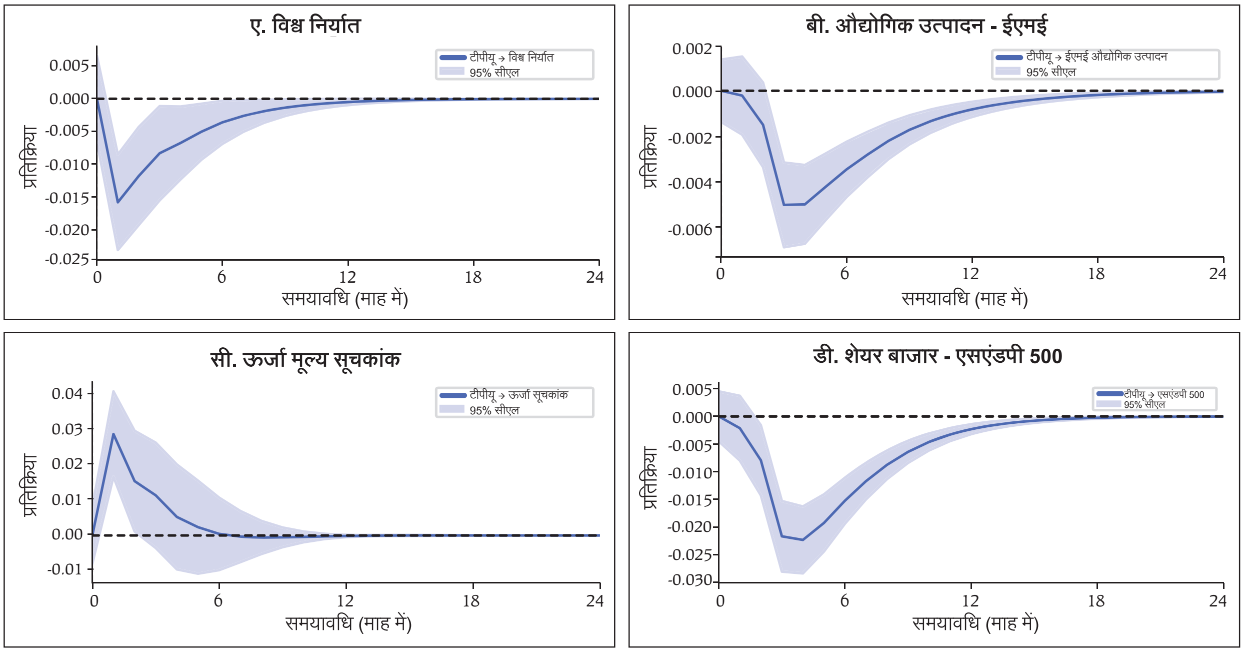


**टिप्पणियाँ**: 1. विश्लेषण के लिए जनवरी 2000 से दिसंबर 2024 तक के मासिक डेटा का उपयोग किया गया।
2. डेटा को लॉग ट्रांसफ़ॉर्म किया गया और एचपी फ़िल्टर का उपयोग करके डीट्रेंड किया गया। टीपीयू में एक मानक विचलन वृद्धि के साथ एक सामान्यीकृत वीएआर मॉडल का उपयोग किया गया, जिसका उपयोग अकाइक सूचना मानदंड (एआईसी) द्वारा निर्धारित इष्टतम अंतराल के साथ किया गया।
3. छायांकित क्षेत्र 95 प्रतिशत विश्वास अंतराल (सीआई) का प्रतिनिधित्व करते हैं।

**स्रोत**: कैलडारा एवं अन्य. (2019); विश्व बैंक; सीईआईसी; एसएंडपी ग्लोबल; विश्व बैंक पिंक शीट; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

धारणाओं और संभावित आपूर्ति व्यवधानों को दर्शाता है (चार्ट II.बी2सी)। इसी तरह, इक्विटी बाजार, जैसा कि अमेरिका के लिए एसएंडपी 500 सूचकांक द्वारा मापा जाता है, बढ़ते टीपीयू पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करता है, जो निवेशकों के विश्वास में गिरावट का संकेत देता है (चार्ट II.बी2डी)। ये प्रतिक्रियाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर टीपीयू के व्यापक और परस्पर प्रभाव को रेखांकित करती हैं।

**संदर्भ**

Ahir, H., Bloom, N., and Furceri, D. (2022). World Uncertainty Index. *NBER Working Paper.*

Caldara, D., Iacoviello, M., Molligo, P., Prestipino, A., and Raffo, A. (2019). Does Trade Policy Uncertainty affect Global Economic Activity? *FEDS Notes.* Washington, DC: Board of Governors of the Federal Reserve System. https://doi.org/10.17016/2380-7172.2445.

वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के हमारे मॉडल-आधारित पूर्वानुमान से पता चलता है कि 2025 की पहली तिमाही में वैश्विक विकास की गति में महत्वपूर्ण गिरावट आएगी (चार्ट II.2)।

वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबावों में फरवरी में वृद्धि दर्ज की गई, जो ऐतिहासिक औसत स्तरों की ओर बढ़ रहा है (चार्ट II.3ए)। मध्य पूर्व में नाजुक युद्धविराम के बावजूद बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद और उबलते राजनीतिक तनाव के कारण फरवरी 2025 में भू-राजनीतिक जोखिम संकेतक बढ़ गया (चार्ट II.3बी)। वैश्विक शिपिंग लागत के संकेतकों ने मिश्रित संकेत दिखाए क्योंकि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स फरवरी में तीन महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसने एशिया में चंद्र नववर्ष अवधि के दौरान देखी गई गिरावट को पलट दिया (चार्ट II.3सी)। इस बीच, ड्र्यूरी वर्ल्ड कंटेनर इंडेक्स में शिपिंग क्षमता में वृद्धि के कारण गिरावट जारी रही (चार्ट II.3डी)।

फरवरी 2025 में, यू.एस., जापान और ब्राजील में उपभोक्ता भावनाएँ प्रतिकूल हो गईं, जबकि यूरो क्षेत्र और यू.के. में मामूली सुधार हुआ (चार्ट II.4ए और II.4बी)। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थितियाँ आसान हुईं, लेकिन उभरती

**चार्ट II.2: वैश्विक जीडीपी वृद्धि का तात्कालिक अनुमान (तिमाही-दर-तिमाही)**

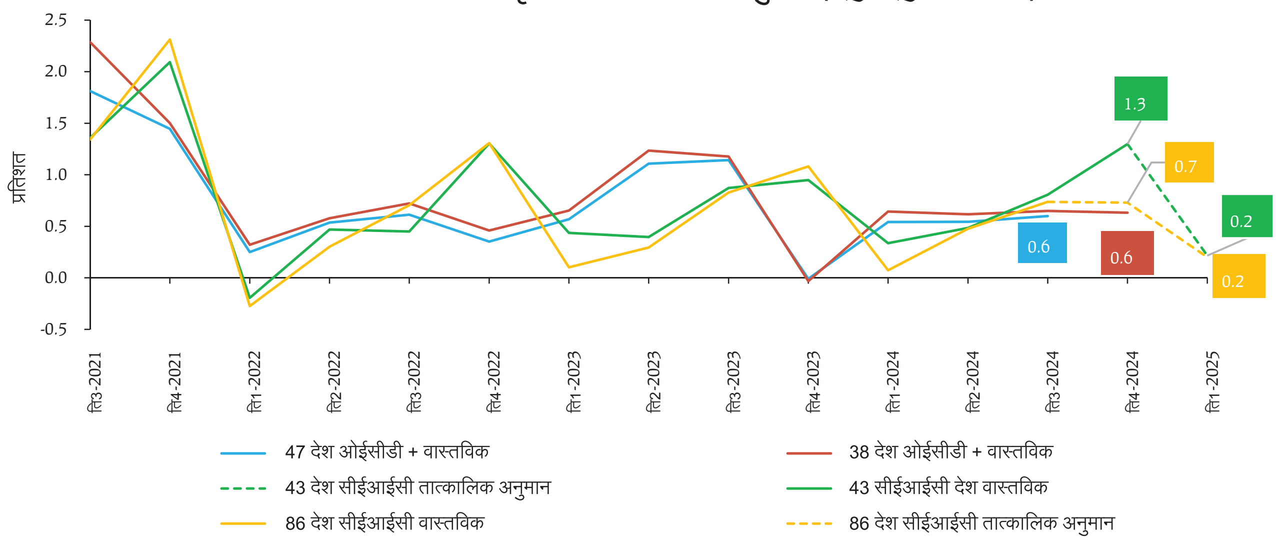


**स्रोत**: सीईआईसी; ओईसीडी; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अर्थव्यवस्थाओं में, चीन और ब्राजील में वे सख़्त हो गईं (चार्ट II.4सी और 4डी)।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) फरवरी 2025 में 14 महीने के निचले स्तर पर आ गया, क्योंकि विनिर्माण

**चार्ट II.3: वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव और भू-राजनीतिक जोखिमों में रुझान**

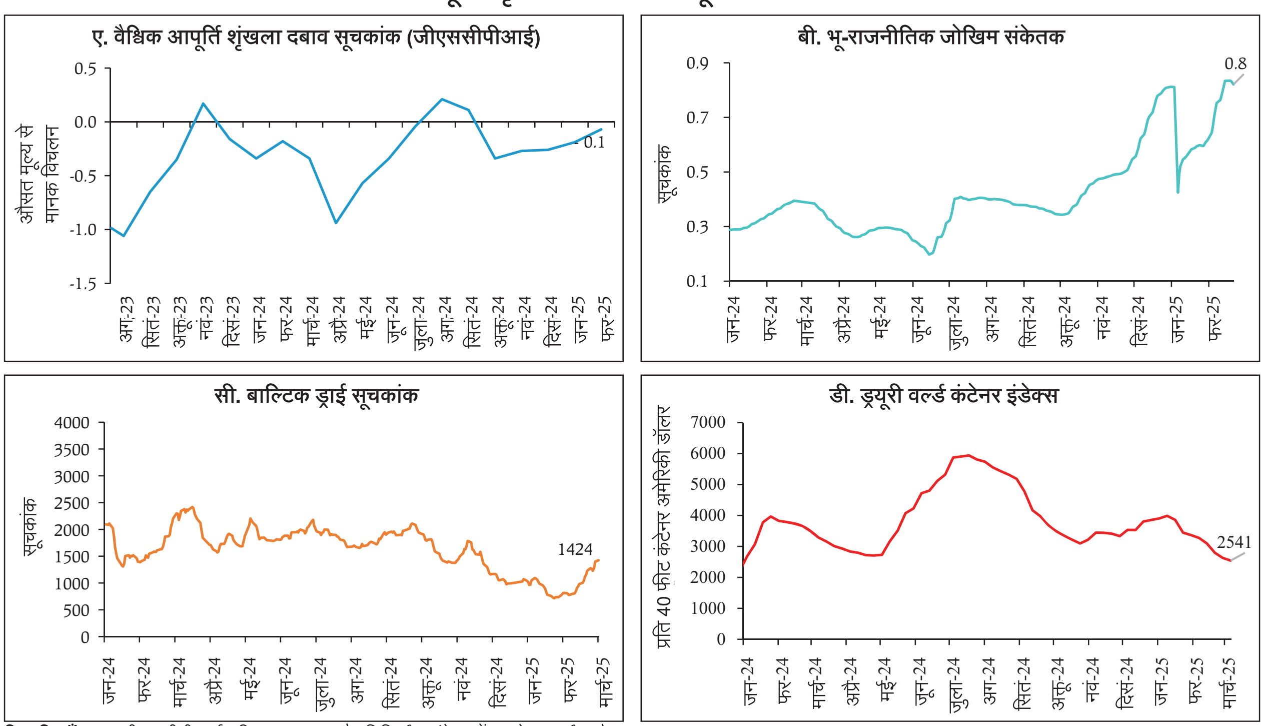


**टिप्पणियाँ**:
1. जीएससीपीआई परिवहन लागत और विनिर्माण संकेतकों पर डेटा दर्शाता है।
2. बाल्टिक ड्राई सूचकांक समुद्र के रास्ते प्रमुख कच्चे माल की ढुलाई की कीमत के लिए एक बेंचमार्क प्रदान करता है और इसमें तीन उप-सूचकांक शामिल हैं जो ड्राई बल्क कैरियर के विभिन्न आकारों को मापते हैं।
3. ड्रयूरी का साप्ताहिक डब्ल्यूसीआई मूल्यांकन प्रमुख पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गों के लिए वास्तविक स्पॉट कंटेनर माल ढुलाई दरों की रिपोर्ट करता है। समग्र सूचकांक मात्रा के हिसाब से आठ शिपिंग मार्गों के भारित औसत का प्रतिनिधित्व करता है और इसे प्रति 40-फुट कंटेनर में यूएसडी में रिपोर्ट किया जाता है।

**स्रोत**: फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क; ब्लैकरॉक इनवेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, फरवरी 2025; और ब्लूमबर्ग।

**चार्ट II.4: उपभोक्ता भावना और वित्तीय स्थितियाँ**

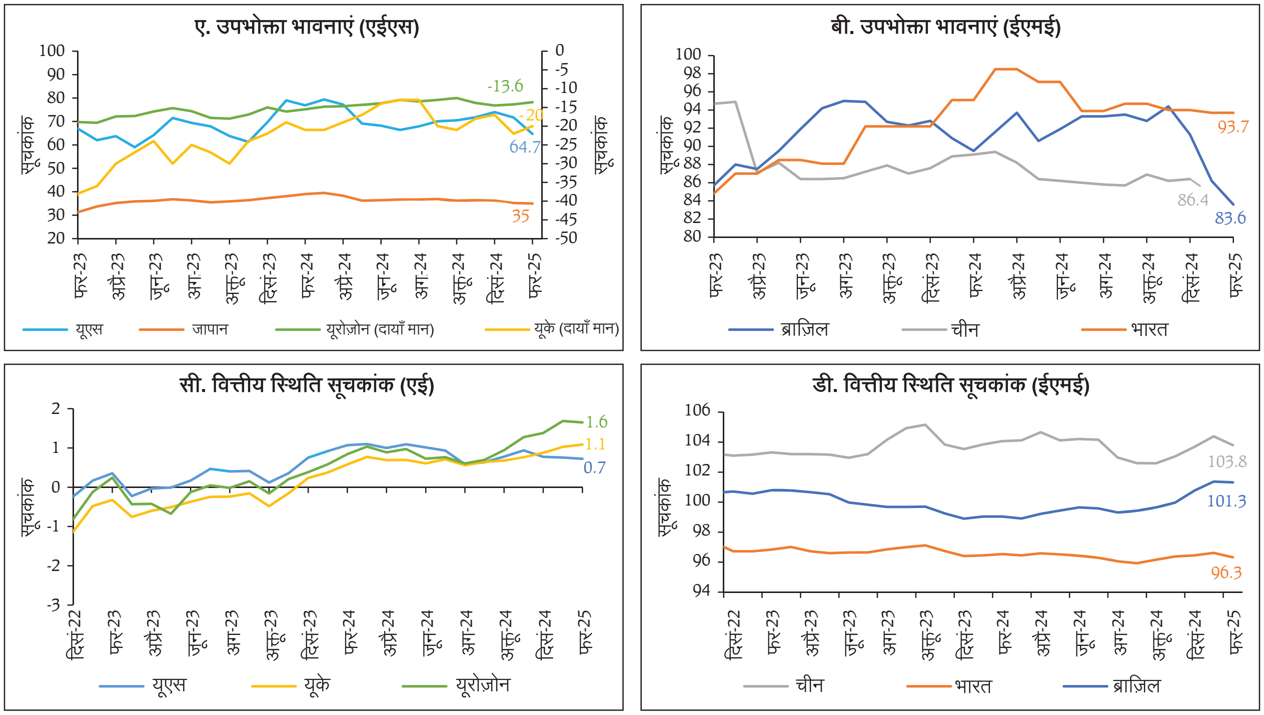


**टिप्पणियाँ**: 1. जापान: 50 से ऊपर का स्कोर उपभोक्ता आशावाद को दर्शाता है, 50 से नीचे का स्कोर उपभोक्ता विश्वास की कमी को दर्शाता है, और 50 तटस्थता को दर्शाता है।
2. यूरोज़ोन और यूके: -100 अत्यधिक अविश्वास को दर्शाता है, 0 तटस्थता को दर्शाता है, और 100 अत्यधिक आत्मविश्वास को दर्शाता है।
3. भारत और अमेरिका: सूचकांक मूल्य जितना अधिक होगा, उपभोक्ता विश्वास उतना ही अधिक होगा।
4. वित्तीय स्थिति सूचकांक (गोल्डमैन सैक्स द्वारा निर्मित ईएमई से संबंधित) के लिए, 100 से नीचे का मान समायोजनात्मक है और इसके विपरीत। एई के लिए, ब्लूमबर्ग द्वारा निर्मित सूचकांक एक जेड-स्कोर है जहां एक सकारात्मक मूल्य समायोजनात्मक/आसान वित्तीय स्थितियों को इंगित करता है और इसके विपरीत।

**स्रोत**: ब्लूमबर्ग।

क्षेत्र में तेजी की भरपाई सेवा क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधि में मंदी से हुई (चार्ट II.5ए)। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई ने उत्पादन और नए ऑर्डर की वृद्धि के रूप में गति पकड़ी, जबकि नए ऑर्डर की धीमी वृद्धि और व्यापार आशावाद में कमी के कारण वैश्विक

**चार्ट II.5: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)**

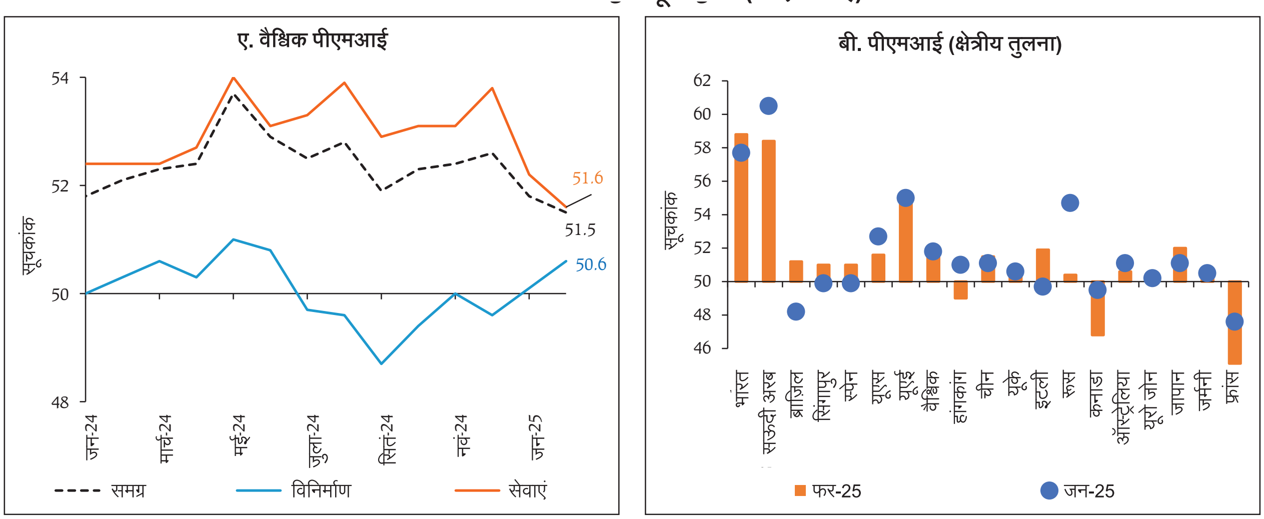


**टिप्पणी**: 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने को दर्शाता है, तथा 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।

**स्रोत**: एस एंड पी ग्लोबल।

सेवा पीएमआई में मंदी आई। सभी क्षेत्रों में, भारत ने अन्य प्रमुख उभरते बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि यूरोप में विकास कमजोर रहा और कनाडा में मंदी तेज हुई (चार्ट II.5बी)।

नए निर्यात ऑर्डर के लिए समग्र पीएमआई ने क्रमिक वृद्धि दर्ज की, हालांकि यह ऋणात्मक क्षेत्र में रहा, क्योंकि विनिर्माण निर्यात ऑर्डर में संकुचन की दर कम हो गई। क्रमिक मंदी के बावजूद सेवा निर्यात ऑर्डर में विस्तार जारी रहा। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, जापान, भारत और चीन ने निर्यात ऑर्डर में विस्तार दर्ज किया, जबकि अमेरिका और यूके में संकुचन देखा गया (चार्ट II.6ए और II.6बी)। जनवरी के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का माल व्यापार बैरोमीटर सूचकांक 102.8 पर है, जो संभावित व्यापार नीति परिवर्तनों की प्रत्याशा में त्वरित आयात द्वारा संचालित प्रवृत्ति से ऊपर के व्यापारिक व्यापार विकास को इंगित करता है।

ब्लूमबर्ग पण्य सूचकांक के संकेत के अनुसार, फरवरी में वैश्विक पण्य की कीमतें अस्थिर रहीं, जिसमें महीने-दर-महीने (माह-दर-माह) आधार पर 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट II.7ए)। एफएओ के खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य कीमतों में फरवरी 2025 में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से चीनी, डेयरी और वनस्पति तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई, जो मांस की कीमतों में कमी से आंशिक रूप से ऑफसेट हो गई (चार्ट II.7बी)। अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि और टैरिफ अनिश्चितता के कारण वैश्विक विकास की चिंताएं बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में 4.6 प्रतिशत (माह-दर-माह) की गिरावट आई (चार्ट II.7सी)। ओपेक प्लस द्वारा अप्रैल में अपने उत्पादन में वृद्धि के साथ आगे बढ़ने के निर्णय के बाद मार्च में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी रही। फरवरी और मार्च की शुरुआत में बेस मेटल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिसे चीन में अतिरिक्त प्रोत्साहन की उम्मीदों और अमेरिकी डॉलर के कमज़ोर होने से बल मिला। फरवरी में सोने की कीमतों में भी उछाल आया (चार्ट II.7डी), जिसे सुरक्षित निवेश की मांग और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी से बल मिला।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के अवस्फीति के अंतिम पड़ाव में हेडलाइन मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है। अमेरिका में, सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी के 3.0 प्रतिशत से फरवरी में कम होकर 2.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई। यूरो क्षेत्र में हेडलाइन मुद्रास्फीति जनवरी के 2.5 प्रतिशत से फरवरी में कम होकर 2.4 प्रतिशत हो गई। जापान में मुद्रास्फीति (ताजे भोजन को छोड़कर सीपीआई)

**चार्ट II.6: वैश्विक पीएमआई: नए निर्यात ऑर्डर**

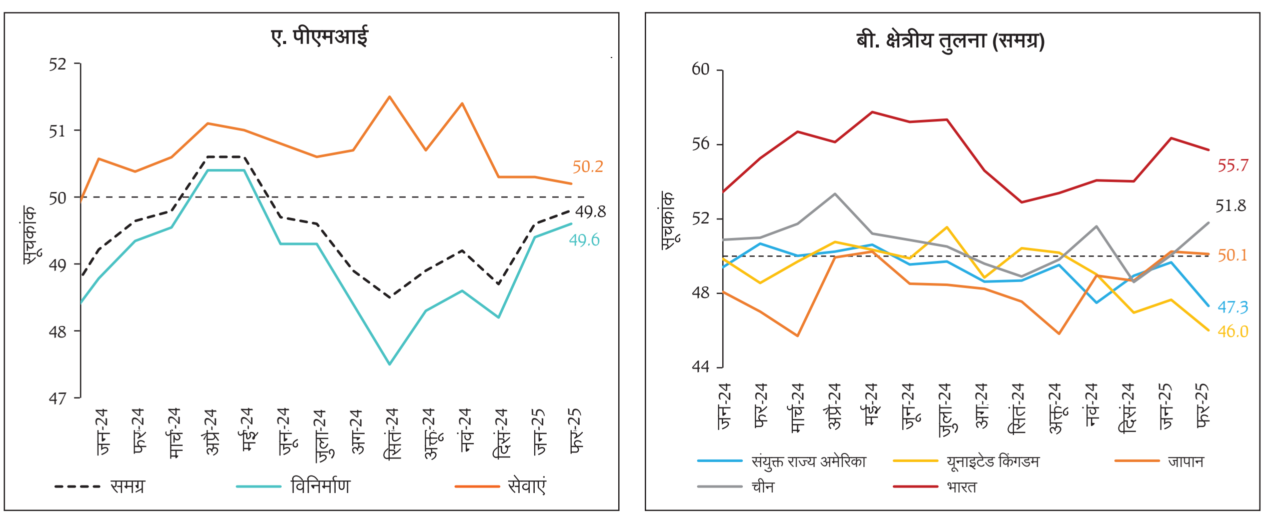


**टिप्पणी**: 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता है, तथा 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत
**स्रोत**: एस एंड पी ग्लोबल।

**चार्ट II.7: पण्य और खाद्य कीमतें**

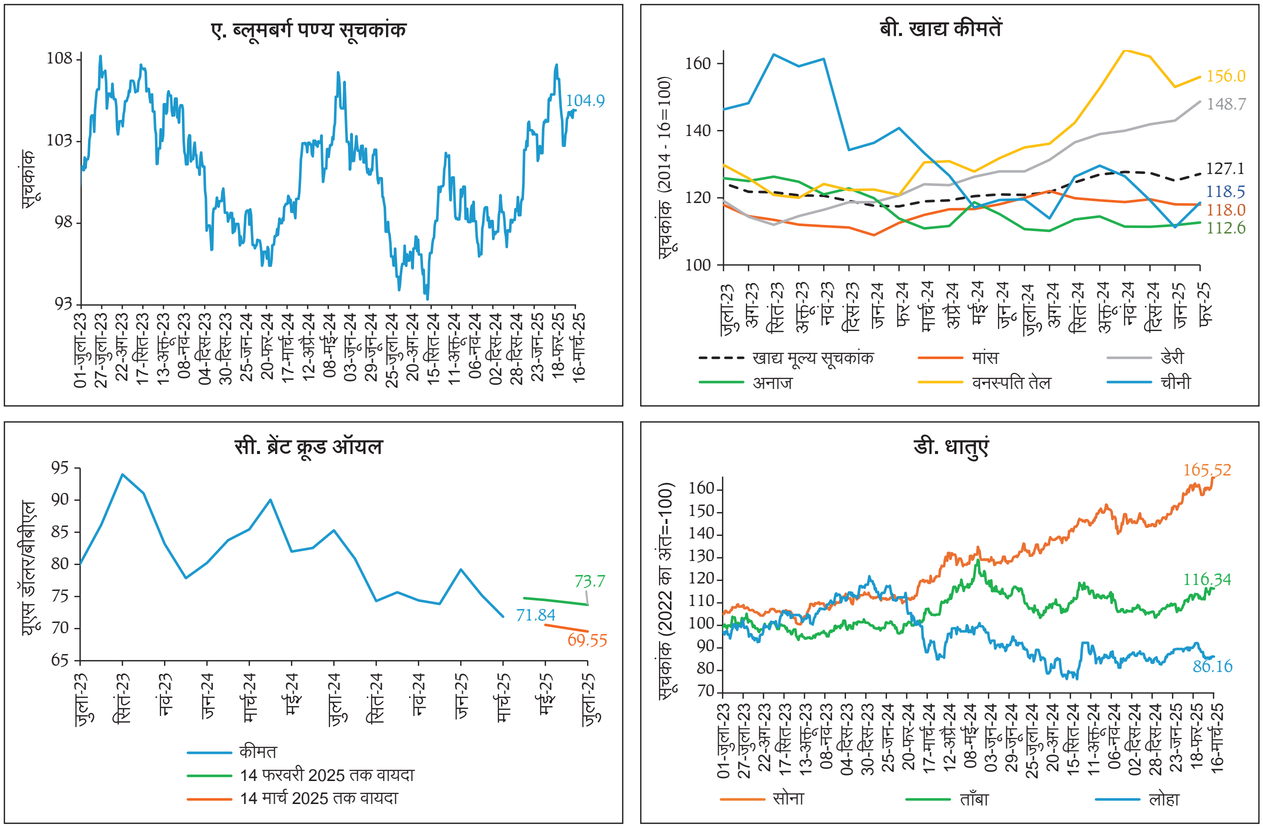


**स्रोत:** ब्लूमबर्ग वर्ल्ड बैंक पिंक शीट; और एफएओ।

जनवरी में बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गई, जबकि यूके में इसमें 50 आधार अंकों की वृद्धि हुई (चार्ट II.8ए)। ईएमई में, चीन में सीपीआई मुद्रास्फीति फरवरी में (-)0.7 प्रतिशत पर अपस्फीति क्षेत्र में लौट आई, जो कमजोर घरेलू मांग के कारण एक वर्ष से अधिक समय में इसका निम्नतम स्तर है (चार्ट II.8बी)। फरवरी में रूस और ब्राजील में और जनवरी में दक्षिण अफ्रीका में सीपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की गई। अधिकांश एई में कोर और सेवाओं की मुद्रास्फीति हेडलाइन से ऊपर बनी हुई है (चार्ट II.8सी और II.8डी)।

मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) विश्व इक्विटी सूचकांक फरवरी में 0.7 प्रतिशत (माह-दर-माह) गिर गया क्योंकि एई में नुकसान ईएमई में लाभ से अधिक था। सूचकांक फरवरी के पहले भाग में बढ़ा, जिसे अमेरिका में मजबूत तिमाही कॉरपोरेट आय का समर्थन मिला, लेकिन इसके बाद गिरावट आई और अब तक मार्च (14 तारीख तक) में गिरावट जारी रही क्योंकि उम्मीद से कमजोर आर्थिक डेटा[10] जारी होने और व्यापार नीतियों के बारे में अनिश्चितता बढ़ने से आशावाद कम हुआ (चार्ट II.9ए) । अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ इन घटनाक्रमों को ट्रैक करने वाले नरम पूर्वाग्रह के साथ अस्थिर रही (चार्ट II.9बी)। अमेरिकी विकास पर व्यापार प्रतिबंधों के संभावित नकारात्मक प्रभाव ने अमेरिकी डॉलर पर दबाव डाला और अमेरिकी डॉलर सूचकांक (डीएक्सवाई) फरवरी में 0.7 प्रतिशत कमजोर हुआ

केंद्रीय बैंकों ने या तो अपनी नीतिगत दरें कम कर दी हैं या अपनी ताजा नीति बैठकों में यथास्थिति बनाए रखी है। एई केंद्रीय बैंकों में, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) और कनाडा ने मार्च में अपनी नीतिगत दरों में 25 बीपीएस की कटौती की और यूके,

[10] इनमें निराशाजनक फ्लैश पीएमआई और सुस्त उपभोक्ता भावना सूचकांक शामिल हैं।

**चार्ट II.8: मुद्रास्फीति एईएस और ईएमई**

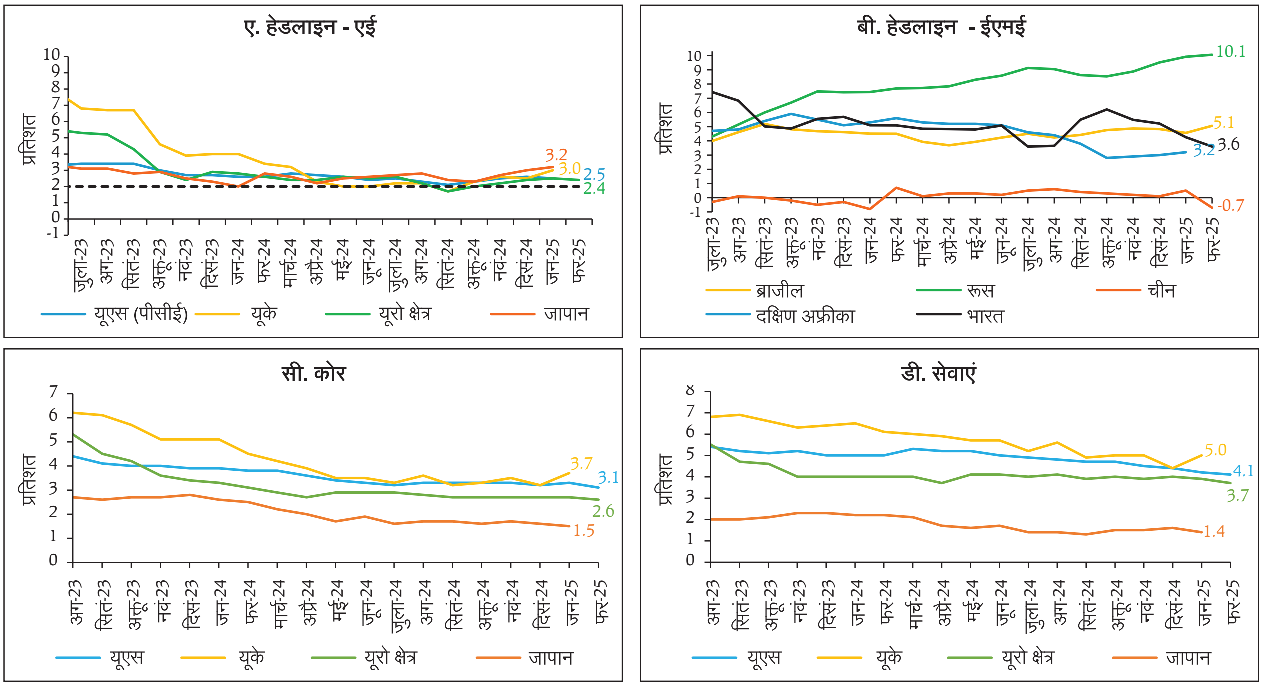


**स्रोत**: ब्लूमबर्ग और ओईसीडी।

चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ने फरवरी में अपनी प्रमुख दरों में 25 बीपीएस की कमी की। आइसलैंड और न्यूजीलैंड ने फरवरी में अपनी दरों में कटौती को बढ़ाकर 50 बीपीएस कर दिया (चार्ट II.10ए)। हालांकि, इज़राइल ने अपनी

**चार्ट II.9: वैश्विक वित्तीय बाज़ार**

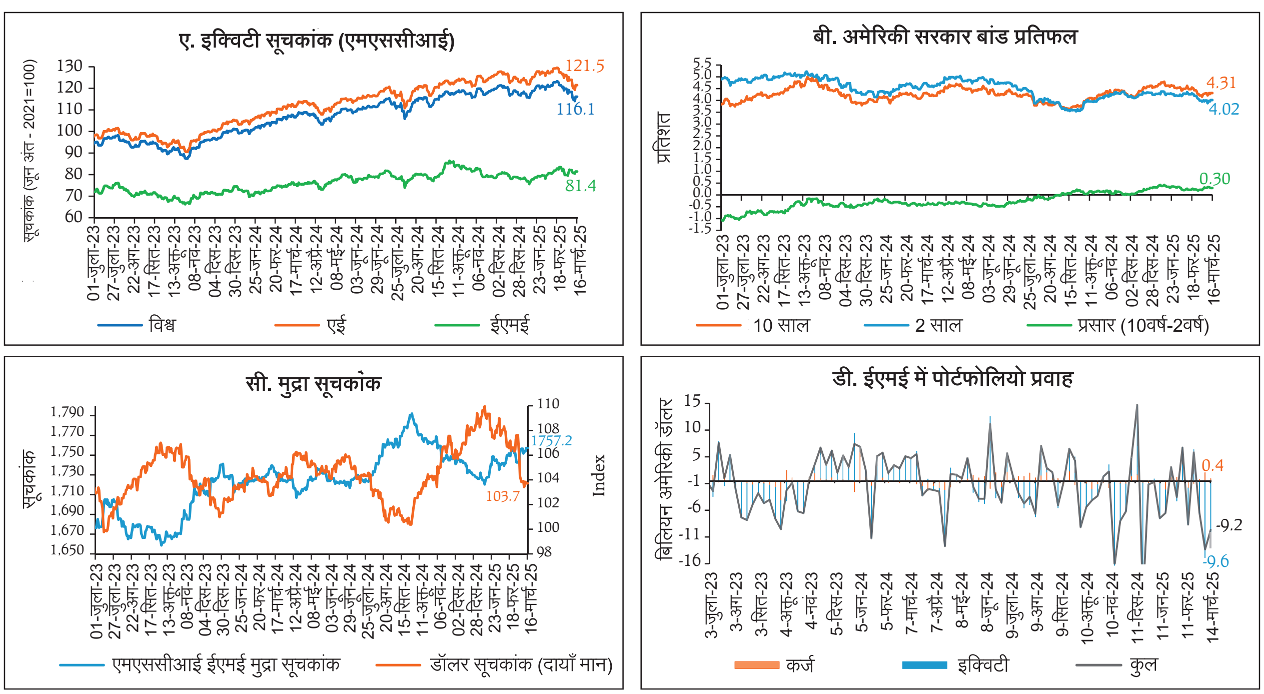


**स्रोत**: ब्लूमबर्ग और ओईसीडी।

**चार्ट II.10: नीति दरों में परिवर्तन**

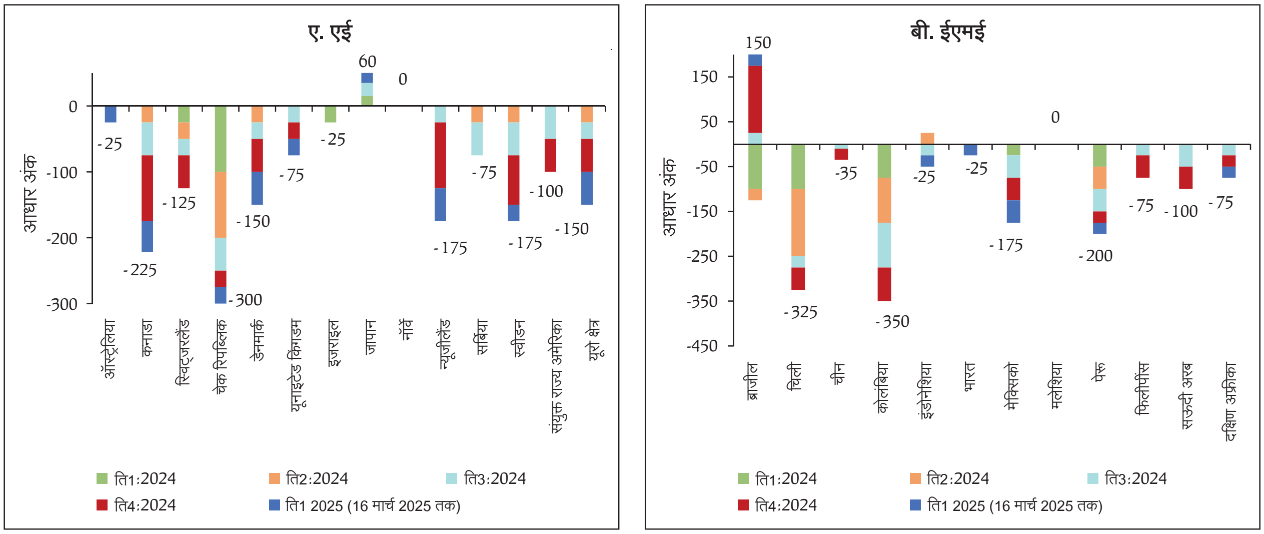


**स्रोत:** ब्लूमबर्ग।

नीति दर को अपरिवर्तित रखा। ईएमई केंद्रीय बैंकों में, चीन, रूस, हंगरी, फिलीपींस, इंडोनेशिया और रोमानिया ने फरवरी में अपनी नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा। मलेशिया, पेरू और पोलैंड ने मार्च में अपनी नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा, जबकि थाईलैंड ने अपनी नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कटौती की, और मेक्सिको ने अपनी बेंचमार्क दर में 50 आधार अंकों की कटौती की (चार्ट II.10बी)।

## III. घरेलू घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था ने निजी खपत और सरकारी खर्च के कारण 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान वृद्धि में क्रमिक वृद्धि दर्ज की। फरवरी में मामूली वृद्धि के बावजूद आपूर्ति शृंखला दबाव ऐतिहासिक औसत स्तर से नीचे रहा (चार्ट III.1)।

**चार्ट III.1: आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (आईएसपीआई)**

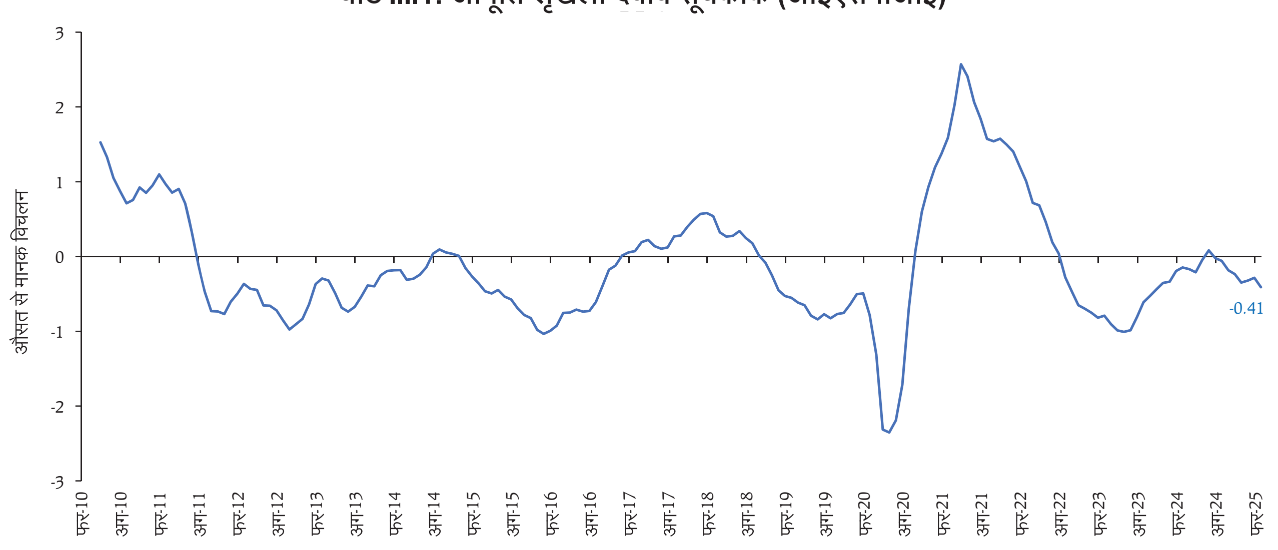


**स्रोत:** आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

**समग्र मांग**

2025 को जारी राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 2024-25 में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है - जो उच्च आधार के बावजूद पहले अग्रिम अनुमान (एफएई) से 10 बीपीएस की वृद्धि दर्शाता है। यह निवल निर्यात में 120 बीपीएस की वृद्धि को 7.1 प्रतिशत और निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में 30 बीपीएस की वृद्धि को 7.6 प्रतिशत पर दर्शाता है। 2023-24 के लिए वृद्धि दर को भी अनंतिम अनुमान (पीई) से 100 बीपीएस बढ़ाकर 9.2 प्रतिशत कर दिया गया।

तिमाही प्रक्षेपवक्र के संदर्भ में, विकास दर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण उपभोग में निरंतर गति और शहरी उपभोग में पुनरुद्धार के कारण तीसरी तिमाही के दौरान पीएफसीई वृद्धि बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गई। केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा व्यय में वृद्धि के कारण सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) की वृद्धि तीसरी तिमाही के दौरान सुधरकर 8.3 प्रतिशत हो गई। हालांकि, स्थिर निवेश में वृद्धि 5.7 प्रतिशत तक कम हो गई, जैसा कि इसके निकटतम संकेतकों - स्टील की खपत और पूंजीगत वस्तुओं के आयात में परिलक्षित होता है। वैश्विक व्यापार और विश्व मांग में बाधाओं के बावजूद, निर्यात में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसे मुख्य रूप से सेवाओं का समर्थन प्राप्त हुआ। आयात के मुकाबले निर्यात में वृद्धि के साथ, 2024-25 की तीसरी तिमाही में निवल निर्यात में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 2.5 प्रतिशत अंकों का धनात्मक योगदान दिया (चार्ट III.2)।

उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि 2024-25 की चौथी तिमाही में कुल मांग सुदृढ़ बनी रहेगी। ई-वे बिल और टोल संग्रह जैसे गतिविधि संकेतकों ने फरवरी 2025 में दोहरे अंकों (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की (चार्ट III.3ए और चार्ट III.3बी)।

फरवरी में थोक ऑटोमोबाइल बिक्री में 6.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई (चार्ट III.4ए)। दोपहिया वाहनों के खंड में 9.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण मोटरसाइकिल की बिक्री में गिरावट थी (चार्ट III.4बी)। ट्रैक्टर की बिक्री में लगातार तीसरे महीने दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई। फरवरी में वाहन पंजीकरण में संकुचन दर्ज किया गया, जो गैर-परिवहन और परिवहन वाहन दोनों खंडों में गिरावट के कारण हुआ (चार्ट III.4सी)। फरवरी में पेट्रोलियम की खपत में 2.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की कमी आई (चार्ट III.4डी)।

**चार्ट III.2: जीडीपी वृद्धि में भारित योगदान**

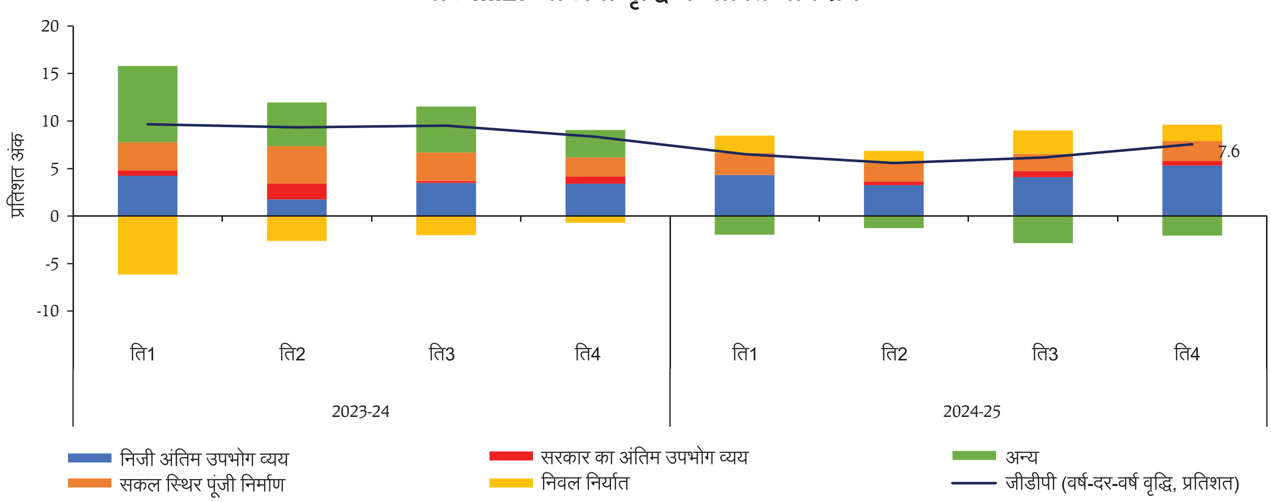


**टिप्पणियाँ:** 1. #: अंतर्निहित वृद्धि।
2. अन्य में स्टॉक, मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तन और सांख्यिकीय विसंगतियां शामिल हैं।

**स्रोत:** एनएसओ।

**चार्ट III.3: ई-वे बिल और टोल संग्रह**

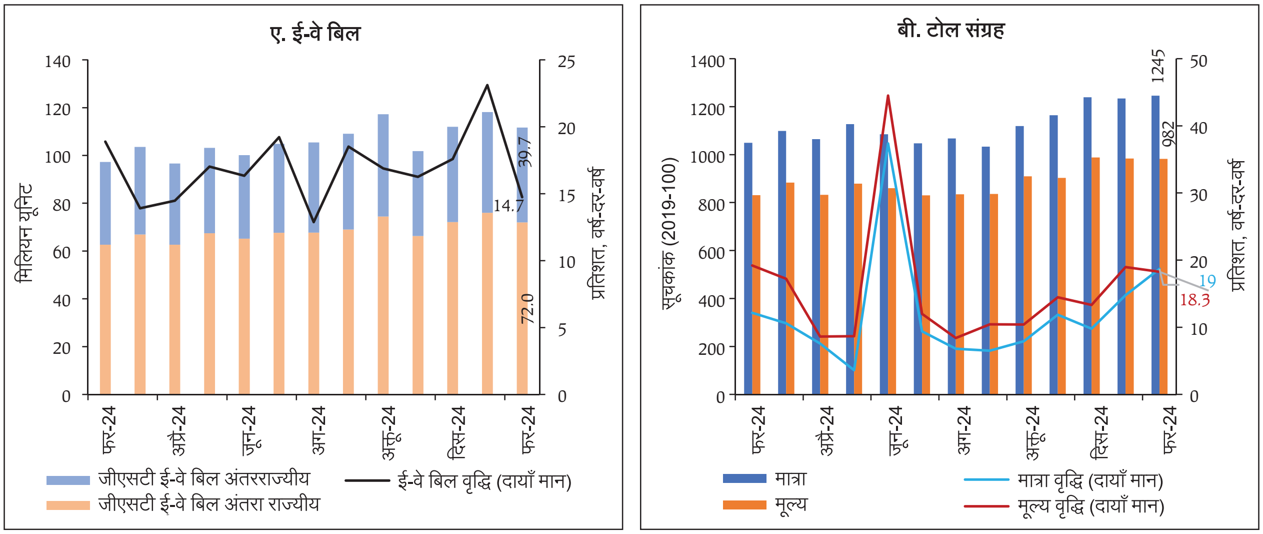


**स्रोत:** जीएसटीएन; और आरबीआई।

फरवरी 2025 में, संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन ने पीएमआई सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से विस्तार की दूसरी सबसे तेज़ दर दर्ज की। सेवा क्षेत्र में भी रोजगार में तेज़ गति से वृद्धि जारी रही (चार्ट III.5)

**चार्ट III.4: ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संकेतक**

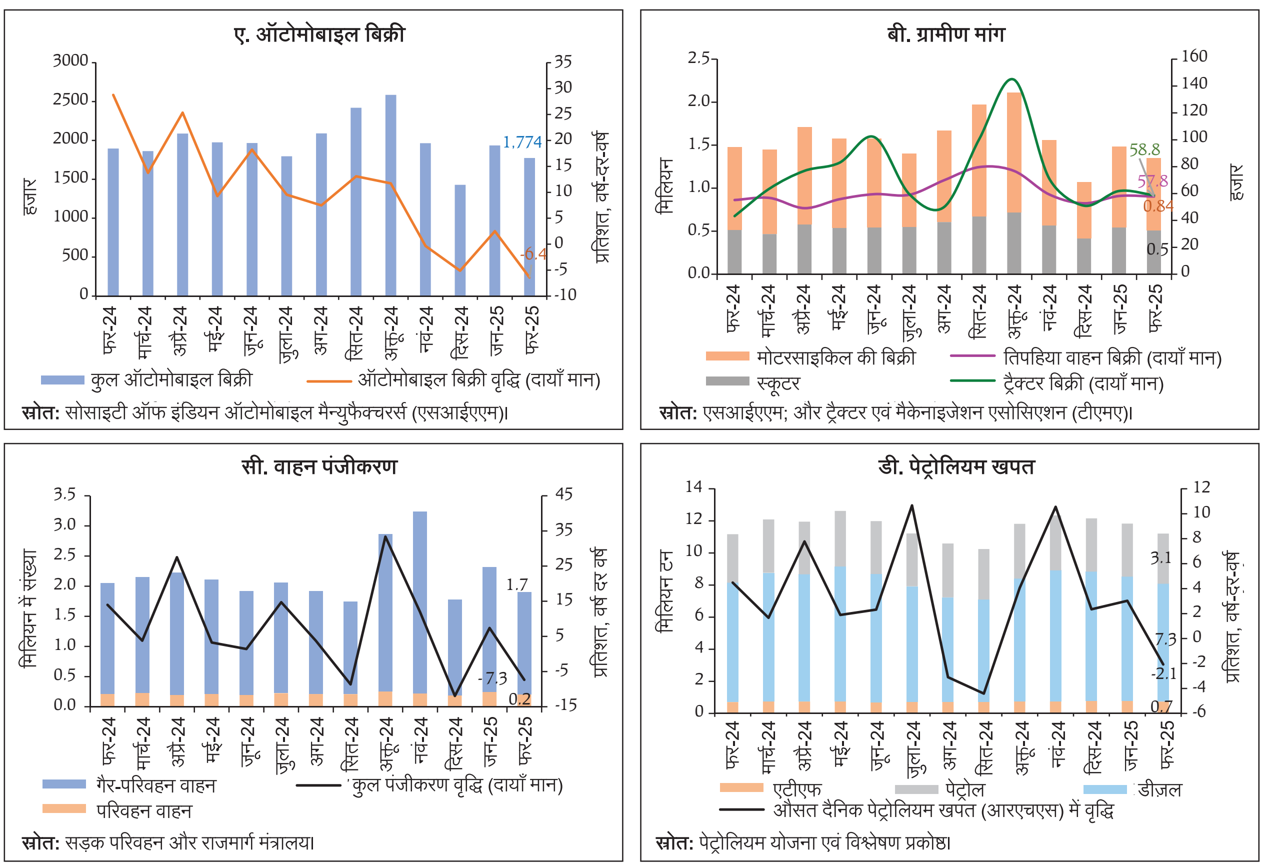

**चार्ट III.5: पीएमआई रोजगार सूचकांक**

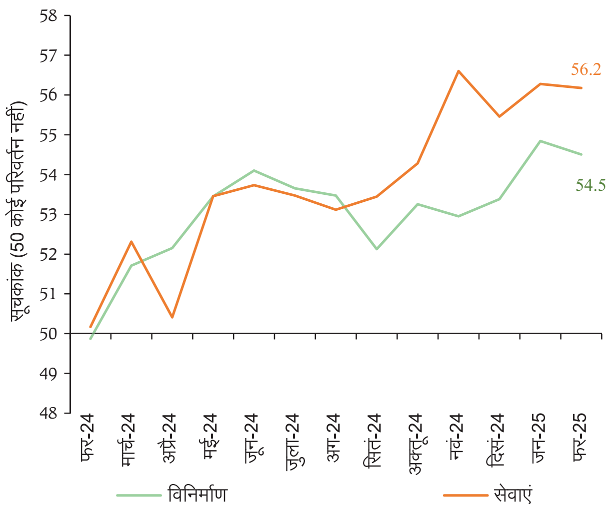


**टिप्पणी:** 50 से ऊपर का पीएमआई मूल्य विस्तार को दर्शाता है।
**स्रोत:** एस एंड पी ग्लोबल।

**चार्ट III.6: पीएलएफएस त्रैमासिक (आयु 15 वर्ष और उससे अधिक)**

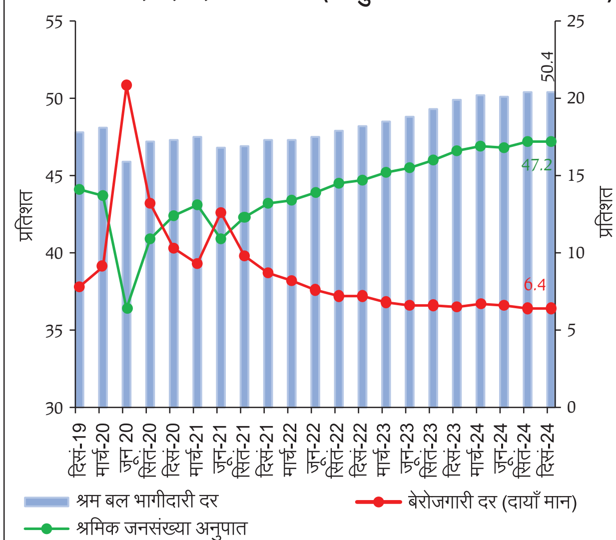


**स्रोत:** एमओएसपीआई।

नवीनतम तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, अक्तूबर-दिसंबर 2024 के दौरान शहरी बेरोजगारी दर 6.4 प्रतिशत थी, जो पिछली तिमाही से अपरिवर्तित थी और पीएलएफएस शृंखला में सबसे कम थी। श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआई) स्थिर रहे (चार्ट III.6)।

लगातार चार महीनों तक क्रमिक वृद्धि दर्ज करने के बाद, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत काम की मांग फरवरी 2025 में 3.1 प्रतिशत (मासिक) घट गई, जो रबी की कटाई की शुरुआत के साथ मेल खाती है (चार्ट III.7)।

फरवरी 2025 में भारत का वस्तु निर्यात 10.9 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) घटकर 36.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण हुआ, जिसने धनात्मक गति को संतुलित कर दिया (चार्ट III.8)।

फरवरी में 30 प्रमुख वस्तुओं में से 17 (जो 2023-24 में निर्यात टोकरी का 75.3 प्रतिशत हिस्सा हैं) के निर्यात में साल-दर-साल आधार पर कमी आई। पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और रत्नों और आभूषणों ने नकारात्मक योगदान दिया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान, चावल, अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्कों ने फरवरी में निर्यात वृद्धि का समर्थन किया (चार्ट III.9)।

अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान, भारत का व्यापारिक निर्यात 0.1 प्रतिशत बढ़कर 395.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य भाग इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, चावल और दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स ने किया,

**चार्ट III.7: एमजीएनआरईजीएस के तहत काम के लिए परिवारों की मांग**

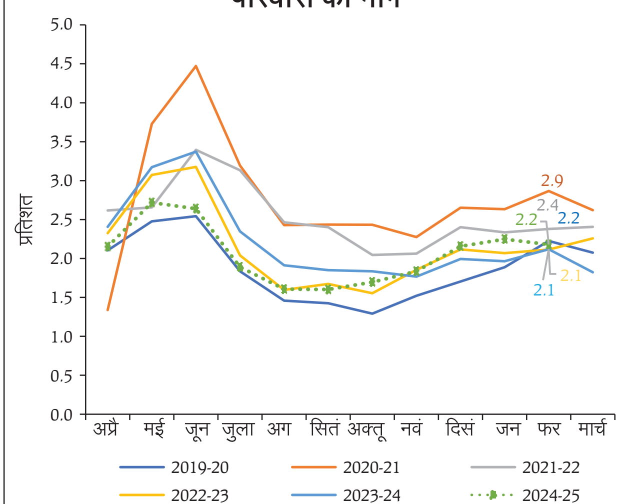


**स्रोत:** ग्रामीण विकास मंत्रालय।

**चार्ट III.8: भारत का पण्य निर्यात**

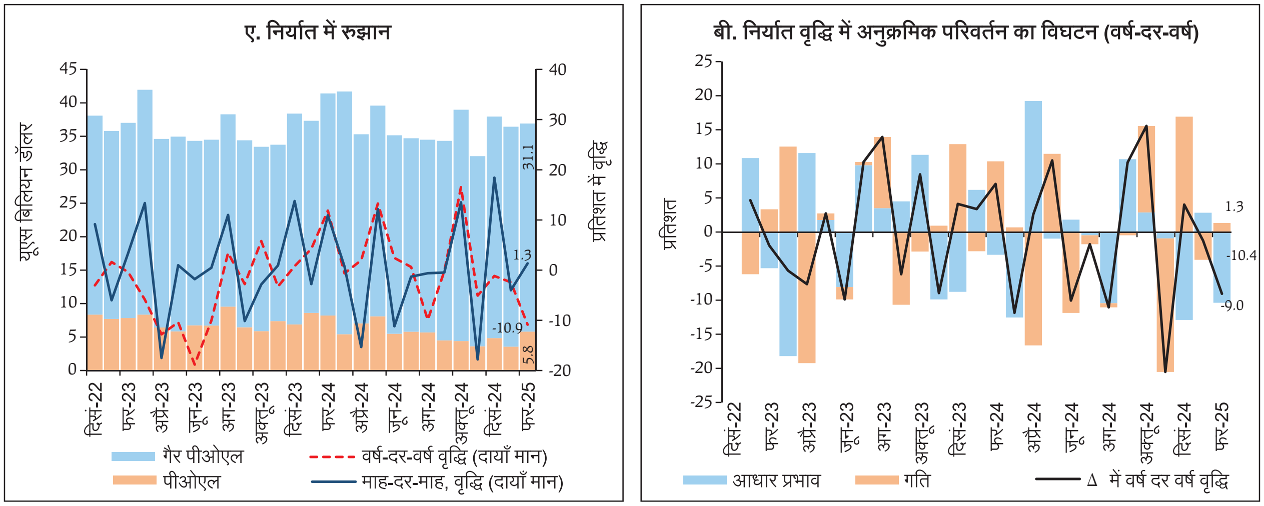


**टिप्पणी:** पीओएल: पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक।
**स्रोत:** पीआईबी; डीजीसीआईएंडएस; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण और लौह अयस्क ने निर्यात को नीचे कर दिया।

फरवरी 2025 में 20 प्रमुख गंतव्यों में से 14 को निर्यात में कमी आएगी, जबकि अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान 20 प्रमुख गंतव्यों में से 13 को निर्यात में वृद्धि होगी, जिसमें अमेरिका, यूएई और नीदरलैंड शीर्ष तीन निर्यात गंतव्य होंगे।

**चार्ट III.9: भारत का पण्य निर्यात - सापेक्ष योगदान**
(फरवरी 2024 की तुलना में फरवरी 2025 की स्थिति)

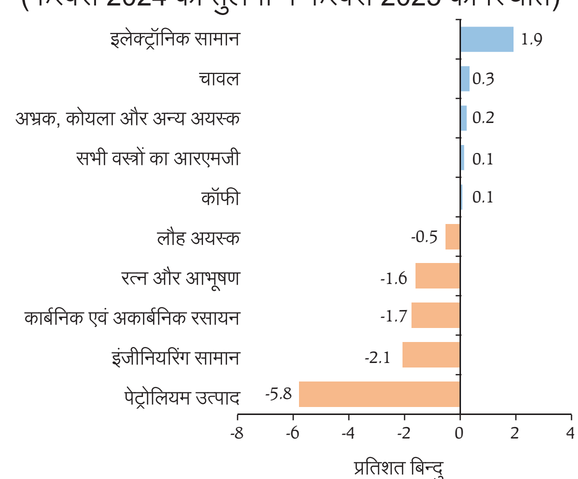


**स्रोत:** पीआईबी; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

फरवरी में माल आयात 51.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 16.3 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की गिरावट दर्शाता है। ऐसा मुख्य रूप से तेल और सोने के आयात में गिरावट के कारण हुआ, जो लगातार 10 महीनों तक बढ़ा था। 30 प्रमुख वस्तुओं में से 12 वस्तुओं (आयात समूह का 56.8 प्रतिशत हिस्सा) में वर्ष दर वर्ष आधार पर संकुचन दर्ज किया गया (चार्ट III.10)।

पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद, सोना, चांदी, कोयला, कोक और ब्रिकेट, आदि, और मोती, और कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों ने आयात को नीचे खींच लिया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान, रासायनिक सामग्री और उत्पाद, वनस्पति तेल, मशीनरी, विद्युत और गैर-विद्युत, एवं अलौह धातुओं ने धनात्मक योगदान दिया (चार्ट III.11)।

अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान, भारत का व्यापारिक आयात 5.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 656.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें मुख्य रूप से सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद, तथा मशीनरी का योगदान रहा, जबकि कोयला, कोक और ब्रिकेट, आदि, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, तथा लोहा और इस्पात का योगदान ऋणात्मक रहा।

**चार्ट III.10: भारत का पण्य आयात**

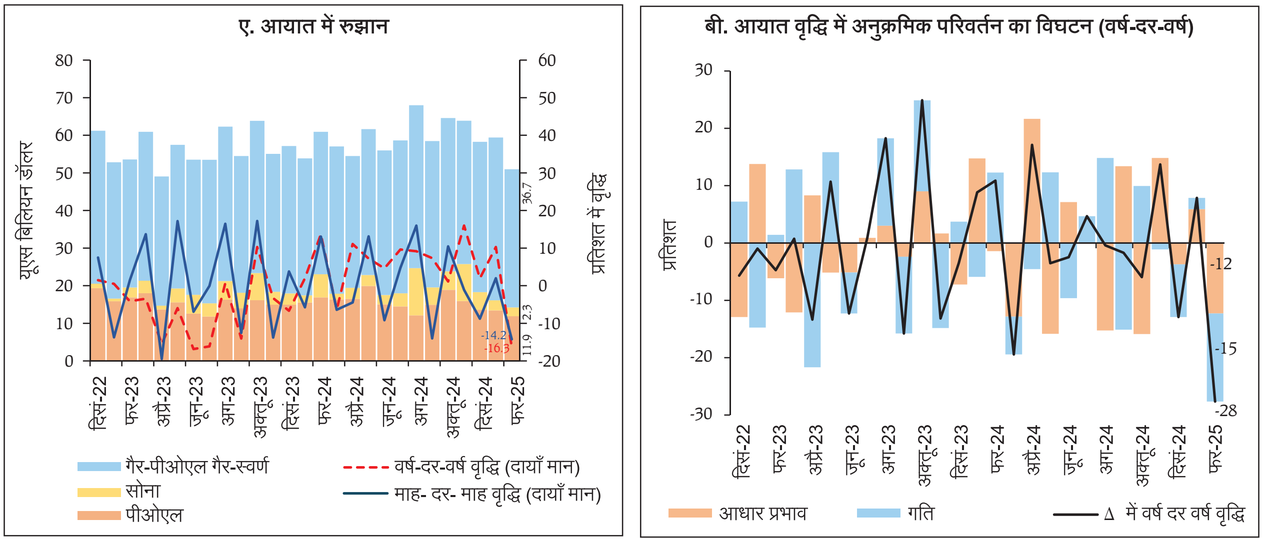


**स्रोत:** पीआईबी; डीजीसीआईएंडएस; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

फरवरी 2025 में 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 13 से आयात में कमी आई, जबकि अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 11 से आयात में वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान प्रमुख आयात स्रोत देशों, जैसे चीन, रूस और यूएई में आयात में वृद्धि देखी गई।

तेल और गैर-तेल घाटे में कमी के कारण व्यापारिक व्यापार घाटा अगस्त 2021 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर 14.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया। व्यापार घाटे में तेल घाटे की हिस्सेदारी फरवरी में 43.3 प्रतिशत पर आ गई, जो एक साल पहले 44.5 प्रतिशत थी। यह बड़ी गिरावट के कारण हुआ (चार्ट III.12)।

अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान, भारत का पण्य व्यापार घाटा एक साल पहले के 225.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 261.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पेट्रोलियम

**चार्ट III.11: भारत का व्यापारिक आयात - सापेक्ष योगदान**
(फरवरी 2024 की तुलना में फरवरी 2025 की स्थिति)

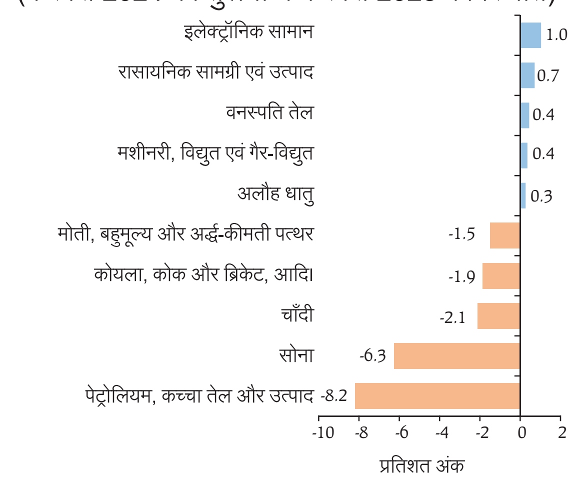


**स्रोत:** पीआईबी; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

**चार्ट III.12: भारत के व्यापारिक कारोबार घाटे का अपघटन**

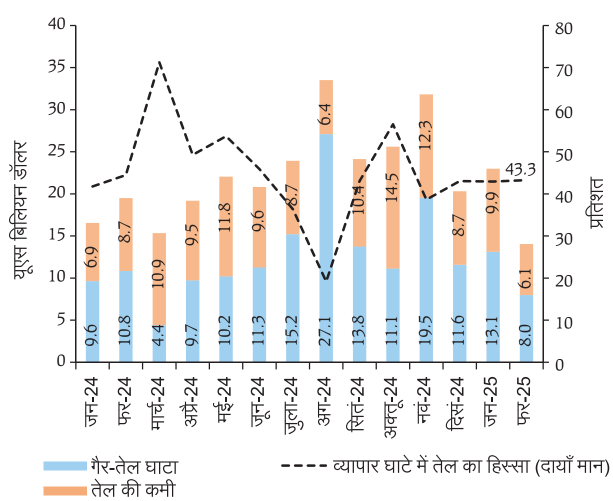


**स्रोत:** पीआईबी; तथा डीजीसीआईएंडएस।

**चार्ट III.13: वस्तु-वार पण्य व्यापार घाटा**

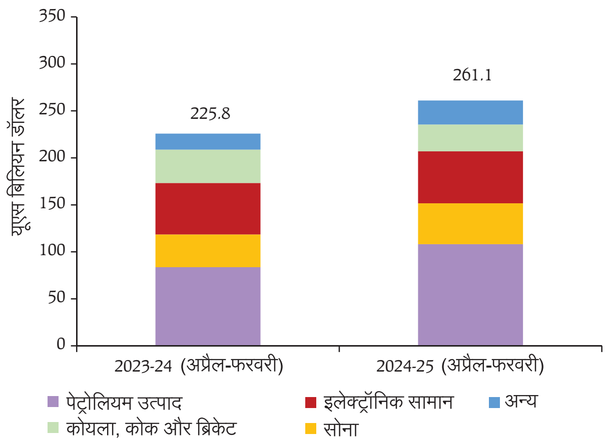


**टिप्पणी:** जनवरी और फरवरी 2025 में कोयला, कोक और ब्रिकेट का निर्यात दिसंबर 2024 के समान स्तर पर माना जाता है। सोने के निर्यात का अनुमान है।
**स्रोत:** पीआईबी; डीजीसीआईएंडएस; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

**चार्ट III. 14: सेवा निर्यात और आयात: विकास दर**

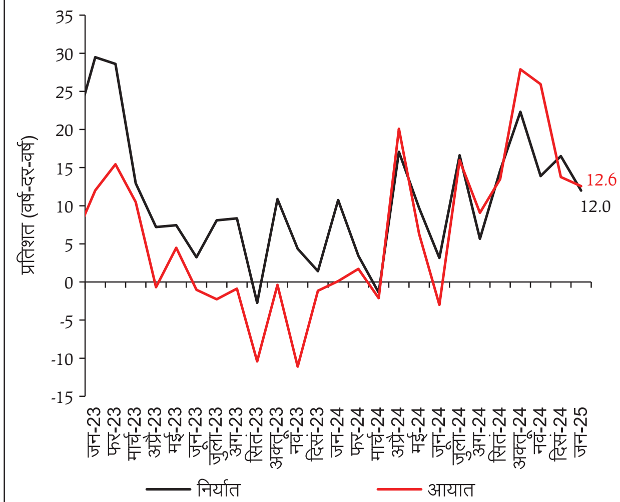


**स्रोत:** आरबीआई।

उत्पाद घाटे का सबसे बड़ा स्रोत थे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोना (चार्ट III.13) का स्थान था।

जनवरी 2025 में, सेवाओं का निर्यात 12.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 34.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, और सेवाओं का आयात 12.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.14)। जनवरी में निवल सेवा निर्यात आय में 11.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई।

अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान, संशोधित अनुमान (आरई) के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और राजस्व घाटा (आरडी) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक रहा, जिसका मुख्य कारण हाल के महीनों में केंद्र सरकार के राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों में वृद्धि है (चार्ट III.15ए)।[11]

**चार्ट III.15: अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान प्रमुख राजकोषीय संकेतक**

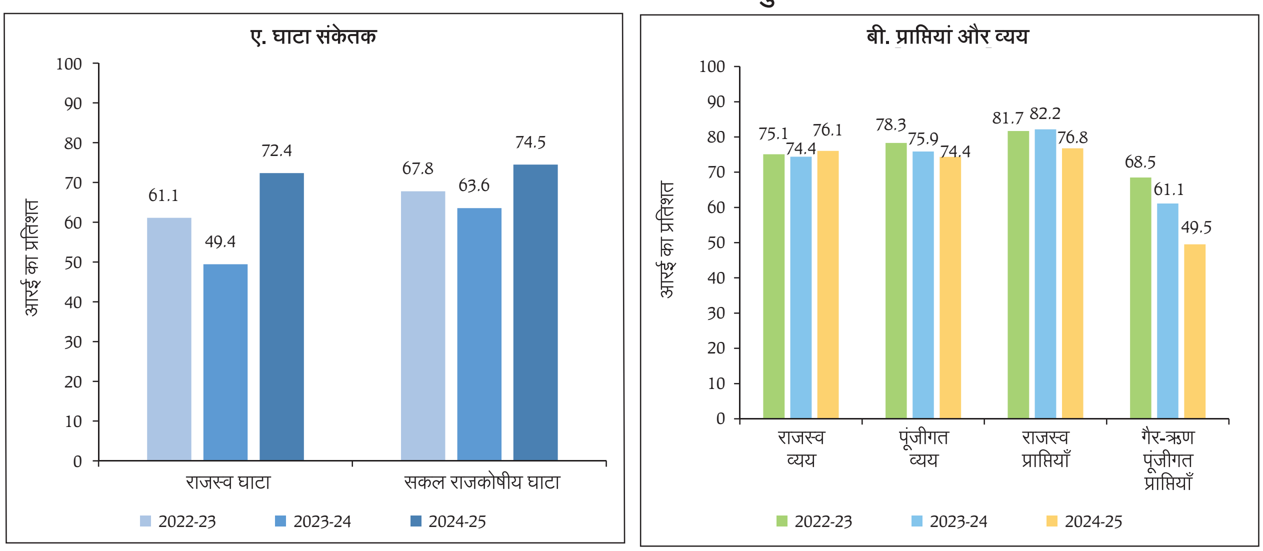


**स्रोत:** केंद्रीय बजट दस्तावेज; तथा सीजीए।

[11] लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार।

कर संग्रह भी मजबूत बना रहा। राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय जैसे प्रमुख राजकोषीय संकेतक मोटे तौर पर पिछले वर्ष (आरई के प्रतिशत के रूप में) के अनुरूप रहे, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को छोड़कर जो पिछले वर्ष की तुलना में कम रही हैं (चार्ट III.15बी)।

केंद्र सरकार का कुल व्यय पिछले वर्ष की इसी अवधि के 5.9 प्रतिशत की तुलना में 6.4 प्रतिशत बढ़ा, क्योंकि पूंजी और राजस्व व्यय दोनों में वृद्धि हुई। केंद्र के राजस्व व्यय के भीतर, प्रमुख सब्सिडी पर व्यय में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष 21.0 प्रतिशत की कमी की तुलना में अधिक खाद्य सब्सिडी के कारण हुआ।

अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान किया गया पूंजीगत व्यय 2024-25 के संशोधित अनुमान का 74.4 प्रतिशत रहा, जो मोटे तौर पर पिछले वर्ष के अनुरूप है। अक्तूबर 2024 से केंद्र के पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि देखी गई, जिसने 2024-25 की पहली छमाही के दौरान देखी गई सुस्ती की भरपाई की (चार्ट III.16ए)। 2024-25 के लिए उच्चतम बजटीय पूंजीगत व्यय लक्ष्य वाले मंत्रालयों ने 2024-25 के अपने संशोधित पूंजीगत व्यय लक्ष्य को प्राप्त करने में पर्याप्त प्रगति की है (चार्ट III.16बी)।

**चार्ट III.17: अप्रैल-जनवरी के दौरान कर राजस्व**

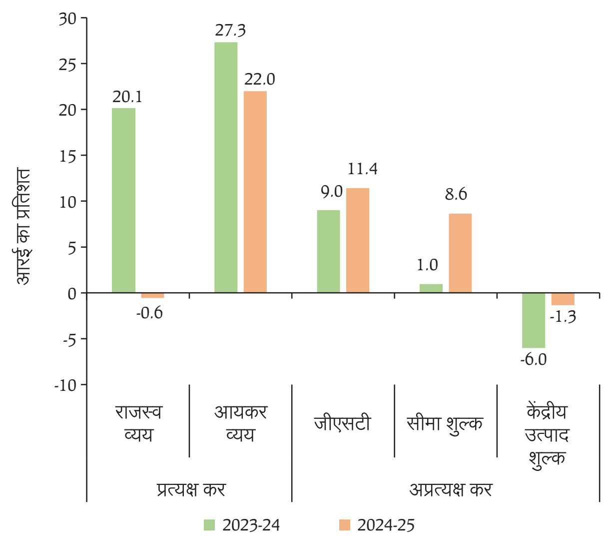


**स्रोत:** केंद्रीय बजट दस्तावेज; तथा सीजीए।

अप्रैल-जनवरी 2024-25 में केंद्र के सकल कर राजस्व और कुल प्राप्तियों में क्रमशः 10.3 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आयकर और जीएसटी 2024-25 में केंद्र के मजबूत कर संग्रह के लिए प्रमुख चालक बने रहे। जबकि निगम कर का प्रदर्शन कमतर रहा, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वृद्धि में सुधार हुआ है (चार्ट III.17)।

**चार्ट III.16: अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार का व्यय**

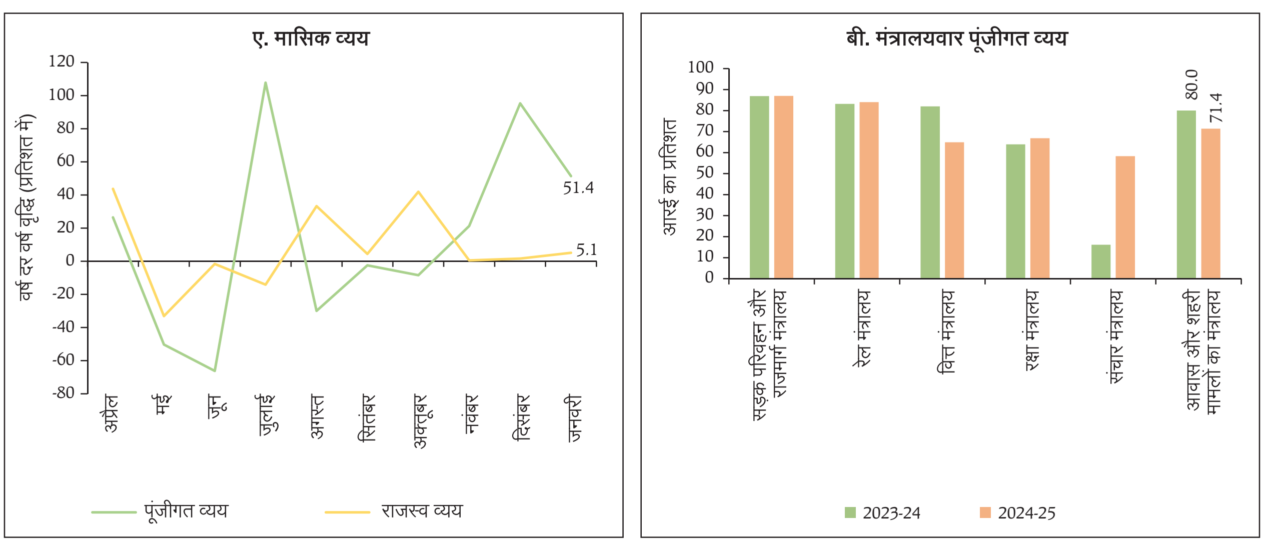


**स्रोत:** केंद्रीय बजट दस्तावेज; तथा सीजीए।

**चार्ट III.18: एसटीटी और जीएसटी में मासिक रुझान**

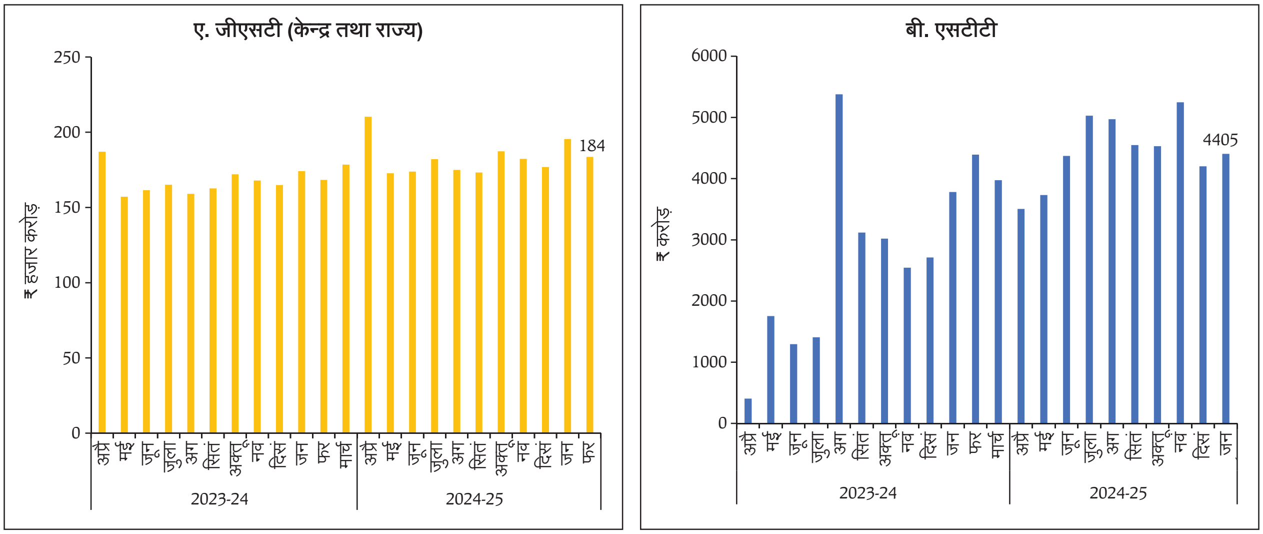


**स्रोत:** सीजीए; प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी); और जीएसटी पोर्टल।

फरवरी 2025 में जीएसटी प्राप्तियां (केंद्र और राज्य) 9.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ीं (चार्ट III.18ए)। अप्रैल-फरवरी 2024-25 के लिए संचयी जीएसटी संग्रह ₹20.13 लाख करोड़ रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) से कर संग्रह में 75.3 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में इसका हिस्सा पिछले वर्ष के 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गया है (चार्ट III.18बी)।

भारतीय रिज़र्व बैंक से 2.11 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण के कारण गैर-कर राजस्व संग्रह में जोरदार वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का प्रदर्शन धीमा रहा, जिसका आंशिक कारण विनिवेश प्राप्तियां कम होना है।

अप्रैल-जनवरी 2024-25 के अनंतिम लेखा आंकड़ों के अनुसार, राजस्व प्रदर्शन में सुधार और पूंजीगत व्यय में कमी के कारण बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में राज्यों का जीएफडी पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कम था (चार्ट III.19)। राजस्व प्राप्तियों में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जिसे उच्च कर राजस्व का समर्थन प्राप्त था, जबकि गैर-कर राजस्व में वृद्धि धीमी रही (चार्ट III.20ए)। राज्यों के अपने कर राजस्व के भीतर, राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) में मजबूत वृद्धि देखी गई और बिक्री कर/वैट संग्रह में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान संकुचन से सुधार के संकेत दिखे।

**चार्ट III. 19: राज्यों के राजकोषीय संकेतक**
(अप्रैल-जनवरी)

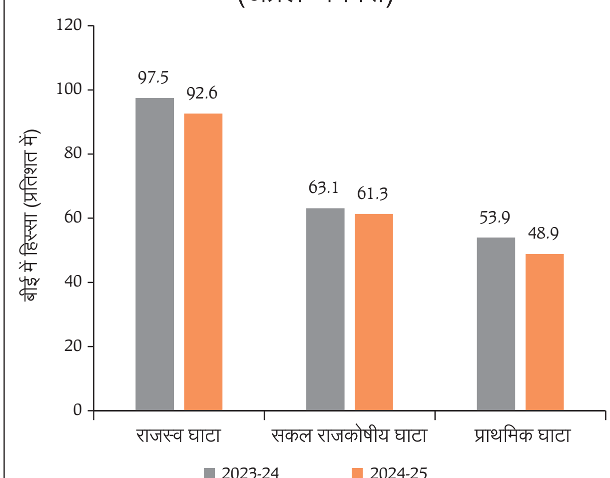


**टिप्पणी:** डेटा 21 राज्यों से संबंधित है।
**स्रोत:** भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)।

**चार्ट III.20: प्रमुख राजकोषीय प्रदर्शन संकेतक (अप्रैल-जनवरी)**

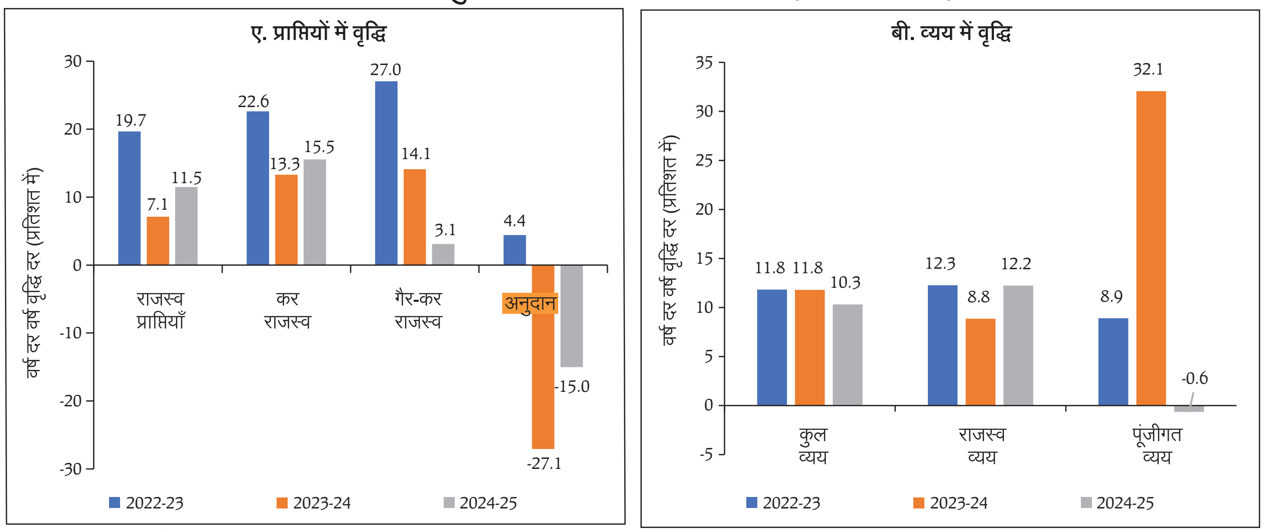


**टिप्पणी:** डेटा 21 राज्यों से संबंधित है।
**स्रोत:** सीएजी।

व्यय पक्ष पर, राजस्व व्यय में वृद्धि अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान बढ़ी, जबकि पूंजीगत व्यय में गिरावट आई (चार्ट III.20बी)। राजस्व व्यय में वृद्धि के साथ-साथ पूंजीगत परिव्यय में संकुचन ने राज्यों के खर्च की गुणवत्ता को कमजोर कर दिया है, पूंजीगत परिव्यय (आरईसीओ) के लिए राजस्व व्यय का अनुपात अप्रैल-जनवरी 2024-25 में पिछले वर्ष की समान अवधि के 6.1 से बढ़कर 7.1 हो गया है।

## समग्र आपूर्ति

एसएई के अनुसार, वर्ष 2024-25 में मूल कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो एफएई के समान है । वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में, वास्तविक जीवीए वृद्धि पिछली तिमाही के 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 6.2 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) हो गई (चार्ट III.21)। विकास को कृषि और सेवा क्षेत्र द्वारा बढ़ावा दिया गया, जबकि उद्योग क्षेत्र ने मामूली प्रदर्शन किया।

सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों की नाममात्र जीवीए वृद्धि पिछली तिमाही से अपरिवर्तित रही, जो कि 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान 5.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रही। फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और रसायन उद्योगों ने वृद्धि में सबसे अधिक योगदान दिया, जो कुल जीवीए में 38 प्रतिशत रहा। इसके विपरीत, लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम और सीमेंट उद्योगों ने समग्र जीवीए वृद्धि में ऋणात्मक योगदान दिया (चार्ट III.22)।

खाद्यान्न उत्पादन में मजबूती और बागवानी उत्पादन में वृद्धि के कारण कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में 2024-25 की

**चार्ट III.21: जीवीए वृद्धि में भारित योगदान**

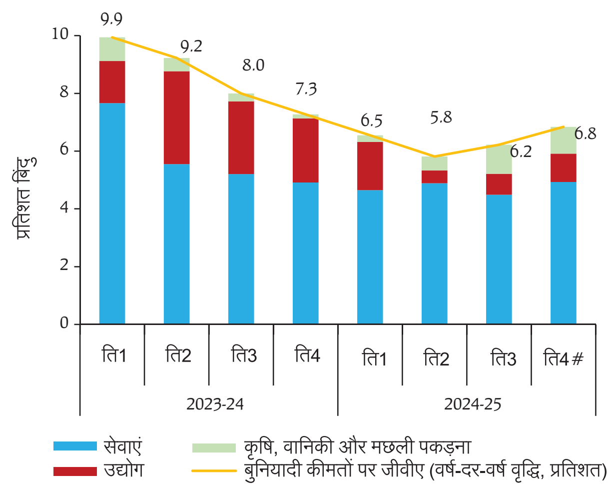


**टिप्पणी :** #: अंतर्निहित वृद्धि।
**स्रोत:** एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.22: विनिर्माण क्षेत्र की नाममात्र जीवीए वृद्धि: उद्योग का योगदान

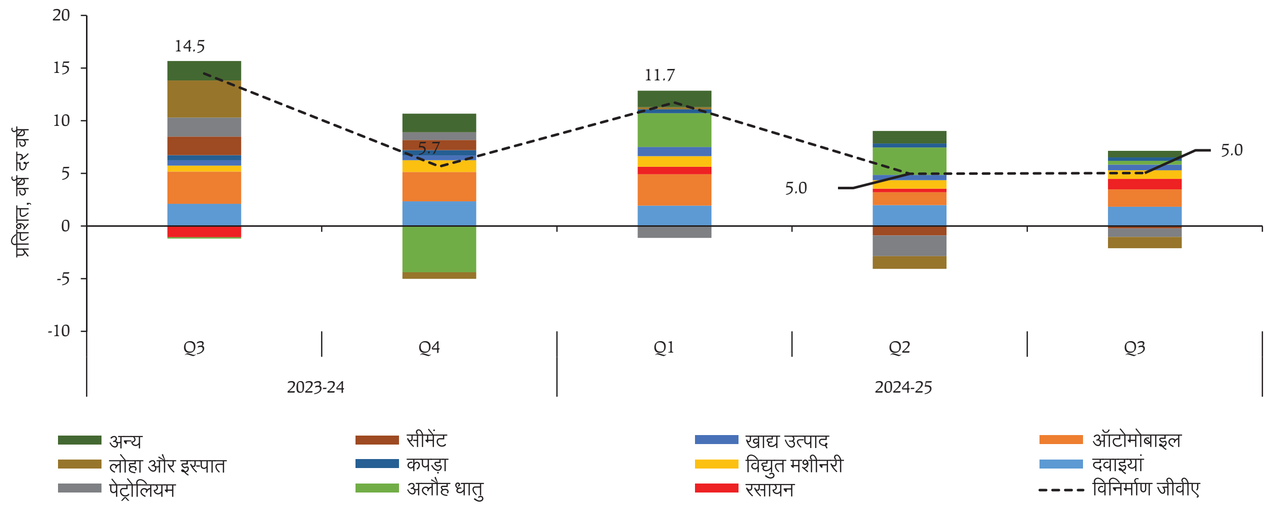


**टिप्पणी:** परिणाम 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए 1,675 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण पर आधारित हैं।
**स्रोत:** कैपिटालाइन डेटाबेस; तथा आरबीआई स्टाफ गणना।

तीसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।[12] पिछली तिमाही में सुस्त प्रदर्शन के बाद औद्योगिक क्षेत्र ने तीसरी तिमाही में मामूली सुधार दिखाया। विनिर्माण क्षेत्र - औद्योगिक जीवीए वृद्धि का प्राथमिक चालक - ने 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिसे सूचीबद्ध कॉरपोरेट विनिर्माण फर्मों की बेहतर लाभप्रदता से सहायता मिली। खनन और उत्खनन में गतिविधि में सुधार हुआ, 2024-25 की तीसरी तिमाही में दूसरी तिमाही की तुलना में संकुचन के मुकाबले 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं में 2024-25 की तीसरी तिमाही में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछली तिमाही में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। सेवा क्षेत्र 2024-25 की तीसरी तिमाही में स्थिर रहा। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर पिछली तिमाही की तुलना में 7.0 प्रतिशत रही, जैसा कि इस्पात की खपत में कमी से पता चलता है, जबकि व्यापार, होटल, परिवहन और संबंधित सेवाओं में वृद्धि दर बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गई, जो मजबूत व्यापारिक गतिविधि के कारण संभव हुई। वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर बनी रही, जबकि सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसे अन्य सेवाओं में मजबूत वृद्धि का समर्थन मिला।

गर्मी के मौसम के दौरान मौसमी तापमान के अपने पूर्वानुमान में, आईएमडी ने मार्च से मई 2025 के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान का अनुमान लगाया है। सामान्य से अधिक तापमान के कारण बिजली की मांग में वृद्धि हो सकती है। हालाँकि, अक्षय स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन पर भारत का बढ़ता ध्यान, गर्मी के मौसम में बढ़ी हुई बिजली की मांग को पूरा करने में मदद कर सकता है (चार्ट III.23)।

सौर ऊर्जा कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का 47 प्रतिशत हिस्सा लेकर प्रमुख योगदानकर्ता बनी हुई है। हाल ही में, भारत ने 100 गीगावॉट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया जो 2014 में 2.82 गीगावॉट से बढ़कर 2025 में 100 गीगावॉट हो गया।[13] मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने के उद्देश्य

[12] खरीफ खाद्य उत्पादन में 2024-25 में 6.8 प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई। पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2024-25 के दौरान बागवानी फसलों का उत्पादन 362.1 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो 2023-24 के अंतिम अनुमानों से 2.1 प्रतिशत अधिक और 2023-24 के पहले अग्रिम अनुमानों से 1.9 प्रतिशत अधिक है।

[13] https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2100603

**चार्ट III.23: नवीकरणीय संसाधनों से बिजली उत्पादन**

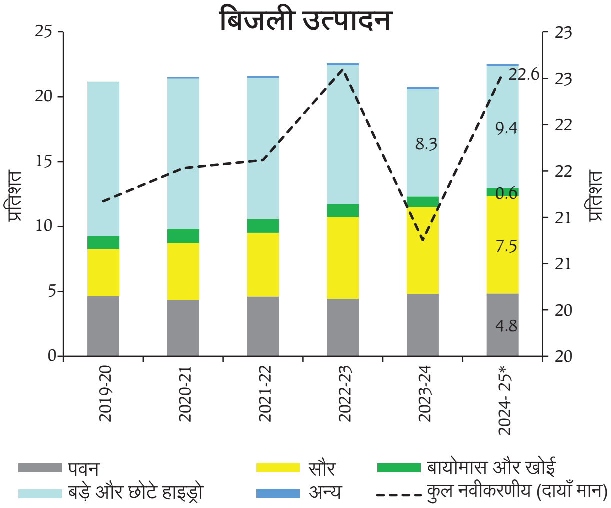


**टिप्पणी:** *जनवरी 2025 तक।
**स्रोत:** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण।

**चार्ट III.24: पीएमएसजीएमबीवाई के तहत छतों पर सौर पैनल की स्थापना**
(27 जनवरी 2025 तक)

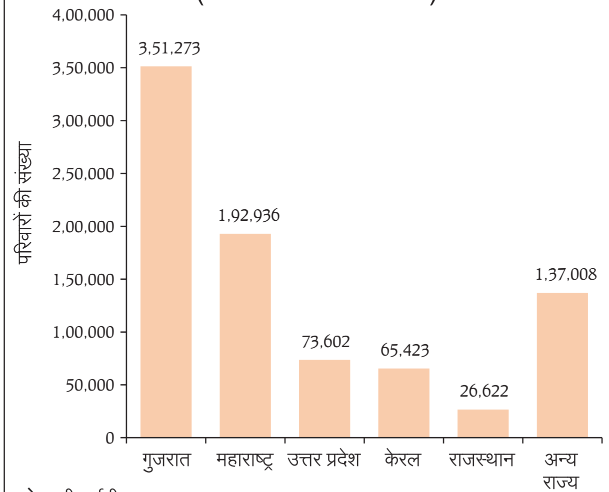


**स्रोत:** पीआईबी।

से, पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) छत पर सौर पैनल लगाने की सुविधा प्रदान करती है। 10 मार्च 2025 तक, 10.09 लाख घरों में छत पर सौर पैनल लगे हुए थे। 27 जनवरी 2025 तक उपलब्ध राज्यवार आंकड़ों के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और राजस्थान मिलकर कुल प्रतिष्ठानों का 84 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं (चार्ट III.24)।

कृषि फसल उत्पादन (खरीफ और रबी)[14] के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2024-25 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 330.9 मिलियन टन रखा गया है, जो खरीफ और रबी दोनों उत्पादन में क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत की वृद्धि के कारण 2023-24 के अंतिम अनुमानों से 4.8 प्रतिशत अधिक है (चार्ट III.25)। गेहूं (प्रमुख रबी प्रधान अनाज) उत्पादन रिकॉर्ड 115.4 मिलियन टन अनुमानित किया गया है जो पिछले वर्ष के अंतिम अनुमानों से 1.9 प्रतिशत अधिक है।

07 मार्च, 2025 तक ग्रीष्मकालीन रकबा पिछले वर्ष की तुलना में 21.1 प्रतिशत अधिक था। सभी प्रमुख फसलों के अंतर्गत रकबा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था, तिलहन को छोड़कर, जिसके लिए यह एक वर्ष पहले की तुलना में थोड़ा कम स्तर पर था (चार्ट III.26)।

जलाशय स्तर (155 प्रमुख जलाशयों के आधार पर) कुल जलाशय क्षमता (13 मार्च, 2025 तक) के 47 प्रतिशत पर एक

**चार्ट III.25: 2024-25 में कृषि उत्पादन (एसएई)**

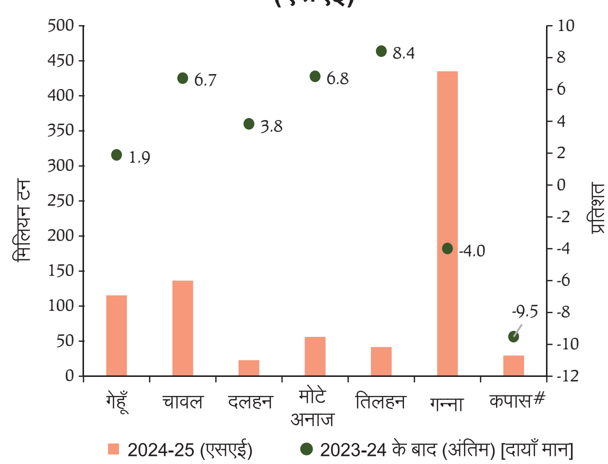


**टिप्पणी:** उत्पादन अनुमान में ग्रीष्मकालीन (ज़ैद) फसलें शामिल नहीं हैं।
#: प्रत्येक 170 किलोग्राम की मिलियन में गांठें।
**स्रोत:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

[14] इन अनुमानों में ग्रीष्म (ज़ैद) ऋतु का उत्पादन शामिल नहीं है, जिसकी बुवाई अभी चल रही है।

[15] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2102149

**चार्ट III.26: साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन *(ज़ैद)* बुवाई प्रगति (7 मार्च तक)**

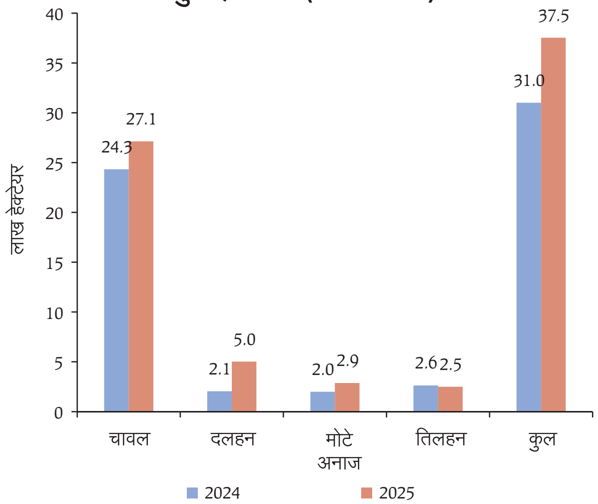


**स्रोत:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

**चार्ट III.27: जलाशय स्तर (13 मार्च तक)**

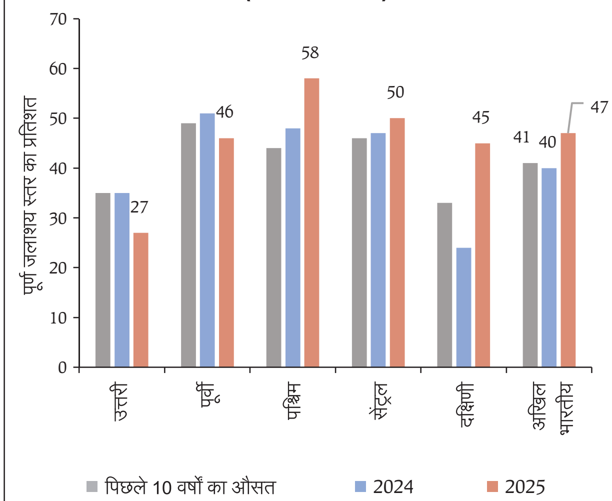


**स्रोत:** केंद्रीय जल आयोग।

संतोषजनक स्थिति में हैं, जो पिछले वर्ष के साथ-साथ दशकीय औसत स्तरों (चार्ट III.27) से भी अधिक है। यह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा देश के अधिकांश हिस्सों में पूरे गर्मी के मौसम (मार्च से मई) के लिए तापमान में असामान्यता और सामान्य से अधिक हीटवेव दिनों के अनुमान से उत्पन्न खड़ी रबी फसलों के लिए चिंताओं को आंशिक रूप से कम करता है (चार्ट III.28)।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा रखे गए खाद्यान्नों का कुल सार्वजनिक स्टॉक बफर आवश्यकताओं से 3.8 गुना अधिक है, जिसका मुख्य कारण चावल का अधिक स्टॉक है

**चार्ट III.28: मार्च 2025 के लिए अधिकतम तापमान का पूर्वानुमान**

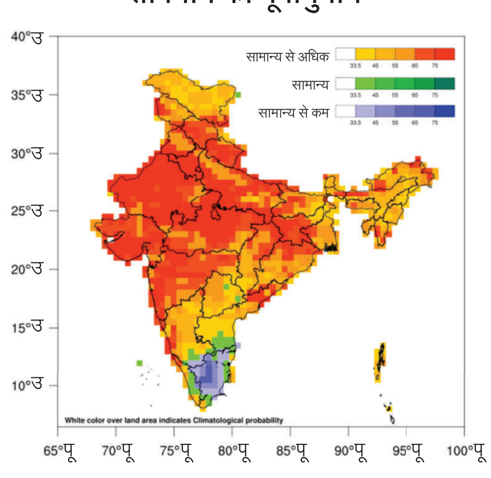


**टिप्पणी:** रंग तापमान की सबसे संभावित श्रेणियों और उनकी संभावनाओं को दर्शाते हैं।
**स्रोत:** भारत मौसम विज्ञान विभाग।

**चार्ट III.29: खाद्यान्नों की खरीद और स्टॉक**

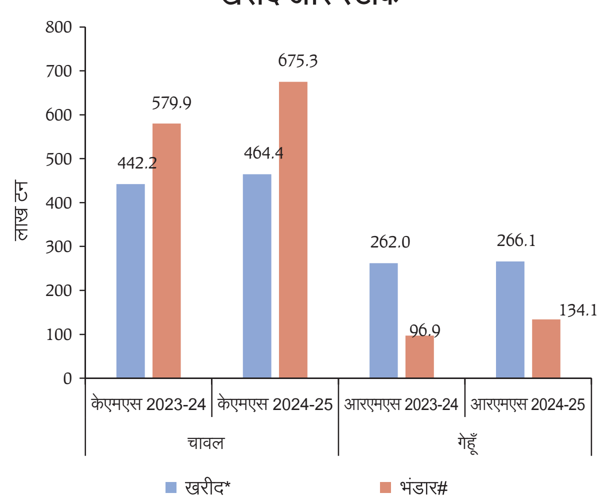


**टिप्पणी:** *: 11 मार्च तक; #: 01 मार्च तक।
**स्रोत:** भारतीय खाद्य निगम।

**चार्ट III.30: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)**

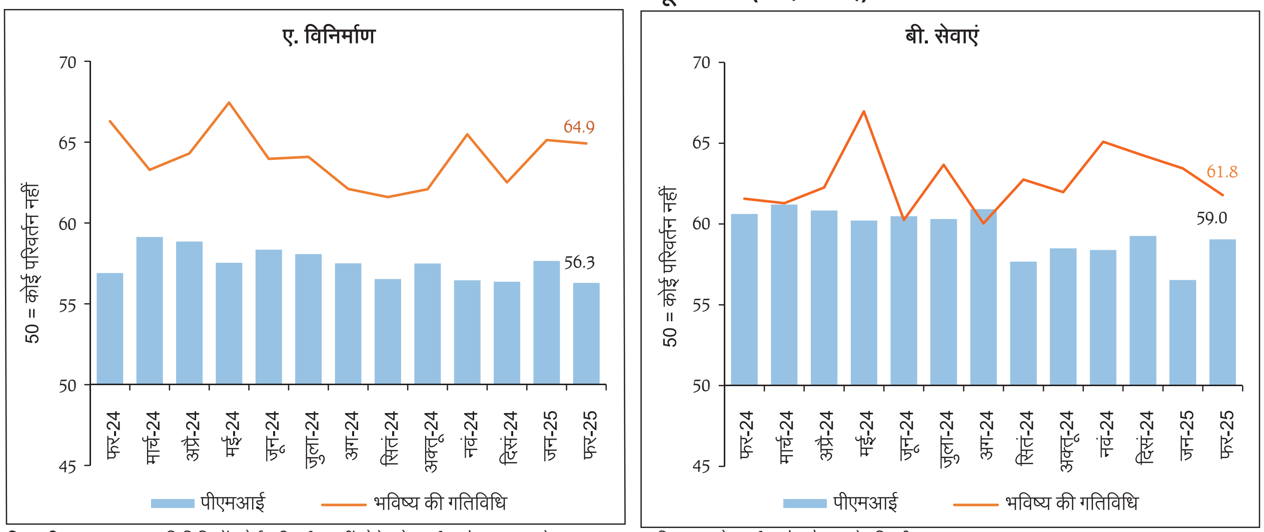


**टिप्पणी:** 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने को दर्शाता है तथा 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।
**स्रोत:** एस एंड पी ग्लोबल।

(चार्ट III.29)। चावल का स्टॉक बफर आवश्यकता से 8.9 गुना अधिक है। गेहूं का स्टॉक पिछले वर्ष की तुलना में 38.3 प्रतिशत अधिक है और बफर मानदंड से ऊपर है। चालू विपणन सत्र के दौरान चावल की खरीद 464.4 लाख टन (11 मार्च, 2025 तक) है जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.0 प्रतिशत अधिक है।

01 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले आगामी रबी विपणन सीजन (2025-26) के लिए गेहूं खरीद का अनुमान 310 लाख टन तय किया गया है।[16] इसी तरह, रबी चावल खरीद और रबी मोटे अनाज (बाजरा सहित) के अनुमान क्रमशः 70 लाख टन और 16 लाख टन तय किए गए हैं।

नए ऑर्डर और उत्पादन में मंदी के कारण भारत का विनिर्माण पीएमआई फरवरी में 14 महीने के निचले स्तर पर आ गया (चार्ट III.30ए)। नए कारोबार में मजबूत वृद्धि से सहायता प्राप्त सेवा पीएमआई ने फरवरी में क्रमिक वृद्धि दर्ज की (चार्ट III.30बी)।

[16] https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2107076®=3&lang=1

औद्योगिक गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतकों में, बंदरगाह यातायात में वृद्धि फरवरी 2025 में तेज हुई, जो अन्य विविध कार्गो और कंटेनरयुक्त कार्गो में उच्च वृद्धि से प्रेरित थी (चार्ट III.31)।

निर्माण क्षेत्र में, फरवरी में इस्पात की खपत में वृद्धि बढ़कर 11.2 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) हो गई, जबकि सीमेंट उत्पादन स्तर

**चार्ट III.31: पोर्ट कार्गो**

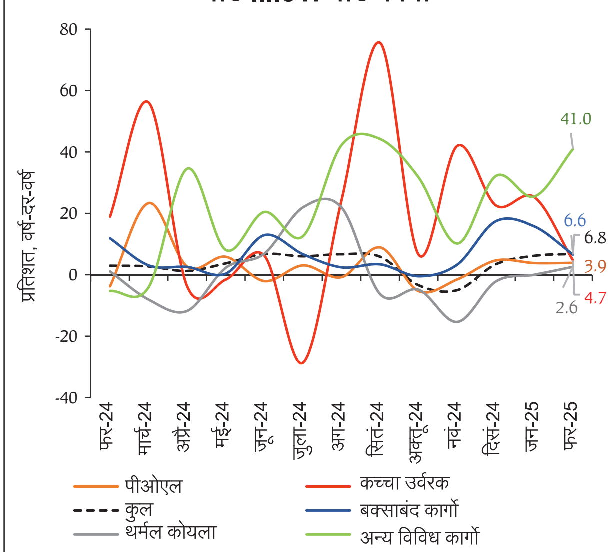


**स्रोत:** भारतीय बंदरगाह संघ।

**चार्ट III. 32: स्टील की खपत और सीमेंट उत्पादन**

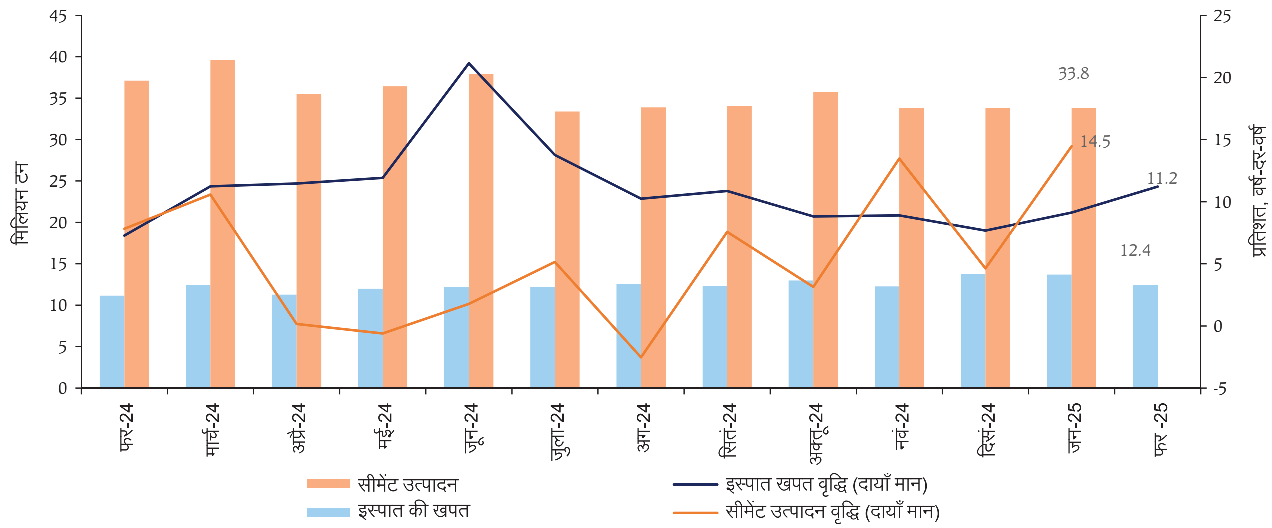


**स्रोत:** संयुक्त संयंत्र समिति; आर्थिक सलाहकार कार्यालय; तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

जनवरी में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया (चार्ट III.32)।

सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक आर्थिक गतिविधि में सुदृढ़ता को दर्शाते हैं (सारणी III.1)।

**सारणी III .1 : उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाएँ**

(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत)

| क्षेत्र | संकेतक | फर-24 | मार्च-24 | अप्रै-24 | मई-24 | जून-24 | जुला-24 | अग-24 | सितं-24 | अक्तू-24 | नवं-24 | दिसं-24 | जन-25 | फर -25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शहरी मांग | यात्री वाहन बिक्री | 9.5 | 8.9 | 1.2 | 4.3 | 4.9 | -2.0 | -1.6 | -0.4 | 1.1 | 4.4 | 11.4 | 3.5 | 3.7 |
| ग्रामीण मांग | दोपहिया वाहन बिक्री | 34.6 | 15.3 | 30.8 | 10.1 | 21.3 | 12.5 | 9.3 | 15.8 | 14.2 | -1.1 | -8.8 | 2.1 | -9.0 |
| | तीन पहिया वाहन बिक्री | 8.3 | 4.3 | 14.5 | 14.4 | 12.3 | 5.1 | 8.0 | 6.7 | -0.7 | -1.3 | 3.5 | 8.6 | 4.7 |
| | ट्रैक्टर बिक्री | -30.6 | -23.1 | -3.0 | 0.0 | 3.6 | 1.6 | -5.8 | 3.7 | 22.4 | -1.3 | 14.0 | 11.4 | 35.9 |
| व्यापार, होटल, यातायात, संचार | वाणिज्यिक वाहन बिक्री | -3.8 | | 3.5 | | | -11.0 | | | 1.3 | | | | |
| | रेलवे माल ढुलाई यातायात | 10.1 | 8.6 | 1.4 | 3.7 | 10.1 | 4.5 | 0.0 | -5.8 | 1.5 | 1.2 | | | |
| | पोर्ट कार्गो यातायात | 3.0 | 2.7 | 1.3 | 3.8 | 6.8 | 5.9 | 6.7 | 5.8 | -3.4 | -4.9 | 3.4 | 7.6 | 6.8 |
| | घरेलू हवाई कार्गो यातायात | 11.5 | 8.7 | 0.3 | 10.3 | 10.3 | 8.8 | 0.6 | 14.0 | 8.9 | 0.3 | 4.3 | 6.9 | |
| | अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात | 30.2 | 22.5 | 16.2 | 19.2 | 19.6 | 24.4 | 20.7 | 20.5 | 18.4 | 16.1 | 10.5 | 7.1 | |
| | घरेलू हवाई यात्री यातायात* | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 5.9 | 6.9 | 7.6 | 6.7 | 7.4 | 9.6 | 13.8 | 10.8 | 14.1 | 16.4 |
| | अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात* | 19.3 | 15 | 16.8 | 19.6 | 11.3 | 8.8 | 11.1 | 11.2 | 10.3 | 10.7 | 9.0 | 11.1 | 11.7 |
| | जीएसटी ई-वे बिल्स (कुल) | 18.9 | 13.9 | 14.5 | 17.0 | 16.3 | 19.2 | 12.9 | 18.5 | 16.9 | 16.3 | 17.6 | 23.1 | 14.7 |
| | जीएसटी ई-वे बिल्स (अंतरा राज्य) | 21.1 | 15.8 | 17.3 | 18.9 | 16.4 | 19.0 | 13.1 | 19.0 | 18.3 | 5.4 | 17.9 | 23.3 | 14.9 |
| | जीएसटी ई-वे बिल्स (अंतर राज्य) | 15.0 | 10.7 | 9.6 | 13.6 | 16.3 | 19.6 | 12.5 | 17.7 | 14.4 | 44.1 | 17.1 | 22.8 | 14.4 |
| | होटल कमरा बुकिंग दर | 1.8 | 2.7 | -1.4 | -2.6 | -3.1 | 3.6 | 0.7 | 2.1 | -5.3 | 11.1 | -0.2 | 1.2 | |
| | प्रति कमरा औसत राजस्व | 7.8 | 6.7 | 4.8 | 1.8 | 2.8 | 7.6 | 5.2 | 3.5 | 4.8 | 10.7 | 8.9 | 8.7 | |
| | यात्री आगमन | 15.8 | 8.0 | 7.7 | 0.3 | 9.0 | -1.3 | -4.2 | 0.4 | -1.4 | -0.1 | -6.6 | | |
| विनिर्माण | इस्पात खपत | 7.3 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 21.1 | 13.8 | 10.3 | 10.9 | 8.8 | 8.9 | 7.7 | 9.1 | 11.2 |
| | सीमेंट उत्पादन | 7.8 | 10.6 | 0.2 | -0.6 | 1.8 | 5.1 | -2.5 | 7.6 | 3.1 | 13.5 | 4.6 | 14.5 | |
| पीएमआई सूचकांक# | सेवाएँ | 60.6 | 61.2 | 60.8 | 60.2 | 60.5 | 60.3 | 60.9 | 57.7 | 58.5 | 58.4 | 59.3 | 56.5 | 59.0 |

<<संकुचन----------------------------------------------------------- विस्तार>>

**टिप्पणी:** #: आंकड़े स्तरों में है। *: फरवरी 2025 के आंकड़े दैनिक आंकड़ों के मासिक औसत पर आधारित हैं। प्रत्येक संकेतक के लिए हीट-मैप जुलाई-2021 से अब तक की अवधि के लिए तैयार किया गया है।

**स्रोत:** एसआईएएम: रेल मंत्रालय: ट्रैक्टर और मशीनीकरण एसोसिएशन: भारतीय बंदरगाह संघ; आर्थिक सलाहकार कार्यालय: जीएसटीएन; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; एचवी-एस एनारॉक; पर्यटन मंत्रालय; संयुक्त संयंत्र समिति; और आईएचएस मार्किट।

**चार्ट III.33: सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और चालक**

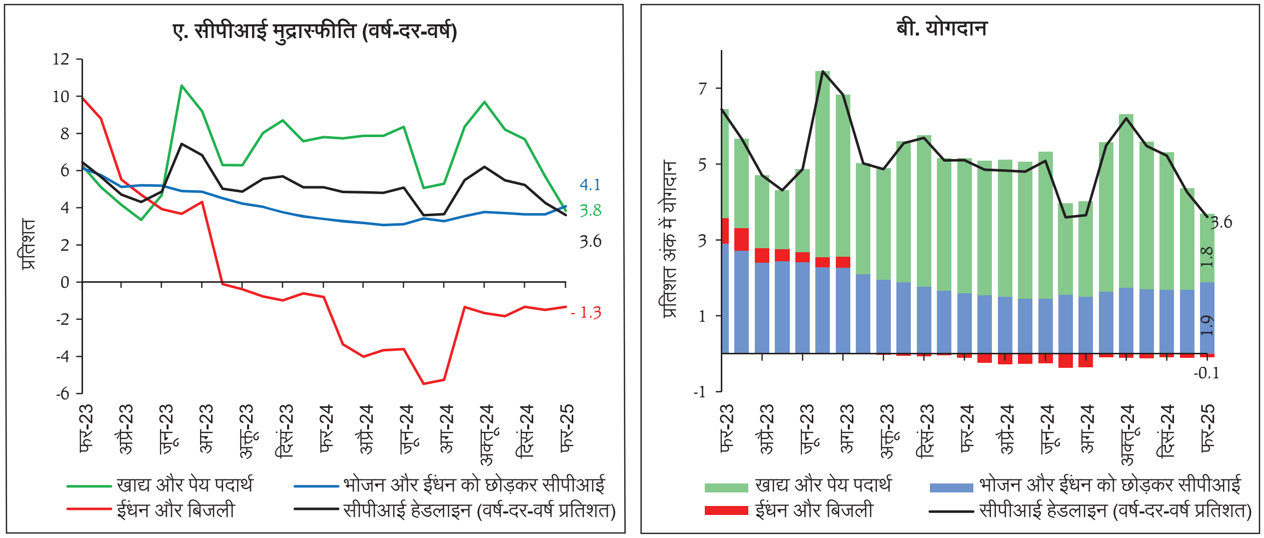


**स्रोत:** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

## मुद्रास्फीति

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)[17] में साल-दर-साल होने वाले बदलावों के आधार पर मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति' जनवरी में 4.3 प्रतिशत से फरवरी 2025 में घटकर सात महीने के निचले स्तर 3.6 प्रतिशत पर आ गई (चार्ट III.33)। मुद्रास्फीति में 70 बीपीएस की गिरावट लगभग 50 बीपीएस की ऋणात्मक मूल्य गति के कारण थी, जिसे लगभग 20 बीपीएस के अनुकूल आधार से और मदद मिली। खाद्य समूह ने महीने के दौरान लगभग (-)1.6 प्रतिशत की ऋणात्मक गति दर्ज की, जबकि सीपीआई ईंधन और कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) समूहों में गति क्रमशः 0.1 और 0.7 प्रतिशत पर धनात्मक रही।

फरवरी में खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी में 5.7 प्रतिशत से घटकर 3.8 प्रतिशत (वार्षिक) हो गई। उप-समूहों के संदर्भ में, सब्जियों, दालों और अंडों की कीमतों में तेज सुधार दर्ज किया गया और वे अपस्फीति क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जबकि अनाज, मांस और मछली, और दूध और उत्पादों में मुद्रास्फीति कम हुई। दूसरी ओर, तेल और वसा, फल, चीनी और मिष्ठान्न, गैर-अल्कोहल पेय और तैयार भोजन में मुद्रास्फीति बढ़ी। मसालों में अपस्फीति बनी रही, हालांकि यह कम दर पर रही (चार्ट III.34)।

ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर (-)1.3 प्रतिशत रह गई, जो जनवरी में (-)1.5 प्रतिशत थी। इसका कारण केरोसिन की कीमतों में कम अपस्फीति और बिजली की कीमतों में उच्च मुद्रास्फीति है। एलपीजी की कीमतों में अपस्फीति की स्थिर दर दर्ज की गई।

कोर मुद्रास्फीति जनवरी में 3.6 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी में 4.1 प्रतिशत हो गई। पान, तम्बाकू और मादक द्रव्यों, आवास, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार, तथा व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों में मुद्रास्फीति बढ़ी, जबकि यह कपड़े और जूते, घरेलू सामान और सेवाओं, मनोविनोद और मनोरंजन, और शिक्षा जैसे उप-समूहों में अपरिवर्तित रही (चार्ट III.35)।

क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, फरवरी 2025 में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति क्रमशः 3.8 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत तक कम हो गई। राज्य स्तर पर, मुद्रास्फीति दर 1.3 प्रतिशत से 7.3 प्रतिशत के बीच रही। अधिकांश राज्यों में मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से कम दर्ज की गई (चार्ट III.36)।

[17] राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 12 मार्च, 2025 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

**चार्ट III. 34: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) और गति (माह-दर-माह)**

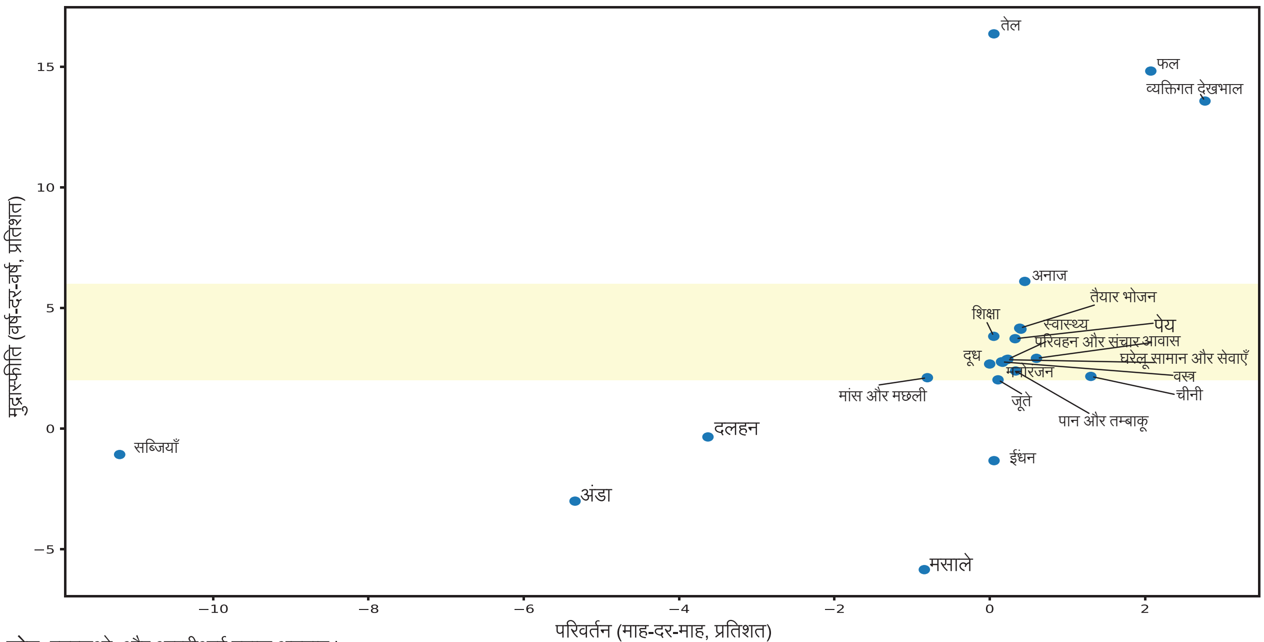


**स्रोत:** एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मार्च के लिए अब तक (17 तारीख तक) उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य डेटा चावल और गेहूं दोनों के लिए अनाज की कीमतों में वृद्धि दिखाते हैं। खाद्य तेल की कीमतों में भी मजबूती आई है - मुख्य रूप से पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल से। दूसरी ओर, दालों की कीमतों में व्यापक आधार पर नरमी जारी रही। आलू, प्याज और टमाटर सहित प्रमुख सब्जियों की कीमतों में और सुधार देखा गया (चार्ट III.37)।

**चार्ट III. 35: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (फरवरी 2025 बनाम जनवरी 2025)**

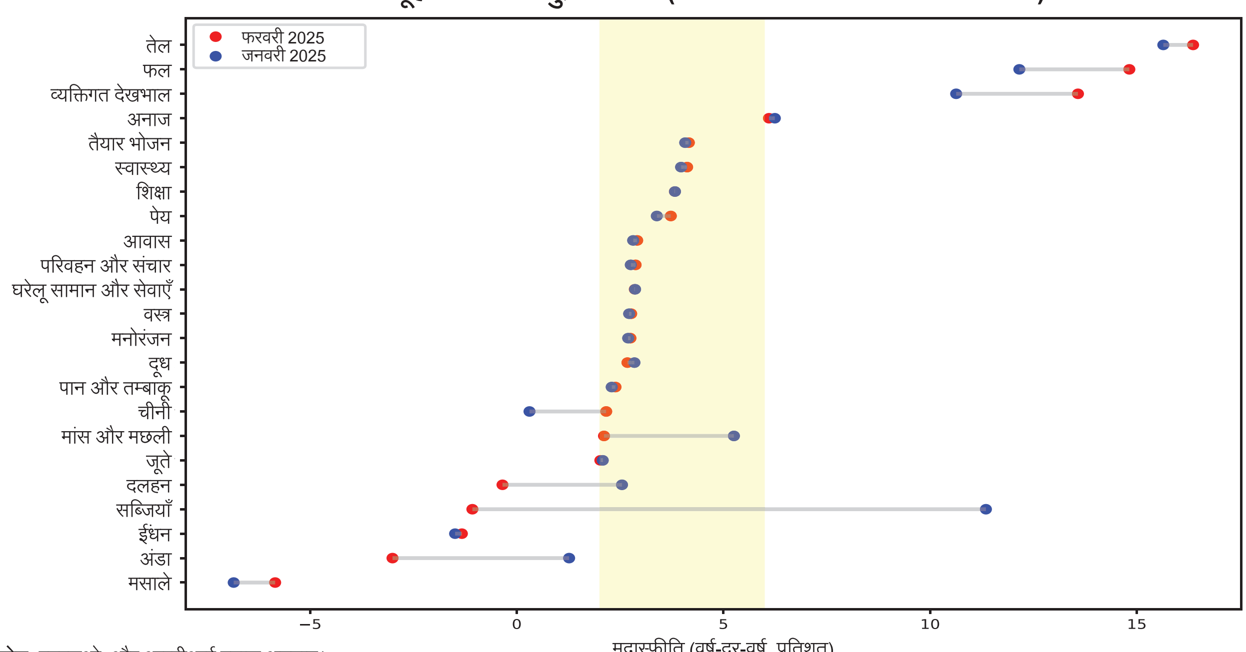


**स्रोत:** एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

**चार्ट III.36: मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण फरवरी 2025**

(सीपीआई-संयुक्त, वर्ष-दर-वर्ष), (प्रतिशत)

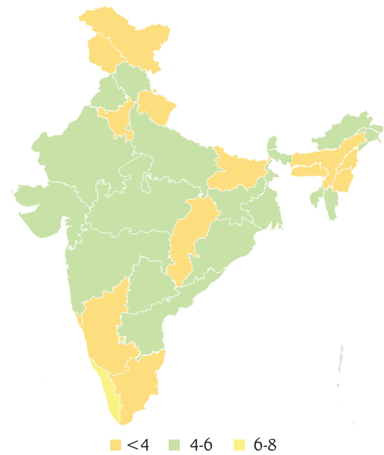


**टिप्पणी:** मानचित्र केवल उदाहरण के लिए है।
**स्रोत:** एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मार्च में अब तक पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खुदरा बिक्री कीमतें अपरिवर्तित रहीं (17 तारीख तक) जबकि केरोसिन की कीमतों में कमी आई (सारणी III.2)।

**सारणी III.2: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें**

| वस्तु | इकाई | घरेलू कीमतें | | | माह-दर-माह (प्रतिशत) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जन-25 | फर-25 | मार्च-25^ | फर-25 | मार्च-25^ |
| पेट्रोल | ₹/लीटर | 101.02 | 101.02 | 101.02 | 0.0 | 0.0 |
| डीज़ल | ₹/लीटर | 90.48 | 90.48 | 90.48 | 0.0 | 0.0 |
| केरोसीन (सब्सिडी वाला) | ₹/लीटर | 43.93 | 46.37 | 46.23 | 5.6 | -0.3 |
| एलपीजी (गैर-सब्सिडी) | ₹/सिलेंडर | 813.25 | 813.25 | 813.25 | 0.0 | 0.0 |

**टिप्पणी:** 1. ^: 1-17 मार्च, 2025 की अवधि के लिए।
2. केरोसिन के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। केरोसिन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाली कीमतों का औसत दर्शाती हैं।

**स्रोत:** आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

पीएमआई के अनुसार, फरवरी में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए इनपुट लागत में वृद्धि की दर धीमी रही। दूसरी ओर,

**चार्ट III.37: डीसीए आवश्यक वस्तु मूल्य**

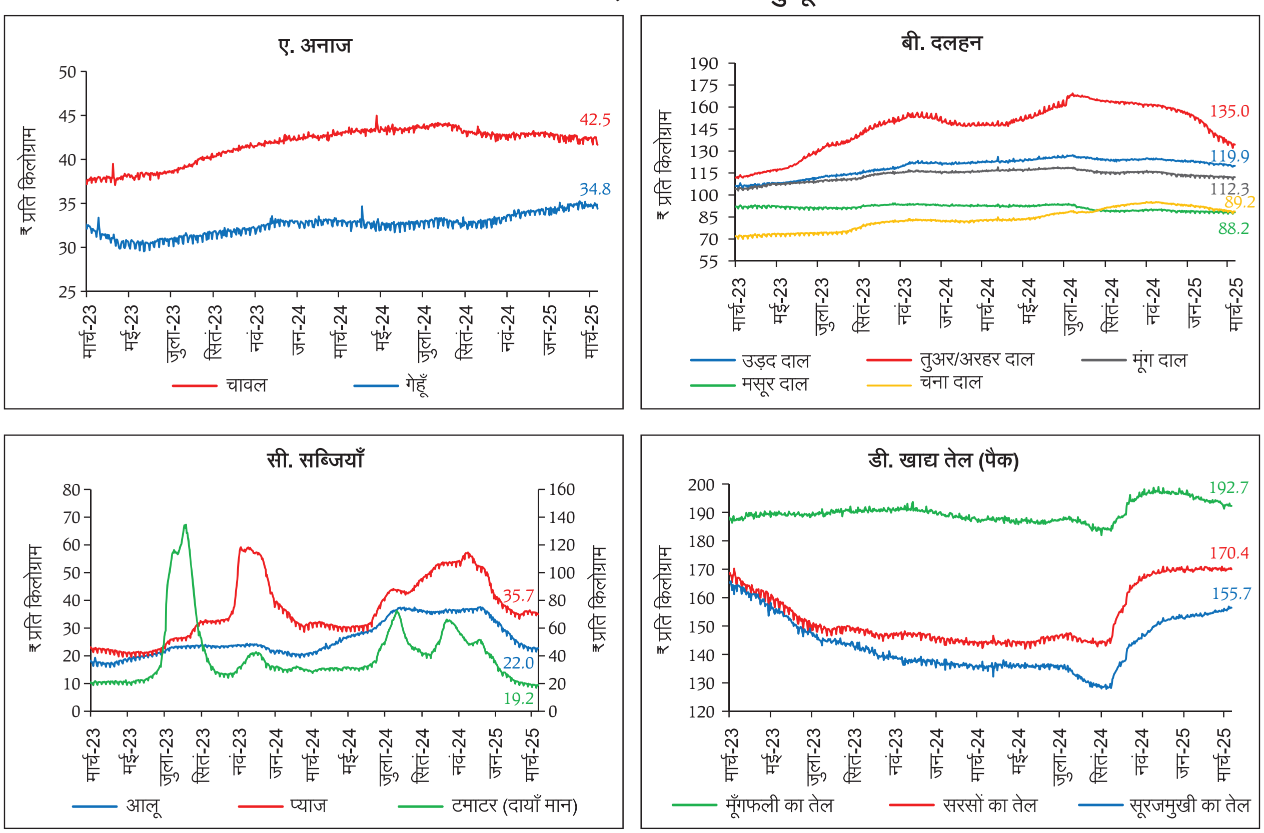


**स्रोत:** उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

**चार्ट III.38: पीएमआई: इनपुट और आउटपुट मूल्य**

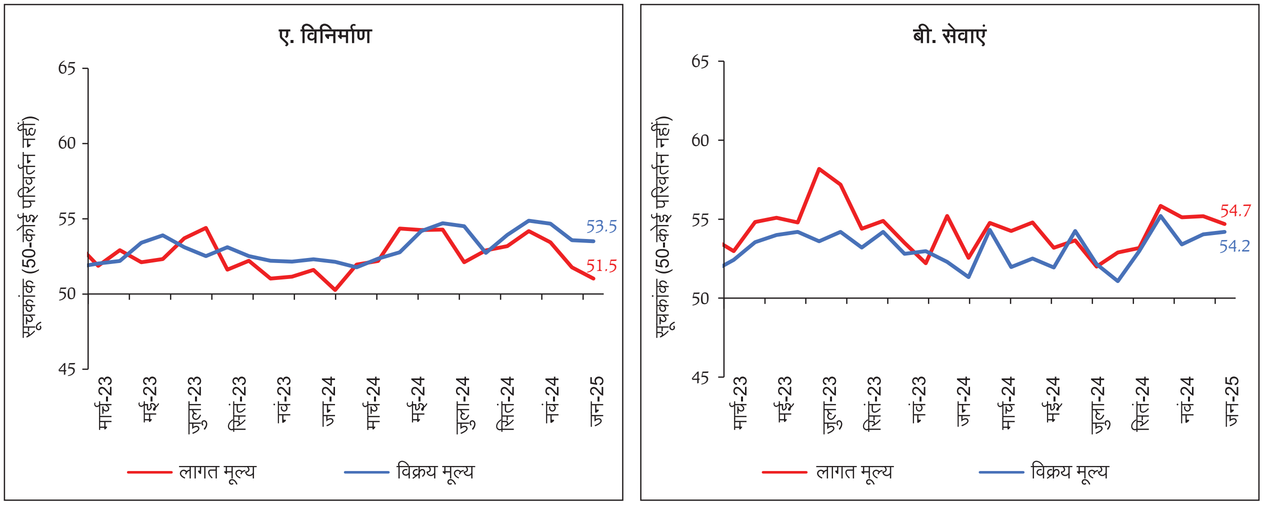


**टिप्पणी:** 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने को दर्शाता है तथा 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।
**स्रोत:** एस एंड पी।

विनिर्माण फर्मों में बिक्री मूल्य दबाव मामूली रूप से कम हुआ, लेकिन सेवा फर्मों के लिए बढ़ा (चार्ट III.38)।

दस प्रमुख शहरों से संपत्ति पंजीकरण डेटा के आधार पर अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) में 2024-25 की तीसरी तिमाही में 3.1 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि पिछली तिमाही में यह 4.3 प्रतिशत और एक वर्ष पहले 3.8 प्रतिशत थी (चार्ट III.39)।

**चार्ट III.39: आवास मूल्य सूचकांक की गति**

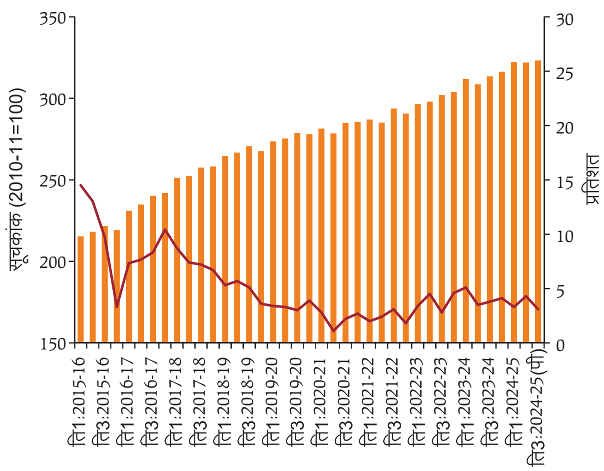


**टिप्पणी:** ति3:2024-25 (पी) आंकड़े अनंतिम हैं।
**स्रोत:** राज्य सरकारों के पंजीकरण प्राधिकरण; और आरबीआई।

## IV. वित्तीय स्थिति

प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) में मौसमी तेजी के बीच फरवरी के उत्तरार्ध और मार्च की शुरुआत (13 मार्च, 2025 तक) में सिस्टम चलनिधि घाटे में रही। फरवरी के मध्य से, रिज़र्व बैंक ने टिकाऊ चलनिधि अंतर्वेशित करने के लिए ₹1.4 लाख करोड़ की संचयी राशि की तीन ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) खरीद नीलामी (20 फरवरी, 12 मार्च और 18 मार्च 2025 को) और 21 फरवरी 2025 को ₹57,951 करोड़ की 45-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित की। इसके अतिरिक्त, 28 फरवरी 2025 को 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की तीन वर्षीय यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी के माध्यम से रुपये की चलनिधि अंतर्वेशित की गई। अब तक की तिमाही के दौरान, रिज़र्व बैंक ने ओएमओ खरीदों, लंबी अवधि की वीआरआर नीलामी और विदेशी मुद्रा विनिमय स्वैप के संयोजन के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹5.5 लाख करोड़ की टिकाऊ चलनिधि अंतर्वेशित की है (सारणी IV.1)।

इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक चलनिधि की क्षणिक तंगी से निपटने के लिए 16 जनवरी से दैनिक वीआरआर नीलामी आयोजित कर रहा है, जिसमें स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को इन दैनिक नीलामियों में भाग लेने की अनुमति दी जा रही है। 16 फरवरी से 17 मार्च 2025 के दौरान 1 से 8 दिनों

**सारणी IV.1: 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान टिकाऊ चलनिधि उपाय**

| उपाय | विवरण | नीलामी की तारीख | अंतर्वेशित राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| ओएमओ खरीद | एनडीएस-ओएम के माध्यम से | जनवरी 2025 | 38,825 |
| ओएमओ खरीद नीलामी | | जनवरी 30, 2025<br>फरवरी 13, 2025<br>फरवरी 20, 2025<br>मार्च 12, 2025<br>मार्च 18, 2025 | 20,020<br>40,000<br>40,000<br>50,000<br>50,000 |
| मीयादी रेपो नीलामी | 56-दिवसीय वीआरआर नीलामी<br>49-दिवसीय वीआरआर नीलामी<br>45-दिवसीय वीआरआर नीलामी | फरवरी 07, 2025<br>फरवरी 14, 2025<br>फरवरी 21, 2025 | 50,010<br>75,003<br>57,951 |
| यूएसडी/आईएनआर खरीद बिक्री स्वैप नीलामी | अवधि: 6 महीने<br>अवधि: 3 वर्ष | जनवरी 31, 2025<br>फरवरी 28, 2025 | लगभग. 44,000 (यूएसडी 5.10 बिलियन)<br>लगभग. 88,000 (यूएसडी 10.06 बिलियन) |
| | | **कुल** | **लगभग. 5,53,809** |

**स्रोत**: आरबीआई।

तक की परिपक्वता अवधि के दो मुख्य और 22 फाइन-ट्यूनिंग वीआरआर आयोजन के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में 9.68 लाख करोड़ रुपये की कुल राशि अंतर्वेशित की गई। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए इन उपायों से चलनिधि घाटे को कम करने में सहायता मिली। परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक शुद्ध अंतर्वेशन 16 फरवरी से 13 मार्च 2025 के दौरान 1.41 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि 16 जनवरी से 15 फरवरी 2025 के दौरान यह 1.92 लाख करोड़ रुपये था (चार्ट IV.1)।

प्रचलित चलनिधि घाटे के बावजूद, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत बैंकों का धन-स्थानन 16 फरवरी 2025 और 13 मार्च 2025 के बीच औसतन 1.15 लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले महीने में 0.85 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। एसडीएफ के तहत चलनिधि घाटे की स्थिति और पर्याप्त धन-स्थानन का सह-अस्तित्व बैंकिंग प्रणाली के भीतर तरलता के असममित वितरण के साथ-साथ बैंकों की ओर से बढ़ी हुई तरलता वरीयता का संकेत देता है। इस बीच, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

**चार्ट IV.1 : चलनिधि परिचालन**

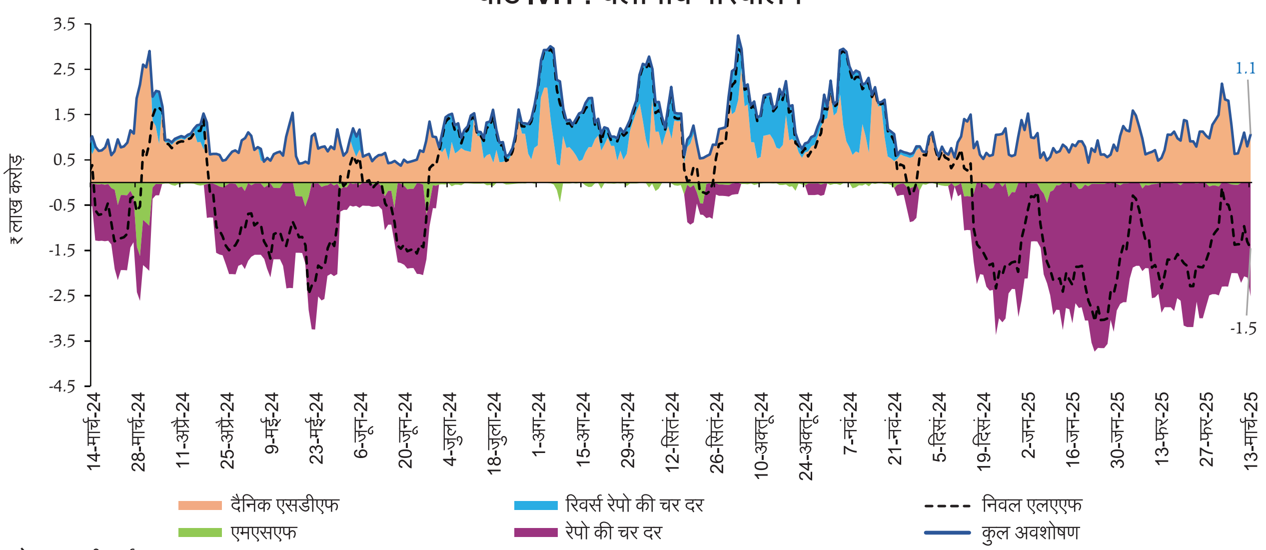


**स्रोत:** आरबीआई।

के तहत दैनिक औसत उधार 16 फरवरी 2025 और 13 मार्च 2025 के दौरान मामूली रूप से घटकर 0.03 लाख करोड़ रुपये रह गया, जो पिछली अवधि में 0.04 लाख करोड़ रुपये था।

भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - नीतिगत कॉरिडोर के भीतर रही और 16 फरवरी और 13 मार्च 2025 के दौरान डब्ल्यूएसीआर का नीतिगत रेपो दर पर औसत प्रसार 5 आधार अंक (bps) रहा, जो 16 जनवरी से 15 फरवरी, 2025 के जैसा ही था (चार्ट IV.2ए)। हालाँकि, चलनिधि की स्थिति में सुधार के बीच, संपार्श्विक खंड में दरें, नीतिगत रेपो दर से नीचे रहीं।

समूचे मीयादी मुद्रा बाजार खंड में, 3 महीने के ट्रेजरी बिल (टी-बिल) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी 3 महीने के वाणिज्यिक पेपर (सीपी) पर प्रतिफल के साथ दरों में गिरावट आई है, जो पिछले महीने की तुलना में 16 फरवरी - 13 मार्च 2025 के दौरान कम हुई है (चार्ट IV.2 बी)। हालांकि, इसी अवधि के दौरान जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर प्रतिफल 7.49 प्रतिशत से बढ़कर 7.52 प्रतिशत हो गई। मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3 महीने की सीपी [एनबीएफसी] माइनस 91-दिवसीय टी-बिल) 18 जनवरी - 14 फरवरी 2025 के 137 बीपीएस से बढ़कर 16 फरवरी - 13 मार्च 2025 के दौरान 142 बीपीएस हो गया।

सीपी की भारित औसत छूट दर (डब्ल्यूएडीआर) और सीडी की भारित औसत प्रभावी ब्याज दर (डब्ल्यूएईआईआर) एक वर्ष पहले दर्ज किए गए स्तरों से कम रही (चार्ट IV.3)।

**चार्ट IV.2: नीति कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दर**

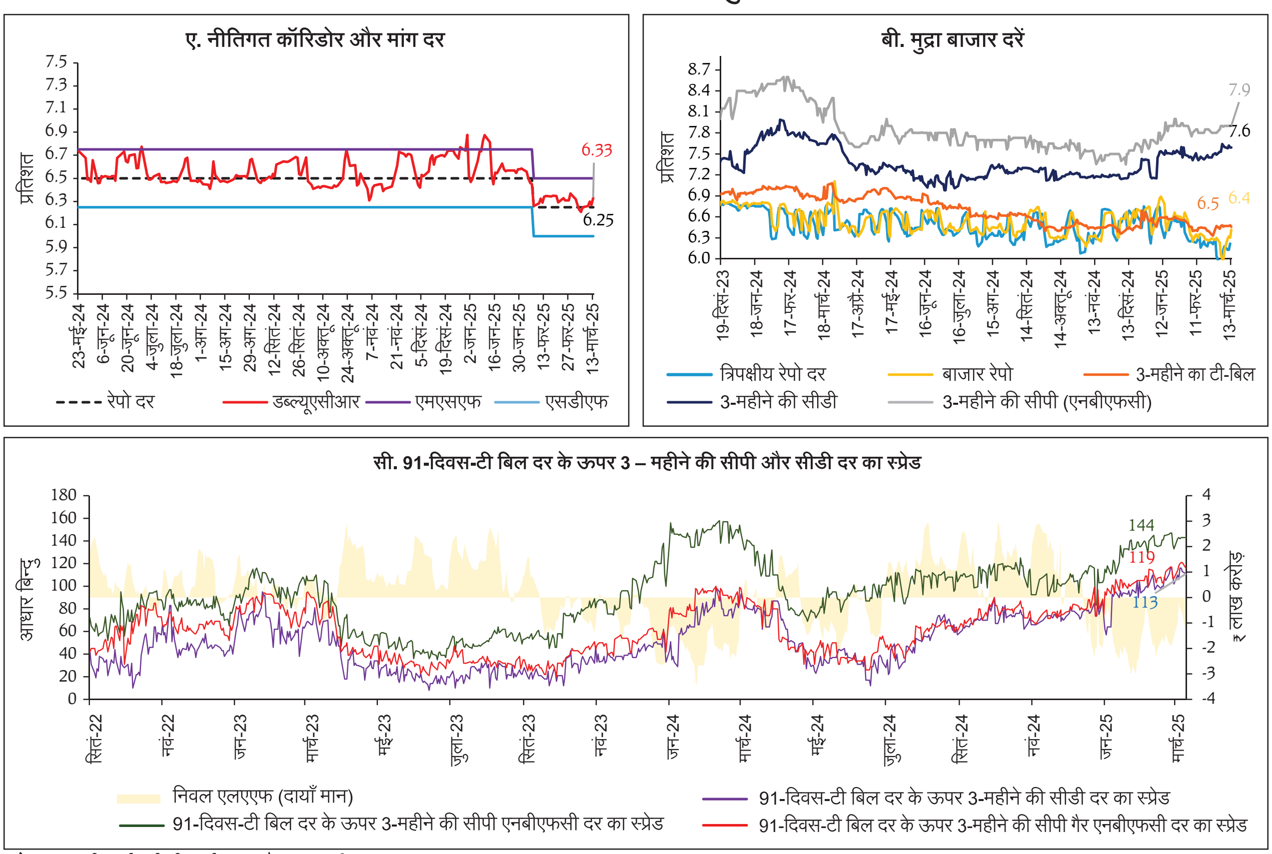


**स्रोत:** आरबीआई; सीसीआईएल; और ब्लूमबर्ग

**चार्ट IV.3: डब्ल्यूएडीआर और डब्ल्यूएईआईआर**

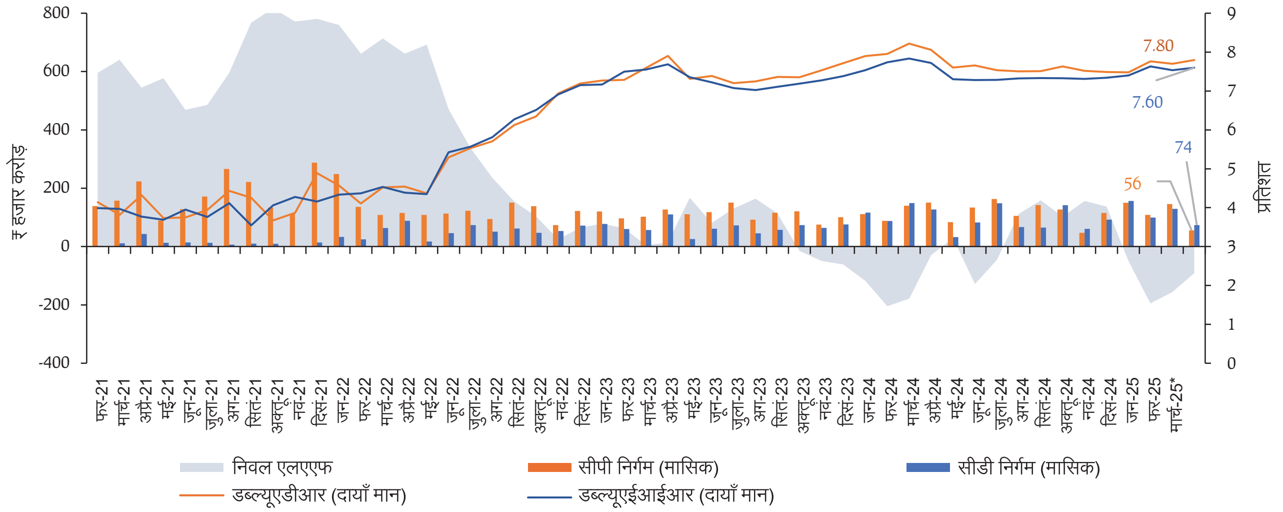


**टिप्पणी*:** 10 मार्च, 2025 तक।
**स्रोत:** आरबीआई; और सीसीआईएल-एफटीआरएसी।

ऋण और जमा वृद्धि में निरंतर अंतर के कारण, बैंक अपनी वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीडी पर निर्भर बने हुए हैं। प्राथमिक बाजार में, सीडी निर्गम 2024-25 (7 मार्च 2025 तक) के दौरान 34 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹10.58 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया [चार्ट IV.4]। इसी प्रकार, 2024-25 (28 फरवरी 2025 तक) के दौरान सीपी निर्गम ₹13.90 लाख करोड़ रहा, जो एक वर्ष पूर्व की इसी अवधि की तुलना में 13.5 प्रतिशत अधिक है।

10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के बेंचमार्क पर प्रतिफल व्यापक स्तर पर सीमित दायरे में रहा और 14 फरवरी 2025 के 6.71 प्रतिशत की तुलना में 13 मार्च 2025 को 6.70 प्रतिशत

**चार्ट IV.4: जमा प्रमाणपत्र (सीडी) एवं वाणिज्यिक पत्र (सीपी) – पाक्षिक निर्गम**

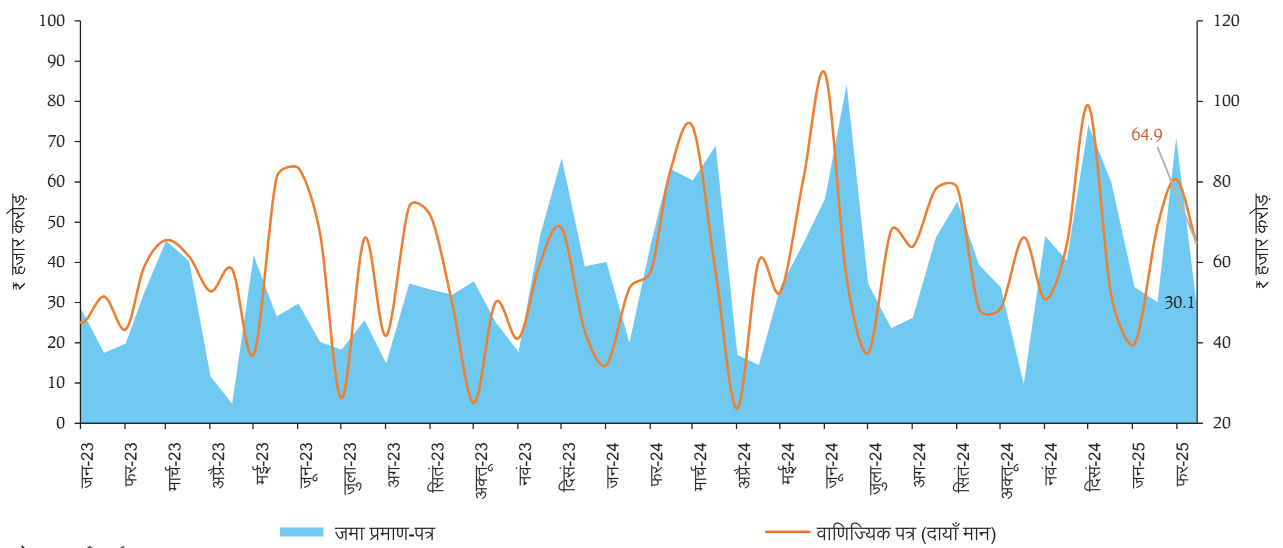


**स्रोत:** आरबीआई।

**चार्ट IV.5: सरकारी प्रतिभूति बाजार में विकास**

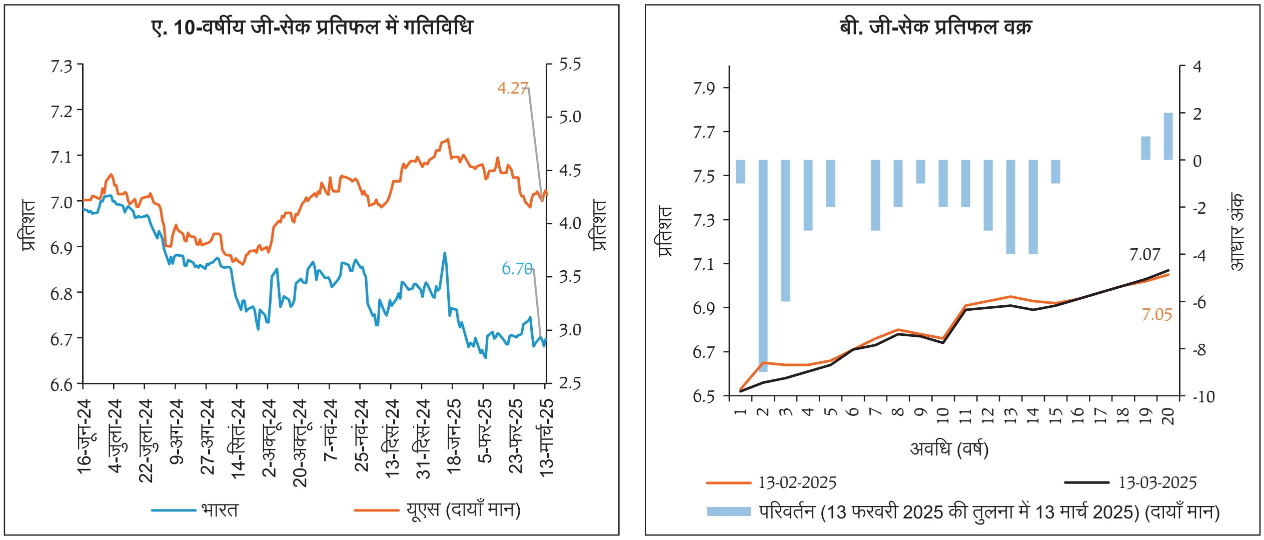


**स्रोत:** ब्लूमबर्ग; सीसीआईएल और आरबीआई स्टाफ आकलन।

रहा (चार्ट IV.5ए)। घरेलू प्रतिफल वक्र अति लघु और मध्यम अवधि-खंडों में नरम हुआ, जबकि अन्य सभी अवधियों के लिए यह स्थिर रहा (चार्ट IV.5बी)। 16 फरवरी और 13 मार्च 2025 के बीच, औसत अवधि प्रसार (10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल माइनस 91-दिवसीय टी-बिल प्रतिफल) में पिछली अवधि की तुलना में 8 आधार अंकों की वृद्धि हुई।

फरवरी के उत्तरार्ध में, 10-वर्षीय भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल का 10-वर्षीय अमेरिकी बॉण्ड पर प्रसार बढ़ गया, जिसका मुख्य कारण अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल में गिरावट थी। अमेरिकी ट्रेज़री की तुलना में भारत में प्रतिफल की अस्थिरता कम रही (चार्ट IV.6)।

2024-25 (जनवरी तक) के दौरान ₹7.94 लाख करोड़ के कॉरपोरेट बॉण्ड जारी किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.0

**चार्ट IV.6 : अस्थिरता और स्प्रेड-बॉण्ड बाजार**

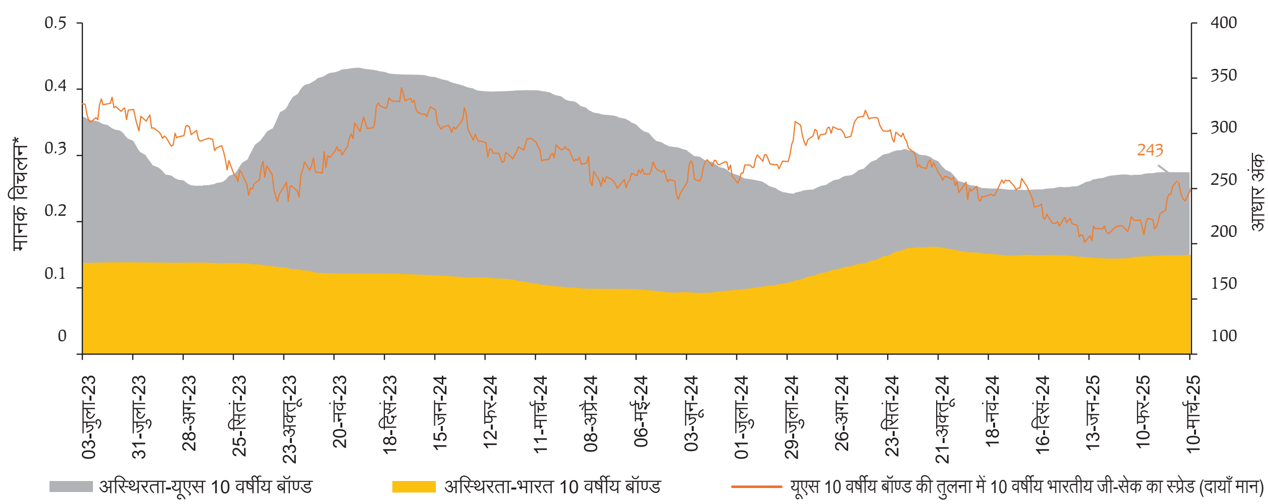


**टिप्पणी:** *: 12 मासिक रोलिंग मानक विचलन।
**स्रोत:** ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ आकलन।

**सारणी IV.2: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड**

| लिखत | ब्याज दरें (प्रतिशत) | | | स्प्रेड (बीपीएस) (संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जन 16, 2025 – फर 15, 2025 | फर 16, 2025 – मार्च 12, 2025 | विभिन्नता | जन 16, 2025 – फर 15, 2025 | फर 16, 2025 – मार्च 12, 2025 | विभिन्नता |
| 1 | 2 | 3 | (4 = 3-2) | 5 | 6 | (7 = 6-5) |
| **कॉरपोरेट बॉण्ड** | | | | | | |
| (i) एएए (1 वर्ष) | 7.87 | 7.86 | -1 | 116 | 122 | 6 |
| (ii) एएए (3 वर्षीय) | 7.64 | 7.67 | 3 | 90 | 97 | 7 |
| (iii) एएए (5 वर्षीय) | 7.50 | 7.62 | 12 | 73 | 85 | 12 |
| (iv) एए (3 वर्षीय) | 8.43 | 8.44 | 1 | 169 | 175 | 6 |
| (v) बीबीबी- (3 वर्ष) | 12.10 | 12.09 | -1 | 536 | 540 | 4 |

**टिप्पणी:** प्रतिफल और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के लिए औसत के रूप में की जाती है।
**स्रोत:** एफआईएमएमडीए; और ब्लूमबर्ग।

प्रतिशत अधिक थे। कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल में मिश्रित रुझान देखने को मिले, जबकि फरवरी के उत्तरार्ध से 12 मार्च 2025 तक सभी रेटिंग और अवधि-स्पेक्ट्रम में संबंधित जोखिम प्रीमियम में वृद्धि हुई (सारणी IV.2)।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में बदलाव के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, आरक्षित मुद्रा (आरएम) में 7 मार्च 2025 तक 6.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई (एक वर्ष पूर्व 5.5 प्रतिशत) [चार्ट IV.7]। आरक्षित मुद्रा के सबसे बड़े घटक, सीआईसी में 7 मार्च 2025 तक 5.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि रही, जबकि एक वर्ष पूर्व यह 3.5 प्रतिशत थी।

स्रोत पक्ष (परिसंपत्तियाँ) पर, आरक्षित मुद्रा में रिज़र्व बैंक की निवल घरेलू परिसंपत्तियाँ (एनडीए) और निवल विदेशी परिसंपत्तियाँ (एनएफए) शामिल हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में जनवरी 2025 की समाप्ति के 1.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) से बढ़कर 7 मार्च 2025 को 3.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट IV.8)। स्वर्ण- एनएफए का एक अन्य प्रमुख घटक - मुख्य रूप से सोने की कीमतों में पुनर्मूल्यांकन लाभ के कारण 53.8 प्रतिशत

**चार्ट IV.7: आरक्षित धन और प्रचलन में मुद्रा**

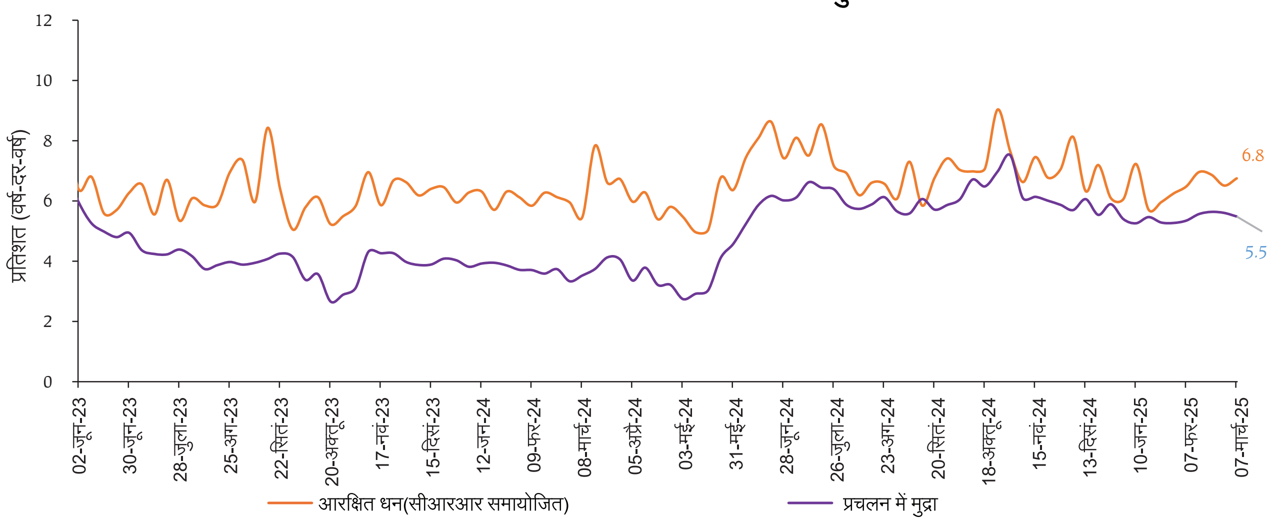


**टिप्पणी:** आरक्षित धन के लिए नवीनतम डाटा 07 मार्च 2025 से संबंधित है।
**स्रोत:** आरबीआई

**चार्ट IV.8: आरबीआई की निवल विदेशी आस्तियों (एनएफए) की वृद्धि**

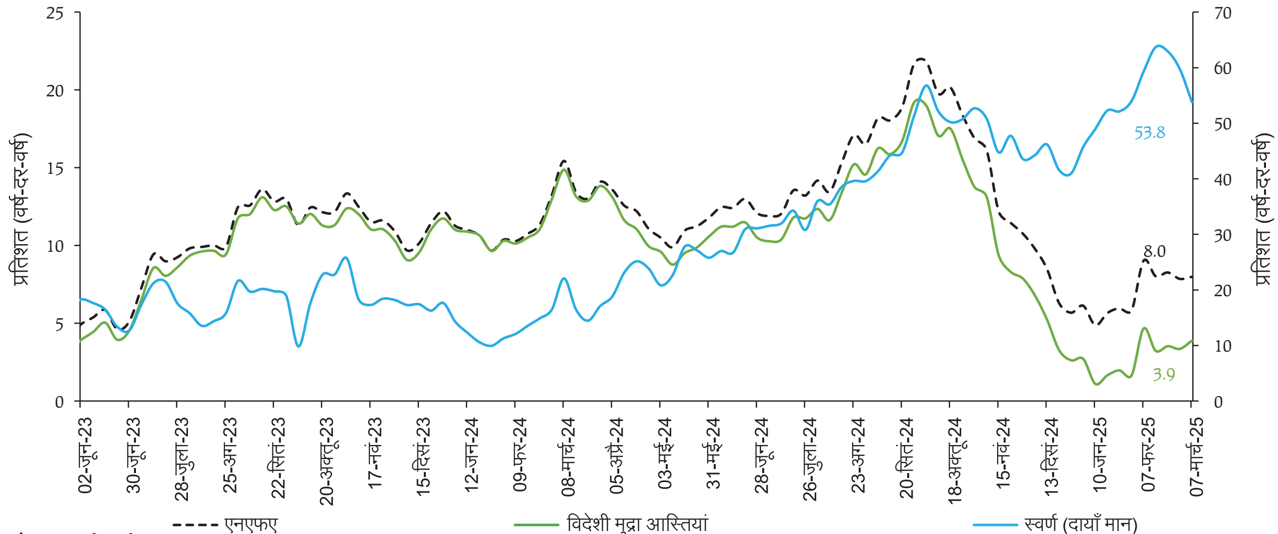


**स्रोत**: आरबीआई।

बढ़ा, जिससे एनएफए में इसकी हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत के 8.3 प्रतिशत से बढ़कर 7 मार्च 2025 तक 11.7 प्रतिशत हो गई।

21 फरवरी 2025 तक, मुद्रा आपूर्ति (एम$_3$) में 9.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (एक वर्ष पूर्व 10.9 प्रतिशत)।[18] बैंकों के पास कुल जमा (जो एम$_3$ का लगभग 86 प्रतिशत है) में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (एक वर्ष पूर्व 11.9 प्रतिशत)। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण 21 फरवरी 2025 तक 12.0 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 16.6 प्रतिशत) तक कम हो गई, जो आंशिक रूप से सकारात्मक गति से संतुलित हुई (चार्ट IV.9)।

**चार्ट IV.9: एम$_3$ वृद्धि और एससीबी की ऋण वृद्धि - आधार और गति प्रभाव**

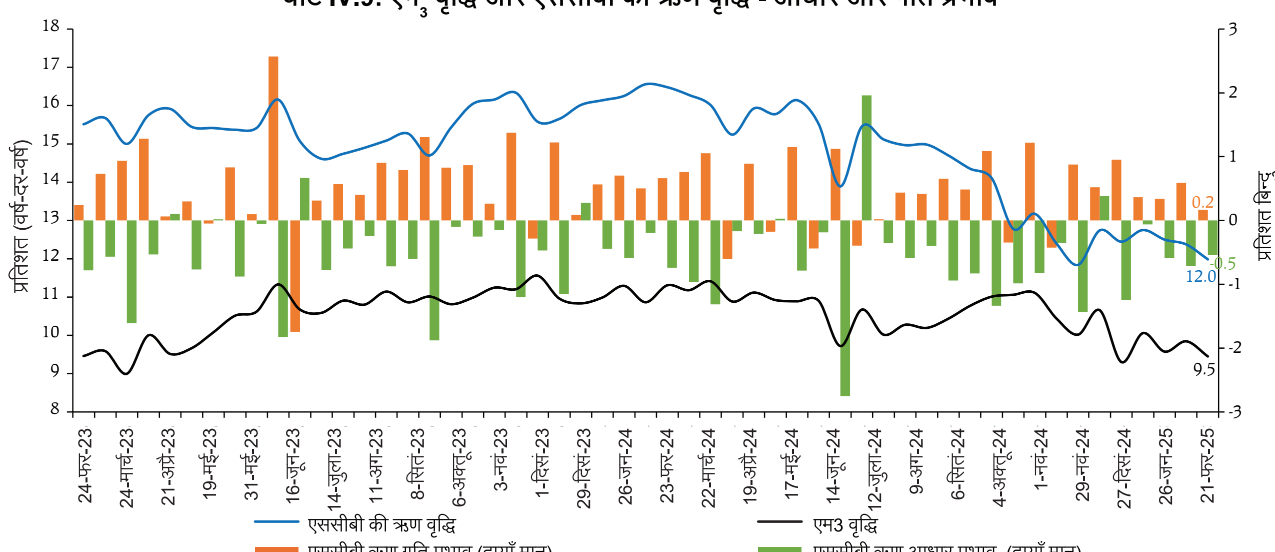


**स्रोत**: आरबीआई।

[18] किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई 2023 से लागू)

**चार्ट IV.10: बैंक ऋण में वार्षिक वृद्धि - प्रमुख क्षेत्र**

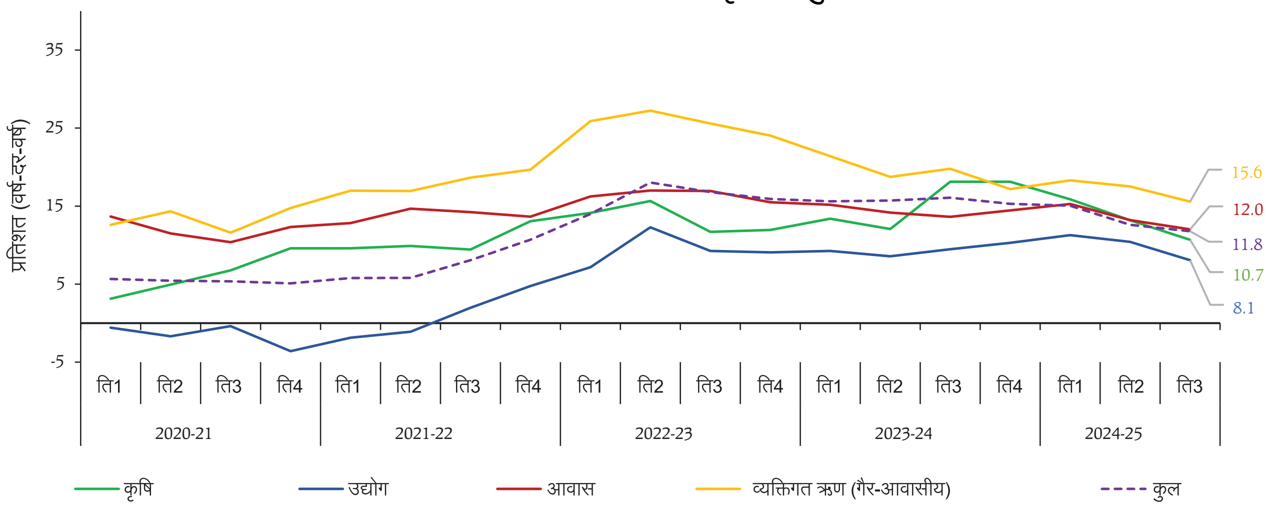


**टिप्पणी:** तुलनात्मकता के लिए 2023-24 की दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही और 2024-25 की पहली तिमाही के वृद्धि आँकड़ों की एक बैंक के साथ गैर बैंक के विलय को समायोजित कर गणना की गई है।
**स्रोत:** आरबीआई।

नवीनतम उपलब्ध तिमाही आंकड़ों के आधार पर, 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हालिया मंदी के बावजूद, ऋण में अच्छी गति से वृद्धि जारी है (चार्ट IV.10)। नवंबर 2023 में घोषित जोखिम भार में वृद्धि के बाद असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण खंड में कमी आने के बावजूद भी व्यक्तिगत ऋण खंड में ऋण वृद्धि समग्र ऋण विस्तार की अग्रणी चालक रही।

निजी कॉरपोरेट क्षेत्र को एससीबी द्वारा दिए गए ऋण (जो कुल बैंक ऋण का लगभग एक-चौथाई हिस्सा था), 2024-25 की तीसरी तिमाही में कम हुआ। हालाँकि, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को दिए गए ऋण में वृद्धि जारी रही (चार्ट IV.11ए)। कार्यशील पूँजी ऋणों में वृद्धि में तेज़ी आई, जो आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी का संकेत है (चार्ट IV.11बी)।

**चार्ट IV.11: वार्षिक ऋण वृद्धि**

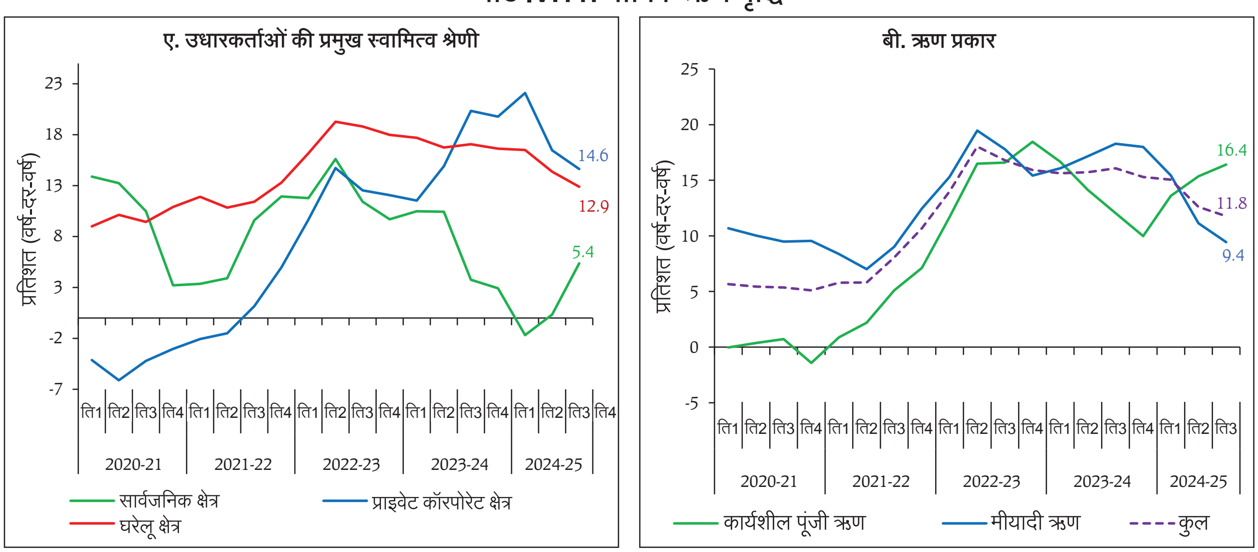


**स्रोत:** आरबीआई।

**चार्ट IV.12: एससीबी की जमा वृद्धि - आधार और गति प्रभाव**

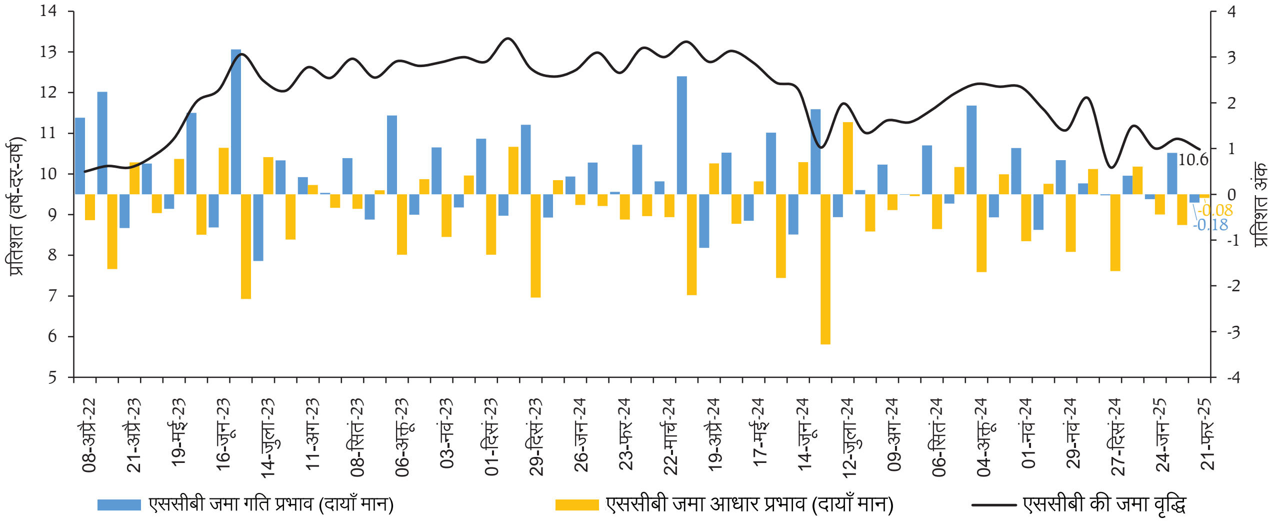


**स्रोत:** आरबीआई

21 फरवरी 2025 तक, एससीबी की जमा वृद्धि (विलय के प्रभाव को छोड़कर) जनवरी 2025 के अंत के 10.6 प्रतिशत के स्तर पर बनी रही (चार्ट IV.12)।

2024-25 की तीसरी तिमाही में सावधि जमाओं की वृद्धि बचत जमाओं की वृद्धि से आगे निकलती रही (चार्ट IV.13)। परिणामस्वरूप, कुल जमाओं में सावधि जमाओं का हिस्सा एक वर्ष पूर्व के 60.3 प्रतिशत से बढ़कर 62.1 प्रतिशत हो गया।

7 प्रतिशत या उससे अधिक ब्याज दर वाली जमाओं का हिस्सा (कुल सावधि जमाओं में) दिसंबर 2023 के 61.4 प्रतिशत और मार्च 2023 के 33.7 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2024 में 70.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.14)।

**चार्ट IV.13: कुल जमाराशियों में वार्षिक वृद्धि – जमा के प्रकार**

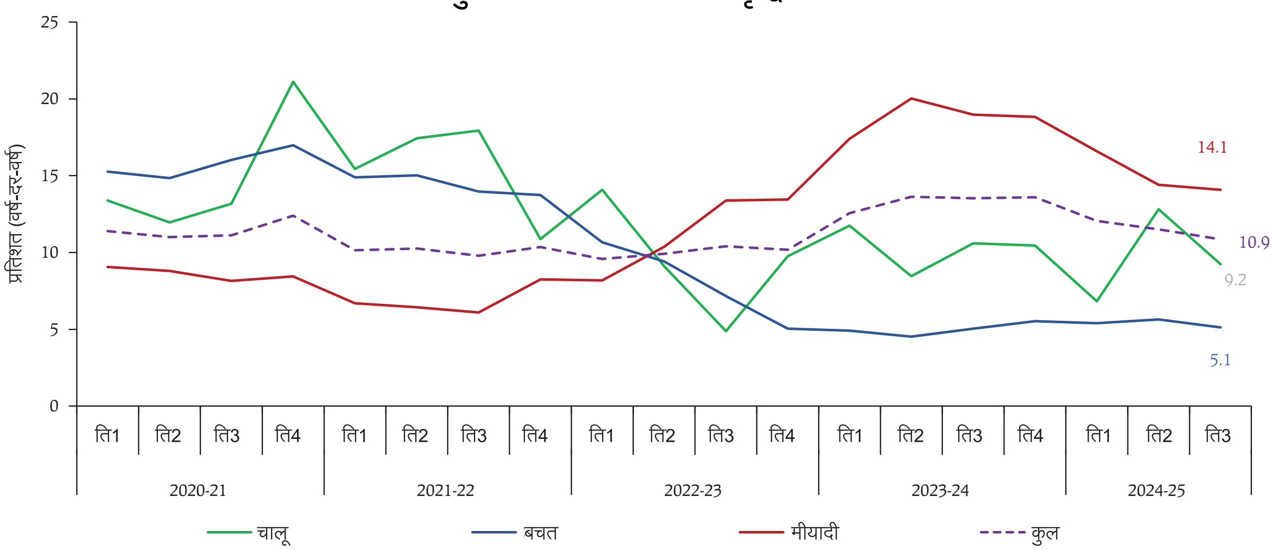


**स्रोत:** आरबीआई

**चार्ट IV.14: बैंकों की मीयादी जमाराशियों का ब्याज दर वार हिस्सा**

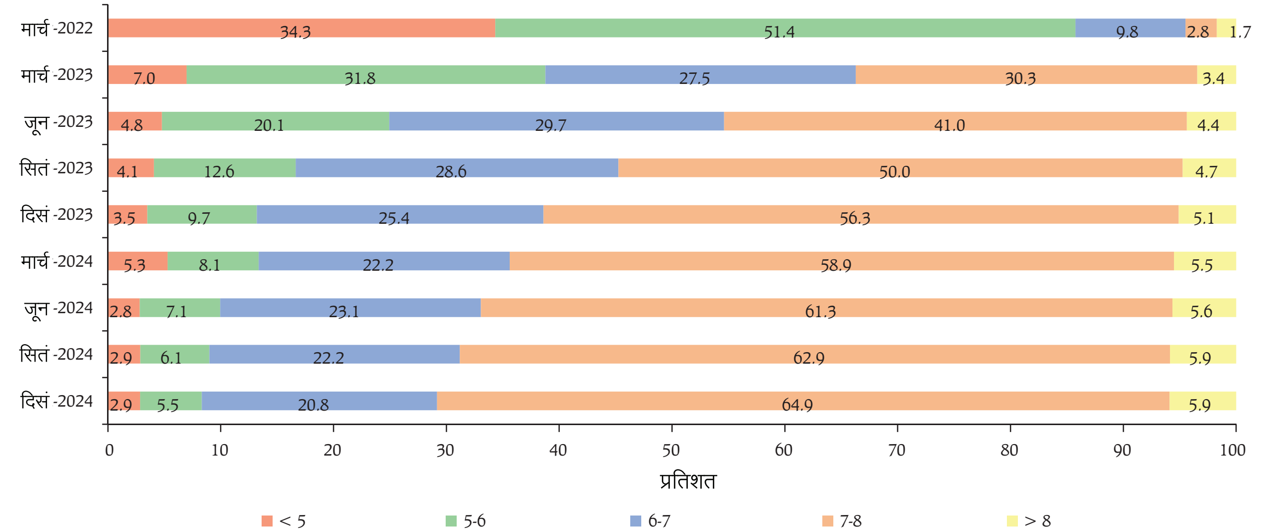


**स्रोत**: आरबीआई

एससीबी का वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात अक्टूबर 2024 के अंत में 80.7 प्रतिशत से बढ़कर 21 फरवरी 2025 तक 88.2 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.15)।

फरवरी पॉलिसी के दौरान पॉलिसी रेपो दर में 25-बीपीएस की कटौती के जवाब में, बैंकों ने अपनी रेपो-लिंक्ड एक्सटर्नल बेंचमार्क-आधारित उधार दरों (ईबीएलआर) को समान परिमाण से कम कर दिया है। एससीबी की 1-वर्षीय सीमांत लागत-आधारित उधार दरों (एमसीएलआर) में मई 2022 से जनवरी 2025 के दौरान 178 बीपीएस की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में क्रमशः 181 बीपीएस और 115 बीपीएस की वृद्धि हुई (चार्ट IV.16ए)। जमा के मामले में, एससीबी की नई जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर),

**चार्ट IV.15 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात**

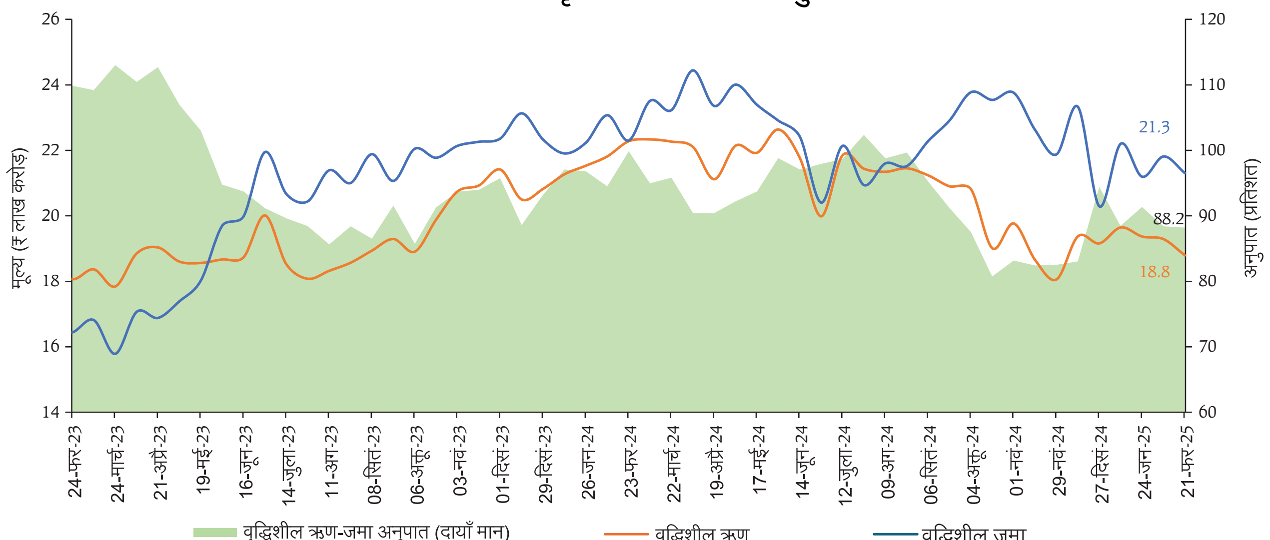


**स्रोत**: आरबीआई

**चार्ट IV.16: बैंकों की उधार और जमा दरों में संचरण**

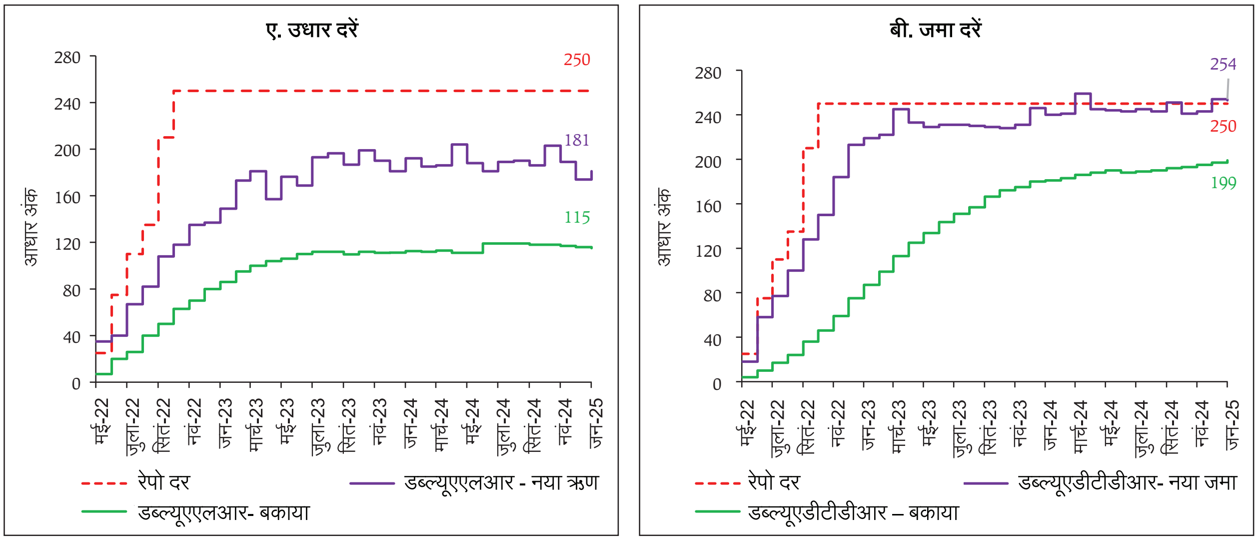


**स्रोत**: आरबीआई

जिसमें खुदरा और थोक जमा दोनों शामिल हैं, में 253 बीपीएस की वृद्धि हुई। बकाया जमा पर डब्ल्यूएडीटीडीआर भी मई 2022 से जनवरी 2025 के दौरान 199 बीपीएस बढ़ गई (चार्ट IV.16बी)।

बैंक समूहों में संचरण से संकेत मिलता है कि नए रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर में वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की तुलना में अधिक थी। हालाँकि, बकाया रुपया ऋणों के मामले में, पीएसबी में संचरण कम था। दूसरी ओर, मई 2022 से जनवरी 2025 के दौरान पीएसबी के लिए जमा दरों में संचरण अधिक था (चार्ट IV.17ए और बी)।

2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान सुस्त प्रदर्शन के बाद, कॉरपोरेट क्षेत्र में तीसरी तिमाही के दौरान सुधार के संकेत दिखाई दिए। 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान सूचीबद्ध

**चार्ट IV.17: बैंक समूहों के बीच संचरण (मई 2022 से जनवरी 2025)**

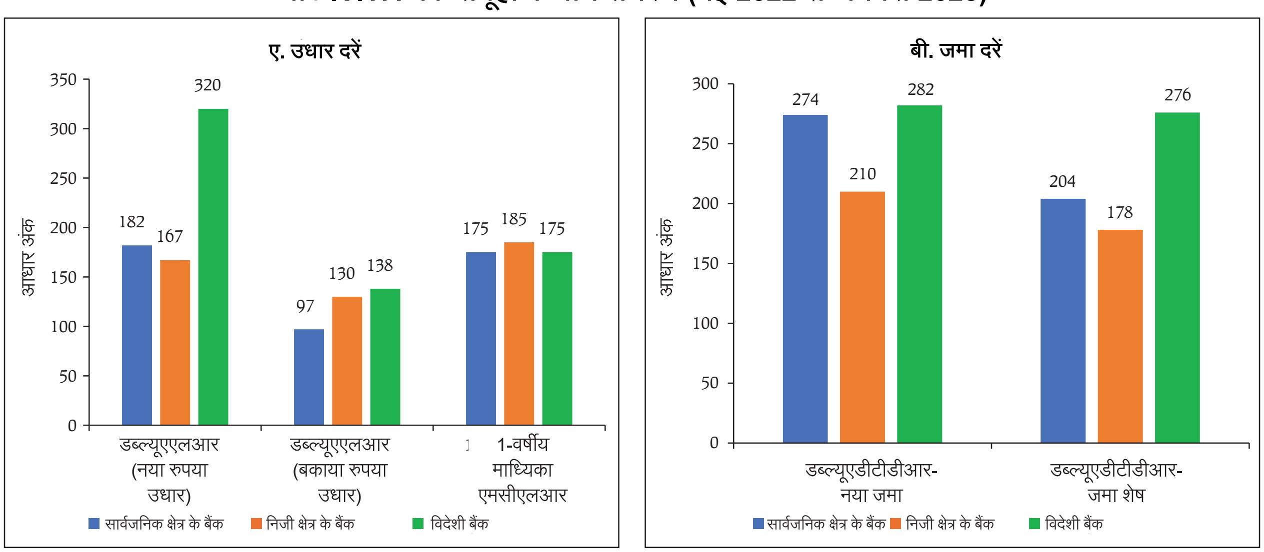


**स्रोत**: आरबीआई

निजी गैर-वित्तीय कंपनियों की बिक्री 8.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी, जो पिछली तिमाही के 5.4 प्रतिशत और एक वर्ष पहले की इसी तिमाही के 5.5 प्रतिशत से बेहतर है।

2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों की बिक्री वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) में सुधार हुआ (चार्ट IV.18)। वृद्धि में यह बदलाव मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, रसायन, खाद्य उत्पाद और विद्युत मशीनरी उद्योगों में बढ़ी बिक्री के कारण हुआ, जबकि पेट्रोलियम, लोहा एवं इस्पात, और सीमेंट उद्योगों की बिक्री में तीसरी तिमाही के दौरान वार्षिक आधार पर गिरावट जारी रही, हालाँकि गिरावट की गति धीमी रही (चार्ट IV.19)।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र ने पिछली तिमाही और एक साल पहले की तुलना में बेहतर बिक्री वृद्धि दर्ज की। गैर-आईटी सेवा कंपनियों की बिक्री वृद्धि में मंदी के बावजूद दोहरे अंकों में वृद्धि जारी रही। यह वृद्धि मुख्य रूप से 'थोक और खुदरा व्यापार' और 'परिवहन एवं भंडारण सेवाएँ' क्षेत्रों द्वारा संचालित रही।

परिचालन व्यय में बिक्री की तुलना में धीमी वृद्धि के साथ, 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान परिचालन लाभ में समग्र

**चार्ट IV.18 बिक्री वृद्धि**

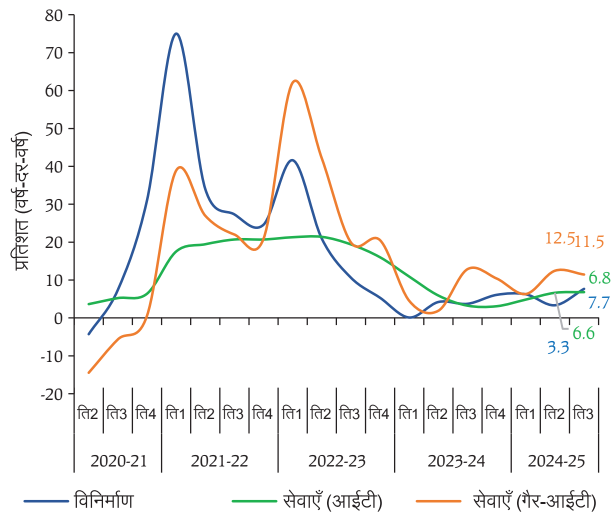


**टिप्पणी:** 2,924 सूचीबद्ध प्राइवेट गैर वित्तीय कंपनियों के परिणामों पर आधारित
**स्रोत:** कैपिटलाइन डाटाबेस; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान

स्तर पर वृद्धि हुई, जिससे परिचालन लाभ मार्जिन में 50 बीपीएस का क्रमिक सुधार हुआ। तिमाही के दौरान सभी प्रमुख क्षेत्रों में मार्जिन में सुधार हुआ, जो उनकी बेहतर बिक्री वृद्धि के अनुरूप था (चार्ट IV.20)।

फरवरी के उत्तरार्ध और मार्च के प्रारंभ में भारतीय इक्विटी बाजारों पर दबाव जारी रहा, जिसका कारण विदेशी संस्थागत

**चार्ट IV.19: विनिर्माण क्षेत्र में प्रमुख उद्योगों की बिक्री वृद्धि**

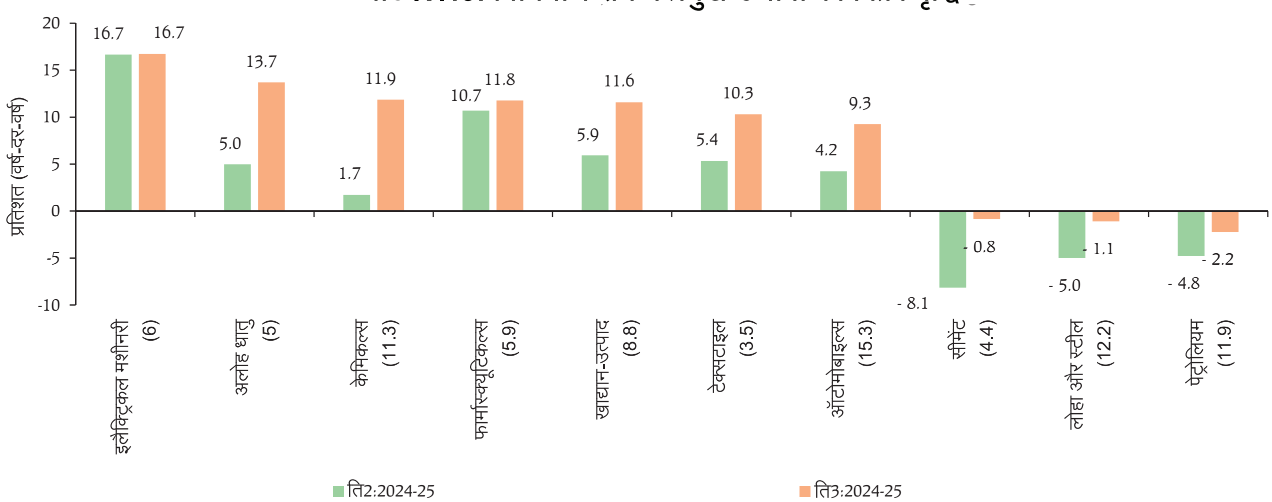


**टिप्पणी:** 1,675 सूचीबद्ध प्राइवेट विनिर्माण के 2024-25 की तीसरी तिमाही के परिणामों पर आधारित; कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उद्योग के बिक्री हिस्से को दर्शाता है।
**स्रोत:** कैपिटलाइन डाटाबेस; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान

**चार्ट IV.20: परिचालन लाभ मार्जिन (बिक्री प्रतिशत)**

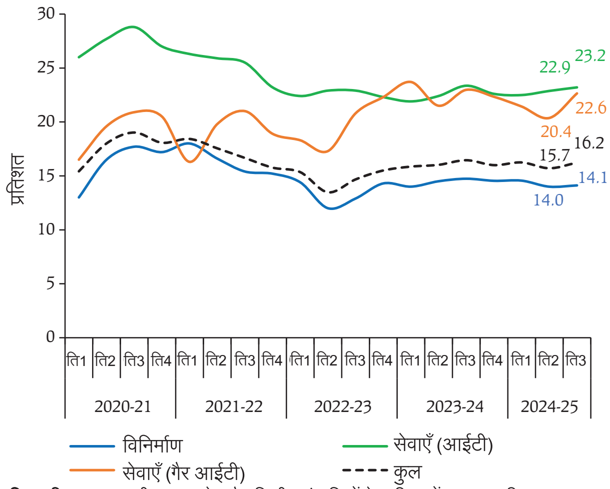


**टिप्पणी:** 2924 सूचीबद्ध प्राइवेट गैर-वित्तीय कंपनियों के परिणामों पर आधारित
**स्रोत:** कैपिटलाइन डाटाबेस; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान

निवेशकों (एफआईआई) द्वारा लगातार बिक्री, अमेरिकी सरकार की टैरिफ नीतियों को लेकर अनिश्चितता और मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच कॉरपोरेट आय को लेकर चिंताएं रहीं। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स 14 फरवरी 2025 से 2.3 प्रतिशत गिरकर 17 मार्च 2025 को 74,170 पर बंद हुआ। हाल के महीनों में इक्विटी बाजार में व्यापक आधार पर करेक्शन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय सूचकांकों में गिरावट आई है (चार्ट IV.21ए)। व्यापक बाजार सूचकांकों में तेज गिरावट हुई है, जो कि हाल की अवधि में उनके घटकों के उच्च अनुपात में 52-सप्ताह के निचले स्तर तक पहुँचने से परिलक्षित होता है और विशेष रूप से, 3 मार्च 2025 को एनएसई 500 सूचकांक के घटक सदस्यों का 31 प्रतिशत, निफ्टी 50 सदस्यों के 22 प्रतिशत के मुकाबले 52-सप्ताह के नए निचले स्तर पर पहुँच गया (चार्ट IV.21बी)।

प्राइम डेटाबेस के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा लगातार बिक्री के कारण दिसंबर 2024 के अंत तक एनएसई-सूचीबद्ध कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी घटकर 17.2 प्रतिशत रह गई है, जो कई वर्षों का निचला स्तर है। इसके विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, जिससे एफआईआई-से-डीआईआई स्वामित्व अनुपात जून 2009 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है (चार्ट IV.22)।[19]

हाल ही में बाजार में हुए सुधार और इक्विटी डेरिवेटिव खंड में विनियामक उपायों के कारण हाल के महीनों में इक्विटी

**चार्ट IV.21: इक्विटी बाजार में करेक्शन**

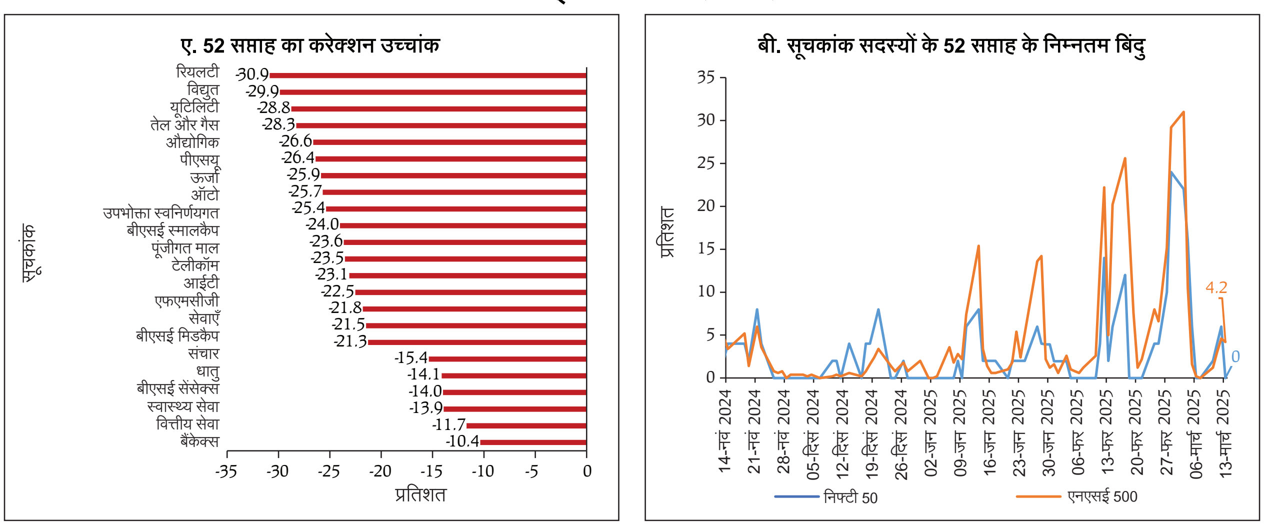


**टिप्पणी:** 13 मार्च, 2025 तक का डाटा लिया गया है। दैनिक क्लोसिंग डाटा के आधार पर गणना की गई है।
**स्रोत:** ब्लूमबर्ग

[19] https://www.business-standard.com/markets/stock-market-news/diis-close-india-inc-ownership-gap-with-foreign-portfolio-investors-125020401430_1.html

**चार्ट IV.22: सभी एनएसई-सूचीबद्ध कंपनियों में एफआईआई-डीआईआई स्वामित्व अनुपात**

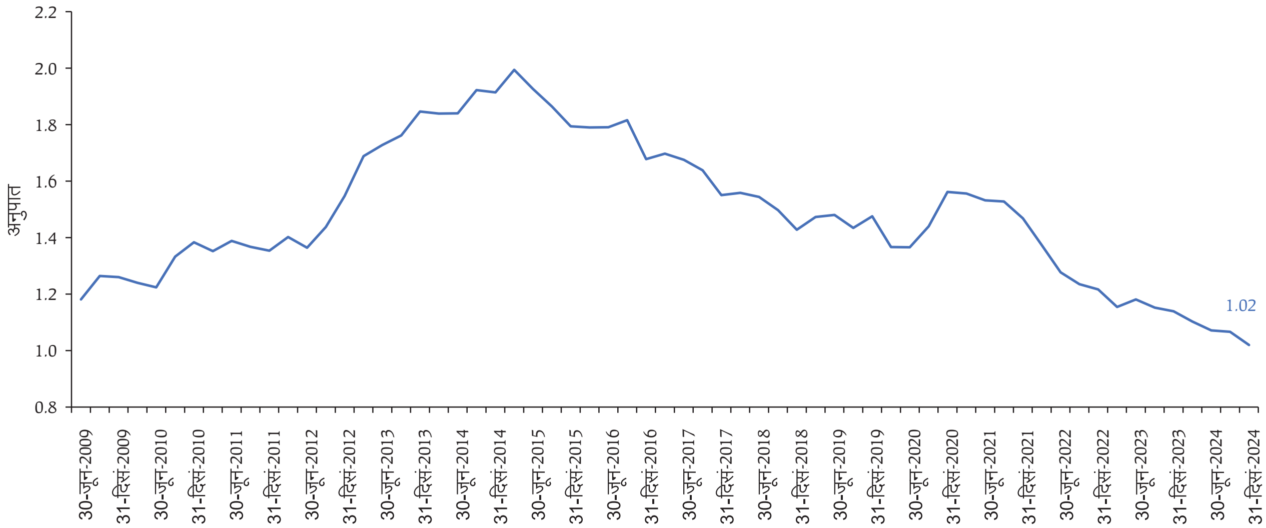


**स्रोत:** प्राइम डाटाबेस

डेरिवेटिव और नकदी खंड दोनों में कारोबार में गिरावट आई है (चार्ट IV.23)।[20]

द्वितीयक बाजार में लोक-रुचि में कमी के चलते जनवरी 2025 में प्राथमिक बाजार में धन जुटाने की गतिविधि भी प्रभावित हुई (चार्ट IV.24)।[21]

**चार्ट IV.23: इक्विटी खंड में गिरता कारोबार**

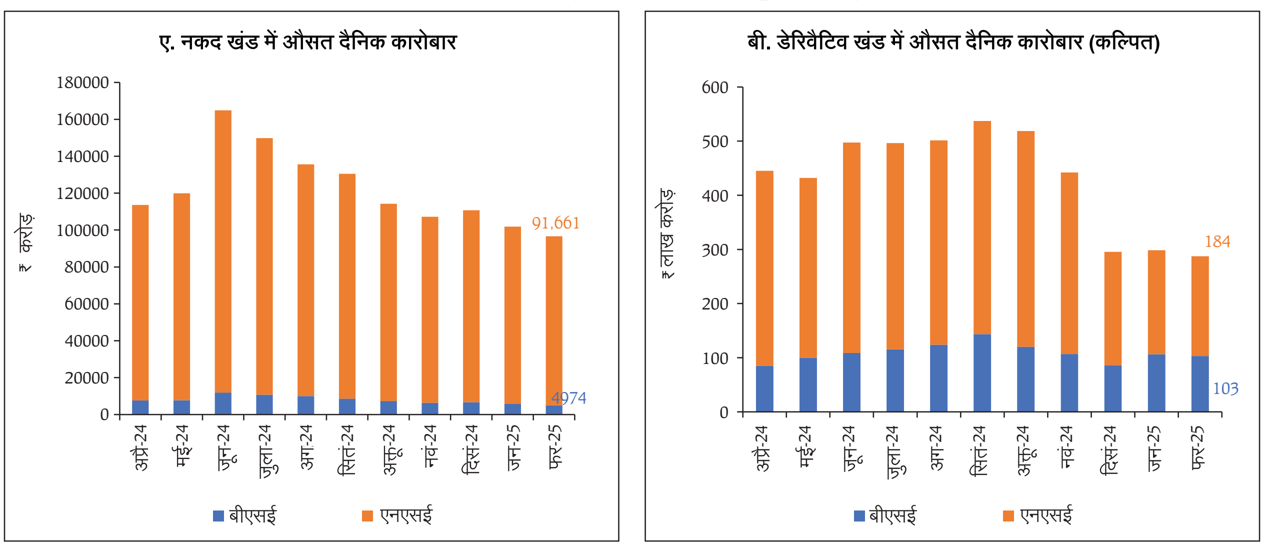


**स्रोत:** सेबी; बीएसई;और एनएसई

[20] https://www.moneycontrol.com/news/business/markets/cash-market-turnover-slips-below-rs1-lakh-crore-in-february-hits-15-month-low-f-o-volume-lowest-since-december-23-12948385.html

[21] https://economictimes.indiatimes.com/markets/ipos/fpos/unwilling-to-bear-a-bearscare-companies-halt-ipo-fair/articleshow/118614369.cms?from=mdr

**चार्ट IV.24: इक्विटी बाजार में संसाधन जुटाना**

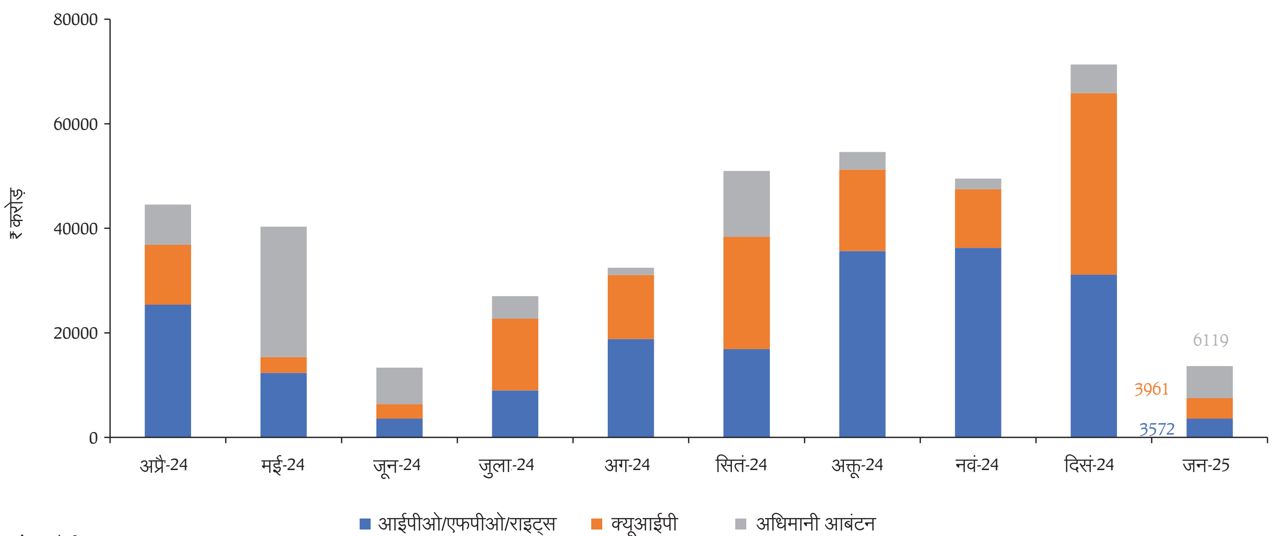


**स्रोत:** सेबी

इक्विटी बाजारों में हाल के सुधार के मद्देनजर, यह उल्लेखनीय है कि खुदरा निवेशकों की 60.8 प्रतिशत इक्विटी परिसंपत्तियां 24 महीने से अधिक समय से रखी गई हैं (चार्ट IV.25)।[22] यह दर्शाता है कि खुदरा निवेशकों ने अपने इक्विटी निवेशों को, विशेष रूप से म्यूचुअल फंड (एमएफ) और व्यवस्थित निवेश योजनाओं (एसआईपी) के माध्यम से, बनाए रखने में दृढ़ता दिखाई है।

घरेलू बचत के वित्तीयकरण को बढ़ाने के लिए तीन हालिया घटनाक्रमों में उल्लेखनीय संभावनाएँ हैं। पहला, माइक्रो एसआईपी योजनाओं[23] की शुरुआत, जो म्यूचुअल फंड उत्पादों को व्यापक

**चार्ट IV.25: म्यूचुअल फंड में धारिताएं**

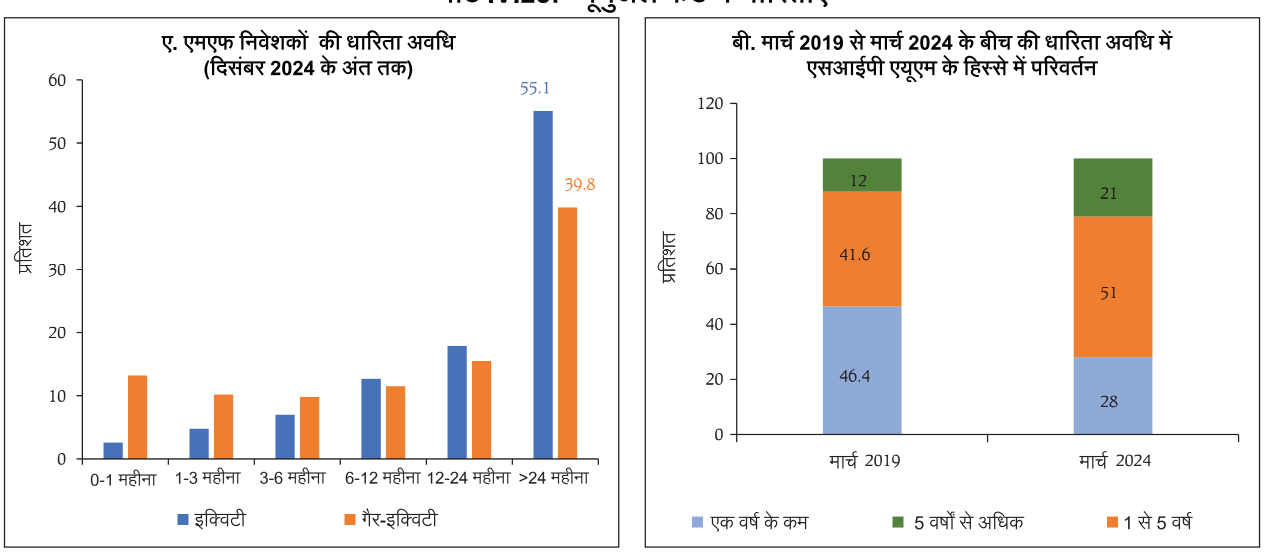


**स्रोत**: एएमएफआई; और क्रिसिल इंटेलिजेंस

[22] https://www.amfiindia.com/Themes/Theme1/downloads/home/FolioandTicketSize.pdf

[23] https://www.financialexpress.com/money/mutual-funds-explainer-building-the-equity-culture-with-micro-sip-3761507/

दर्शकों तक पहुँचाएगी। दूसरा, विशेष निवेश फंडों[24] की शुरुआत, जो निवेशकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने और म्यूचुअल फंडों और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) के बीच एक सेतु का काम करने के लिए बनाए गए हैं। तीसरा, कॉरपोरेट बॉण्ड के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस की स्थापना, जो भारत में कॉरपोरेट बॉण्ड के बारे में जानकारी का एक प्रामाणिक स्रोत प्रदान करेगा।[25]

सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मजबूत बना हुआ है, जो 2024-25 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 12.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर एक वर्ष पहले की इसी अवधि के 60.2 बिलियन यूएस डॉलर से 67.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया(चार्ट IV.26ए)। हालांकि, भारत से अधिक प्रत्यावर्तन और जावक एफडीआई के कारण, निवल एफडीआई 2024-25 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान एक वर्ष पहले के 11.5 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर 1.4 बिलियन यूएस डॉलर रह गया। क्षेत्रवार, विनिर्माण क्षेत्र को इक्विटी प्रवाह का सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त हुआ, उसके बाद वित्तीय सेवाएं, बिजली और अन्य ऊर्जा, और संचार सेवाएं रहीं - जिनका कुल प्रवाह में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान रहा। इस अवधि के दौरान 75 प्रतिशत से अधिक प्रवाह सिंगापुर, मॉरीशस, अमेरिका, यूएई और नीदरलैंड से हुआ।

वैश्विक स्तर पर घोषित ग्रीनफील्ड एफडीआई परियोजनाओं के संदर्भ में, 2024 में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर रहा, जो 2020 में छठे स्थान पर था। 2024 में दुनिया भर में घोषित कुल 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की एफडीआई परियोजनाओं में से, भारत का योगदान लगभग 6 प्रतिशत (100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) था। उभरते क्षेत्र - नवीकरणीय ऊर्जा, संचार, सेमीकंडक्टर और धातु - 2024 के दौरान वैश्विक स्तर पर सबसे आकर्षक एफडीआई क्षेत्र बने रहे (चार्ट IV.26बी)। भारत में, धातु, नवीकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर शीर्ष उद्योग थे, जिनका 2024 में घोषित कुल एफडीआई परियोजनाओं में लगभग 60 प्रतिशत योगदान था।

फरवरी 2025 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह में लगातार बहिर्वाह जारी रहा। फरवरी में 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल एफपीआई बहिर्वाह दर्ज किया गया, जबकि निवल इक्विटी बहिर्वाह 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा (चार्ट IV.27ए)। इसके अलावा, मौद्रिक और राजकोषीय

**चार्ट IV.26 : विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह**

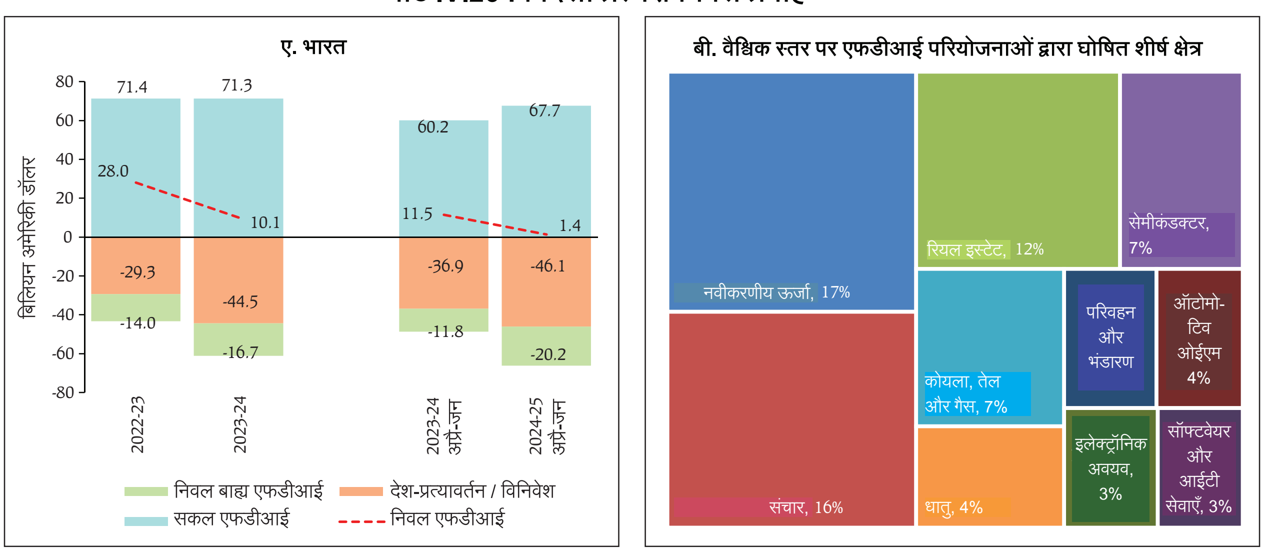


**स्रोत:** आरबीआई; और एफडीआई बाजार

---

[24] https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/feb-2025/regulatory-framework-for-specialized-investment-funds-sif-_92299.html

[25] https://www.sebi.gov.in/media-and-notifications/press-releases/feb-2025/launch-of-bond-central-a-centralised-database-portal-for-corporate-bonds_92306.html

**चार्ट IV.27 : निवल पोर्टफोलियो निवेश**

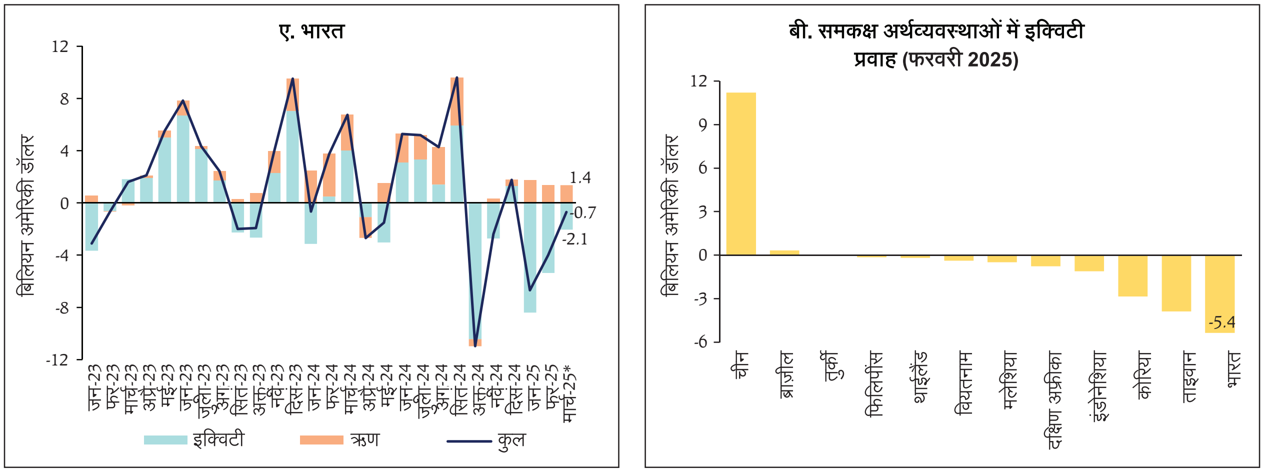


**टिप्पणियाँ :** 1 ऋणों में हाइब्रिड लिखतों के अंतर्गत किए गए निवेश को शामिल किया गया है।
2 *:12 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार

**स्रोत :** नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल); और अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान

प्रोत्साहन के माध्यम से चीनी अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार को लेकर बढ़ती आशावादिता के बीच, इस महीने के दौरान वैश्विक एफपीआई प्रवाह चीनी इक्विटी की ओर उल्लेखनीय रूप से पुनर्निर्देशित हुआ (चार्ट IV.27बी)। भारत में, मार्च 2025 में एफपीआई का तीव्र बहिर्वाह 0.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (17 मार्च तक) के निवल बहिर्वाह के साथ जारी रहा।

2024-25 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान अनिवासी जमा (एनआरडी) में 14.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवल वृद्धि रही, जो एक वर्ष पहले के 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अधिक थी, जिसमें सभी तीन खातों यानी अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते [एनआर(ई)आरए], अनिवासी साधारण (एनआरओ) और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] खातों में अधिक वृद्धि हुई।

अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के दौरान संचयी आधार पर बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) पंजीकरण (47.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और संवितरण (42.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर), पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किए गए संवितरणों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक था। इस अवधि के दौरान मूलधन के पुनर्भुगतान के कारण ईसीबी बहिर्वाह 23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसके परिणामस्वरूप 18.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मजबूत निवल अंतर्वाह हुआ - जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में देखे गए स्तर से दोगुने से भी अधिक है (चार्ट IV.28)।

अप्रैल 2024 - जनवरी 2025 के दौरान कुल पंजीकृत ईसीबी में से लगभग 44 प्रतिशत पूंजीगत व्यय उद्देश्यों के लिए थे (चार्ट IV.29)।

अगस्त 2024 से प्रतिभूतित एक दिवसीय वित्तपोषण दर (एसओएफआर) में निरंतर गिरावट ने ईसीबी की कुल लागत में

**चार्ट IV.28 : बाह्य वाणिज्यिक उधार – पंजीकरण और प्रवाह**

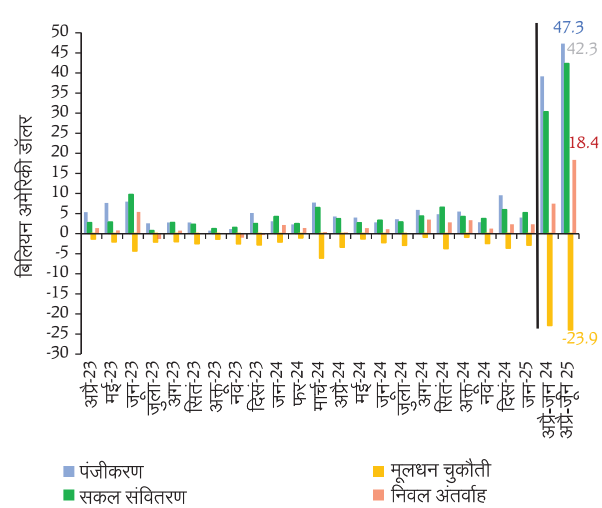


**स्रोत:** फॉर्म ईसीबी, आरबीआई

**चार्ट IV.29: पंजीकृत ईसीबी का अंतिम उपयोग**

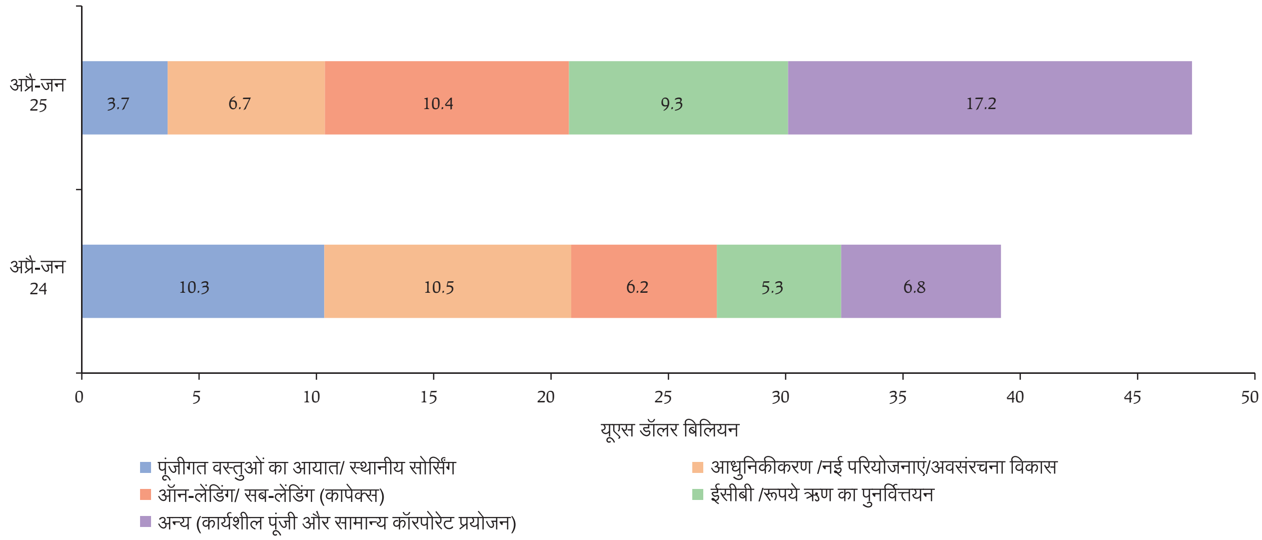


**स्रोत:** फॉर्म ईसीबी, आरबीआई

कमी लाने में योगदान दिया है। जनवरी 2025 में, ईसीबी की कुल लागत में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 129 बीपीएस की गिरावट हुई (चार्ट IV.30)।

फरवरी 2025 के दौरान भारी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का बहिर्वाह के चलते भारतीय रुपये (आईएनआर) में 0.9 प्रतिशत (माह-दर-माह) की गिरावट आई (चार्ट IV.31)। हालाँकि, रुपये के अवमूल्यन की सीमा पिछले महीने की तुलना में कम थी। इसके अलावा, रुपया सबसे कम अस्थिर प्रमुख मुद्राओं में से एक बना रहा।

फरवरी 2025 में 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में भारतीय रुपये में 2.4 प्रतिशत (माह-दर-माह) की गिरावट आई, जिसका कारण नामित प्रभावी शर्तों

**चार्ट IV.30: ईसीबी का समग्र मूल्य**

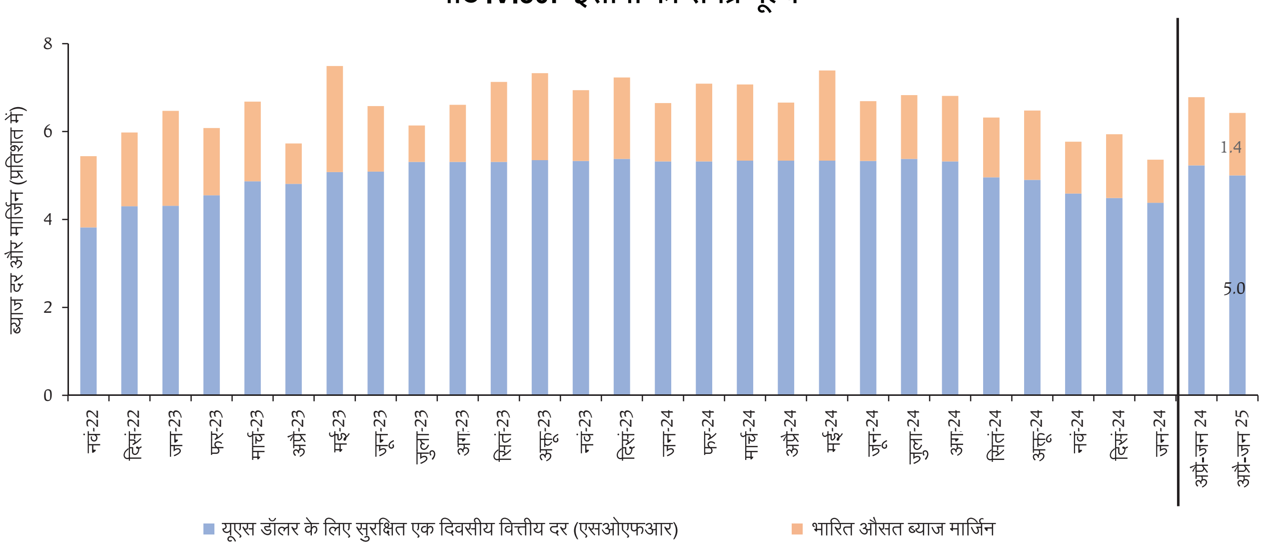


**स्रोत:** फॉर्म ईसीबी; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान

**चार्ट 31: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये और अन्य प्रमुख मुद्राओं का उतार-चढ़ाव (जनवरी 2025 की तुलना में फरवरी 2025)**

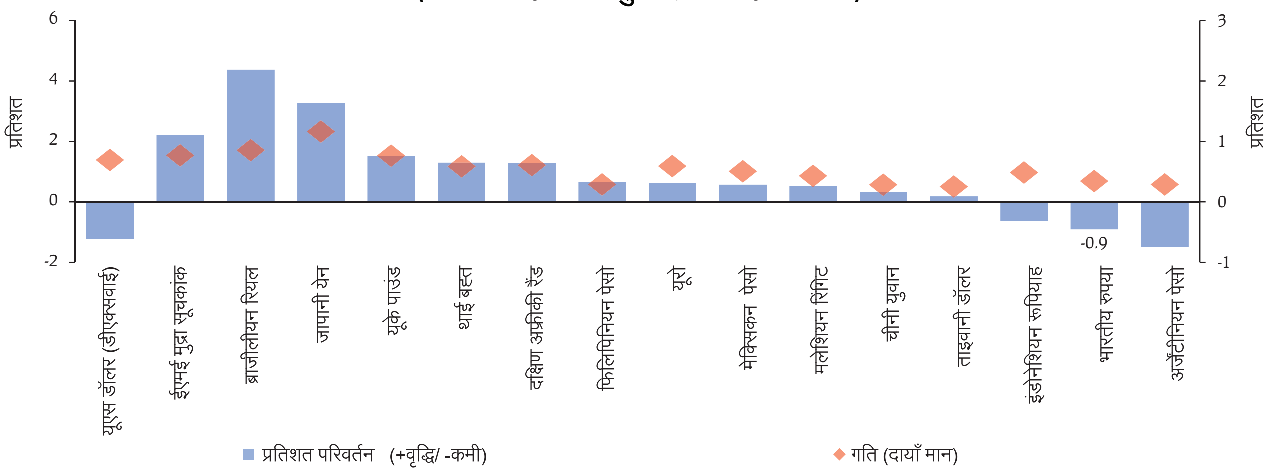


**टिप्पणी:** यूएस डॉलर (डीएक्सवाई) प्रमुख मुद्राओं (जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना, स्विस फ्रैंक) के सामने यूएस डॉलर की उतार-चढ़ाव को मापता है।
**स्रोत:** एफबीआईएल; थॉमसन रॉयटर्स; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

में भारतीय रुपये का मूल्यह्रास और भारत के अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ मुद्रास्फीति अंतर का कम होना है (चार्ट IV.32)।

7 मार्च 2025 तक, भारत के पास 654.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो 11 महीनों से अधिक के आयात और सितंबर 2024 के अंत तक बकाया विदेशी ऋण के 91 प्रतिशत के लिए पर्याप्त है (चार्ट IV.33ए)। 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान शीर्ष भंडार रखने वाली अर्थव्यवस्थाओं के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखी गई, जिसमें 2025 में सुधार के कुछ संकेत हैं (चार्ट IV.33बी)।

### भुगतान प्रणालियाँ

फरवरी 2025 में भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के कारण भारत के

**चार्ट IV.32 : 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में परिवर्तन**

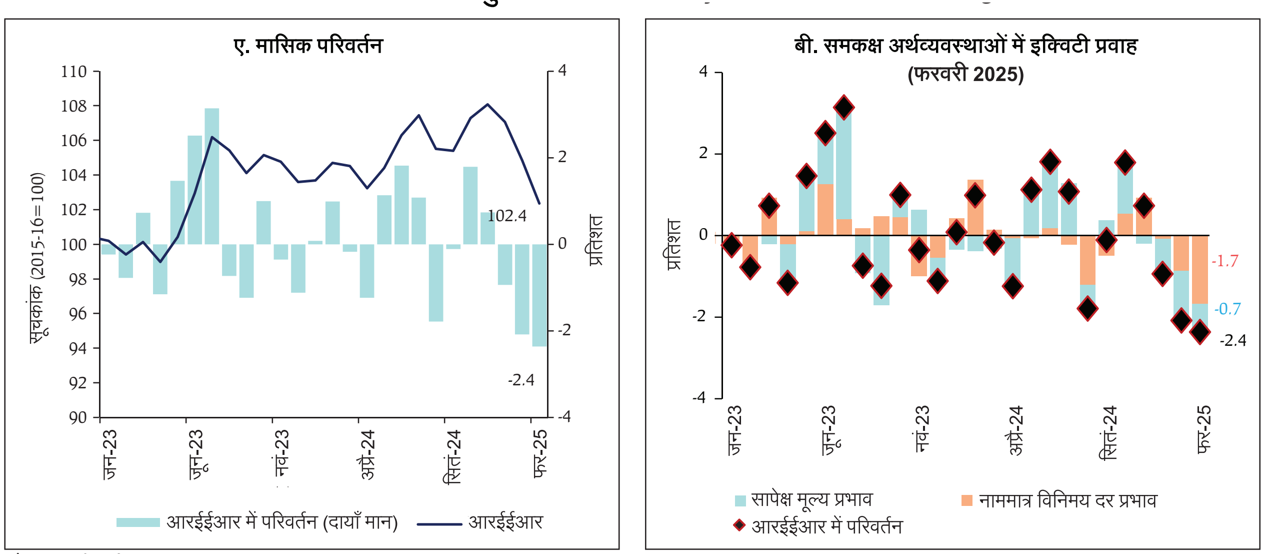


**स्रोत:** आरबीआई

**चार्ट IV.33 : विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ**

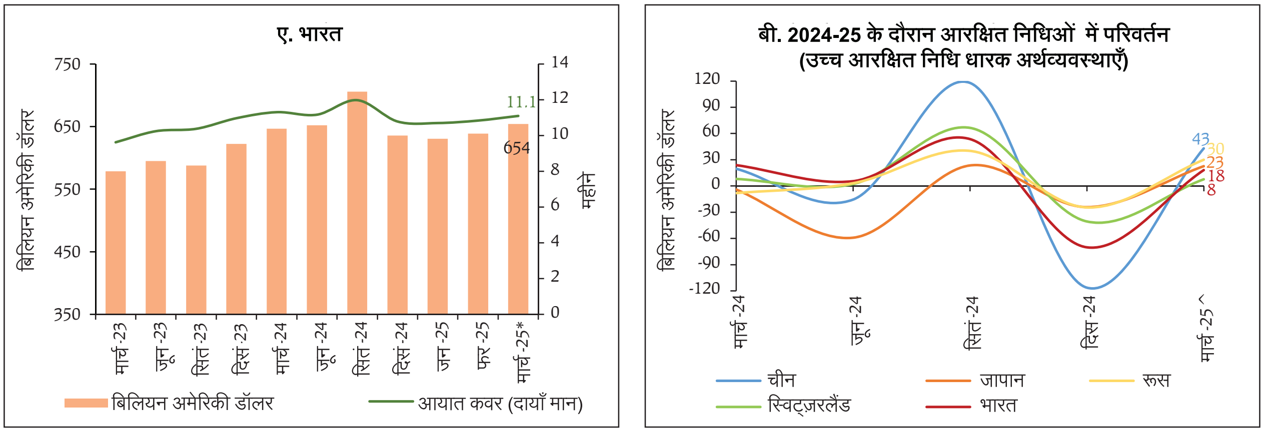


**टिप्पणी:** 1. *: डाटा 7 मार्च का है।
2. दिसंबर 2024 से आयात कवर डाटा भुगतान संतुलन सांख्यिकी के अनुसार सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए वार्षिक माल आयात पर आधारित है।
3. ^: भारत और रूस के लिए डाटा 7 मार्च, 2025, स्विट्ज़रलैंड के लिए जनवरी 2025 की समाप्ति और अन्य देशों के लिए फरवरी 2025 की समाप्ति के अनुसार है।
**स्रोत:** आरबीआई; संबंधित केंद्रीय बैंक; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान

डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार हुआ (सारणी IV.4)। भारत में उद्यमिता और व्यापार विस्तार को बढ़ावा देने में डिजिटल भुगतान की बढ़ती भूमिका पर्सन-टू-मर्चेंट(पी2एम) लेनदेन में वृद्धि से स्पष्ट है, जो फरवरी 2025 में कुल यूपीआई लेनदेन का 62.5 प्रतिशत है, जबकि एक वर्ष पहले यह 60.8 प्रतिशत थी।

डिजिटल वित्त खंड में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) के माध्यम से तेजी से पूरा किया जा रहा है, जैसा कि वित्तपोषित फैक्टरिंग यूनिट्स[26] (एफयू) में तेज वृद्धि से परिलक्षित होता है - जिसने जनवरी 2025 में मात्रा में 78 प्रतिशत और मूल्य (वर्ष-दर-वर्ष) में 68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। टीआरईडीएस पर पंजीकृत एमएसएमई विक्रेताओं[27] की औसत संख्या एक साल पहले के 24,081 से बढ़कर जनवरी 2025 में 41,094 हो गई। यह

**सारणी IV.4 : चुनिन्दा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि**

(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत)

| भुगतान प्रणाली | लेनदेन मात्रा | | | | लेनदेन मात्रा | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जन-24 | जन-25 | फर-24 | फर-25 | जन-24 | जन-25 | फर-24 | फर-25 |
| आरटीजीएस | 13.1 | 16.1 | 18.8 | 2.5 | 17.1 | 19.1 | 21.2 | 10.2 |
| एनईएफटी | 43.4 | 24.5 | 47.3 | 11.0 | 19.8 | 14.3 | 25.1 | 2.0 |
| यूपीआई | 51.8 | 39.3 | 60.6 | 33.1 | 41.7 | 27.5 | 47.9 | 20.2 |
| आईएमपीएस | 7.2 | -12.7 | 19.4 | -24.3 | 18.6 | 7.1 | 21.2 | -0.9 |
| एनएसीएच | 22.8 | 17.2 | 13.1 | 6.8 | 21.5 | 22.5 | 15.6 | 20.0 |
| एनईटीसी | 10.2 | 14.8 | 12.1 | 18.7 | 15.5 | 19.0 | 19.2 | 18.3 |
| बीबीपीएस | 24.6 | 97.4 | 29.8 | 87.3 | 75.4 | 276.4 | 85.8 | 240.6 |

**टिप्पणी**: **आरटीजीएस**: तत्काल सकल निपटान, **एनईएफटी**: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, **यूपीआई**: यूनीफाइड इंटरफेस, **आईएमपीएस**: इमिडियट पेमेंट सर्विस, **एनएसीएच**: नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, **एनईटीसी**: नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, **बीबीपीएस**: भारत बिल पेमेंट सिस्टम
**स्रोत**: आरबीआई

[26] फैक्टरिंग यूनिट (एफयू) एक नाम है जिसका उपयोग टीआरईडीएस में चालान या विनिमय पत्र के लिए किया जाता है। प्रत्येक एफयू, सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों सहित, कॉरपोरेट या अन्य खरीदारों के एक निश्चित दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है।

[27] एमएसएमई विक्रेताओं की औसत संख्या की गणना टीआरईडीएस के अंतर्गत शीर्ष तीन संस्थाओं के साथ पंजीकृत एमएसएमई विक्रेताओं की कुल संख्या को तीन से विभाजित करके की जाती है।

**चार्ट IV.34: उद्यमी प्रयोजनों के लिए इंटरनेट का उपयोग**

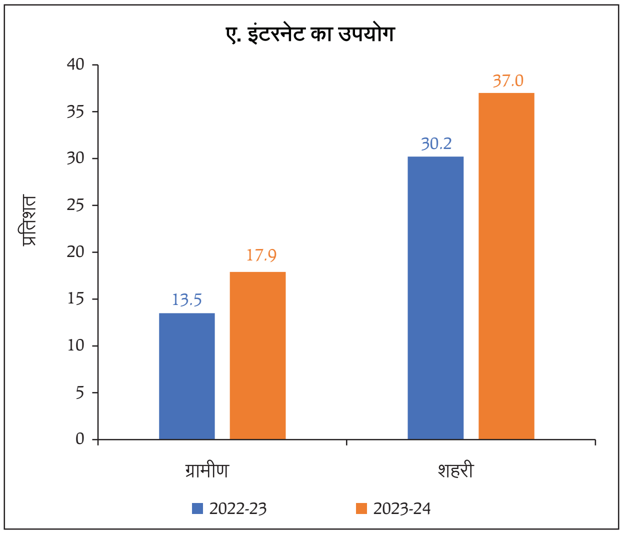


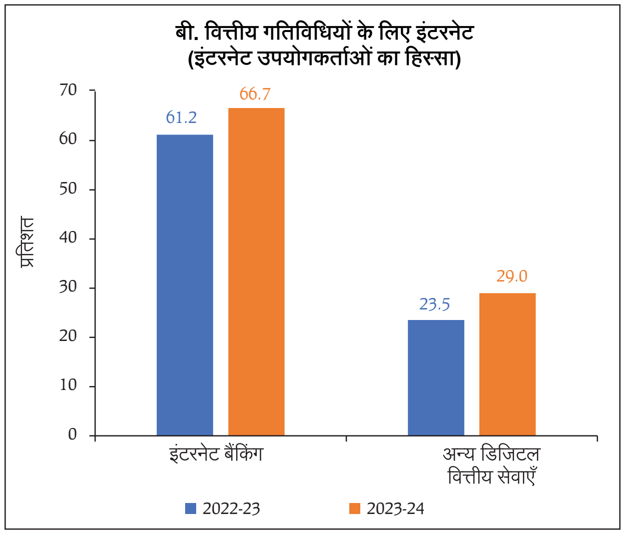


**स्रोत:** असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान

परिवर्तन उद्यमी गतिविधियों के लिए इंटरनेट का उपयोग करने वाले असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के बढ़ते अनुपात में भी परिलक्षित होता है। राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेट अपनाने की दर 2022-23 के 21 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 26.7 प्रतिशत हो गई, जिसमें शहरी उद्यमों में तेज़ी से वृद्धि देखी गई (चार्ट IV.34ए)। इसके अतिरिक्त, वित्तीय गतिविधियों के लिए इंटरनेट का उपयोग करने वाले उद्यमों की हिस्सेदारी में भी वृद्धि हुई है (चार्ट IV.34बी)।

नीतिगत मोर्चे पर, रिज़र्व बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम (एसआरओ-एए) के लिए स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता देने के लिए रूपरेखा जारी की है और उनकी मान्यता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।[28] भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूपीआई लाइट कार्यक्षमता में सुधार के लिए अनुशिष्ट प्रस्तुत किए हैं, जिनमें ट्रांसफर-आउट, बैलेंस समाधान, ऐप पासकोड और उन्नत यूपीआई सीमाएँ शामिल हैं, जो विशेष रूप से ऑफलाइन[29] संव्यवहार[30, 31] के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को और बेहतर बनाती है।

## V. निष्कर्ष

वैश्विक अर्थव्यवस्था की तात्कालिक दिशा बढ़ते व्यापार तनावों, टैरिफ़ से उत्पन्न मुद्रास्फीति के दबावों और उससे जुड़ी वित्तीय बाज़ार की अस्थिरता से प्रभावित हो सकती है। हाल ही में घोषित राजकोषीय प्रोत्साहन से यूरो क्षेत्र में विकास को अल्पकालिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, हालाँकि ऐसी घोषणाओं के बाद प्रतिफल में हुई तेज़ वृद्धि से संकेत मिलता है कि दीर्घकालिक उधारी लागत में हुई वृद्धि से बड़े विस्तार में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। विकास में मंदी के माहौल में माँग में अपेक्षित कमी के अनुरूप, कोमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का आधार बन सकती है। हालाँकि, उपभोक्ता कीमतों पर उच्च टैरिफ़ का प्रभाव मुद्रास्फीति के लिए एक प्रमुख जोखिम बना हुआ

[28] आरबीआई प्रेस विज्ञप्तियाँ, 12 मार्च 2025। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के लिए स्व-विनियामक संस्था(ओं) की मान्यता हेतु आवेदन आमंत्रित।

[29] 'ऑफलाइन' जैसा कि आरबीआई परिपत्र संख्या . RBI/2021-22/146 CO.DPSS. POLC.No.S1264/02-14-003/2021-2022, दिनांक 04 दिसंबर 2024 में परिभाषित किया गया है - 'ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए ढांचा'

[30] एनपीसीआई परिपत्र, 21 फरवरी 2025। यूपीआई लाइट की शुरूआत के लिए अनुशिष्ट।

[31] एनपीसीआई परिपत्र, 27 फरवरी 2025। यूपीआई लाइट सीमाओं में वृद्धि का अनुशिष्ट।

है, जो पहले से ही कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में दृढ़ता के संकेत प्रदर्शित कर रही है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों को विकास में संभावित मंदी के माहौल में नीतिगत प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करते समय ऐसे दबावों को ध्यान में रखना होगा। दूसरी ओर, उभरती अर्थव्यवस्थाएँ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के अपने समकक्षों की तुलना में उच्च वृद्धि दर्ज करने की संभावना रखती हैं, हालाँकि पूँजी बहिर्वाह और संभावित मुद्रा अवमूल्यन प्रमुख जोखिम बने हुए हैं।

घरेलू स्तर पर, समष्टि आर्थिक बुनियादी ढाँचे मजबूत बने हुए हैं, और मजबूत घरेलू माँग, स्थिर निवेश गतिविधि, और चालू नीति-संचालित अवसंरचना विकास के साथ-साथ सरकारी खर्च में वृद्धि से आर्थिक विकास की गति बनी रहेगी। हेडलाइन मुद्रास्फीति अक्टूबर 2024 के 6 प्रतिशत से अधिक से घटकर फरवरी 2025 में 3.6 प्रतिशत हो गई है। मजबूत खरीफ उत्पादन, बेहतर रबी बुआई के साथ-साथ उच्च जलाशय स्तर और सब्जियों की कीमतों में मौसमी सर्दी के चलते सुधार खाद्य मुद्रास्फीति के लिए शुभ संकेत हैं, हालाँकि कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मौसम संबंधी विसंगतियाँ समग्र मुद्रास्फीति परिदृश्य के लिए संभावित रूप से जोखिम बने हुए हैं।

कमजोर होते वैश्विक व्यापार और टैरिफ अनिश्चितता से चुनौतियों का सामना करते हुए, भारत के बाह्य क्षेत्र को आघात-सहनीय सेवा निर्यात से समर्थन मिल रहा है, जो वैश्विक व्यवधानों से कम प्रभावित हैं। भविष्य में, भारत की संरचनात्मक शक्तियाँ—मजबूत राजकोषीय नीतियाँ, एक सुसंतुलित मौद्रिक ढाँचा, और डिजिटल परिवर्तन पहल—दीर्घकालिक सतत आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेंगी।